



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 14, 1974/अग्रहायण 23, 1896

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 14, 1974/AGRAHAYANA 23, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये सार्वजनिक आदेश और अधिसूचनाएँ

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities
(other than the Administrations of Union Territories)

विविध, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1974

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 5th December, 1974

का० घा० 3261.—एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नांकित उपक्रमों के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरणों के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है —

1. मै० जे० स्टोन एण्ड कम्पनी (इन्डिया) प्रा० लि०,
(पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं० 19/1970, दिनांक 20/10/70)
2. म० मौलिन्य आफ इन्डिया लि०
(पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं० 724/71, दिनांक 6-5-71)
3. मै० कैम्फूर एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स लि०
(पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं० 293/70, दिनांक 24-10-70)
4. मै० इन्सुलैटर्स एम० इन्सुलैटर्स आफ इन्डिया लि०
(पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं० 704/71, दिनांक 22-3-71)
5. वि सरसिल्क लि०
(पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं० 417/70, दिनांक 30-10-70)
6. मै० त्रावणकोर कैमिकल्स एण्ड मैनुफैक्चरिंग कं० लि०
(पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं० 475/70 दिनांक 11-11-70)

[संख्या 22/30/72-एम० 2]

डी० पी० उप्पल, अवर सचिव

S.O. 3261.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of the following undertakings under the said Act:—

1. M/s. J. Stone & Co. (India) Private Ltd.
(Certificate of registration No. 19/1970, dated 20-10-1970).
2. M/s. Molins of India Ltd.
(Certificate of registration No. 724/71, dated 6-5-1971).
3. M/s. Camphor & Allied Products Ltd.
(Certificate of registration No. 293/70, dated 24-10-1970).
4. M/s. W. S. Insulators of India Ltd.
(Certificate of registration No. 704/71, dated 22-3-1971).
5. M/s. Sirsilk Ltd.
(Certificate of registration No. 417/70, dated 30-10-1970).
6. M/s. Travancore Chemical & Manufacturing Co. Ltd.
(Certificate of registration No. 475/70, dated 11-11-1970).

[F. No. 22/30/72-M. II]

V. P. UPPAI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बोसा विभाग)

(आय-कर)

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1974

क्र० आ० 3262.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ की उपधारा (2) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, श्री धनयुथपानी स्वामी मंदिर पलानी मयुराई जिला, तमिल नाडु को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए तमिल नाडु राज्य में सर्वत्र विख्यात लोक-पूजा का स्थान अधिसूचित करती है।

[सं० 764 (फा० सं० 176/53/74-आई टी (ए आई)]

वी०बी० श्रीनिवासन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue & Insurance)

(Income-Tax)

New Delhi, the 26th October, 1974

S.O. 3262.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies Sri Dhandayuthapani Swami Temple, Palani, Madurai Dist., Tamil Nadu to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu for the purpose of the said section.

[No. 764 (F. No. 176/53/74-IT(AI))
V. B. SRINIVASAN, Under Secy.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1974

क्र० आ० 3263.—रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में नवम्बर, 1974 की 22 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा दृष्टि विभाग

वैयताएं	रुपये	रुपये	प्रास्तियां	रुपये	रुपये
1	2	3	4	5	6
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	40,93,28,000		सोने का सिक्का और मुद्रियां :—		
संचालन में नोट	6063,56,52,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,52,68,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	..	
			विदेशी प्रतिभूतियाँ	141,73,97,000	
जारी किये गये कुल नोट		6104,49,80,000	जोड़		324,26,65,000
			रुपये का सिक्का		14,88,85,00
			भारत सरकार की रुपया प्रति-		
			भूतियाँ		5765,34,30,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे		
			वाणिज्य-पत्र		..
कुल वैयताएं		6104,49,80,000	कुल प्रास्तियाँ		6104,49,80,000

तारीख : 27 नवम्बर, 1974

वी० बी० जारी, उप गवर्नर

22 नवम्बर, 1974 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

वैयताएं	रुपये	प्रास्तियाँ	रुपये
(1)	(2)	(3)	(4)
मुक्तता पूंजी	5,00,00,000	नोट	40,93,28,000
भारक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	3,61,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण :		छोटा सिक्का	3,44,000
(बीर्षकालीन प्रवर्तन) निधि	284,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल :	
राष्ट्रीय कृषि ऋण :		(क) देशी	119,48,72,000
(स्थिरीकरण) निधि	95,00,00,000	(ख) विदेशी	..
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण :		(ग) सरकारी खजाना बिल	659,32,18,000
(बीर्षकालीन प्रवर्तन) निधि	265,00,00,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	611,23,15,000
अमाराशियाई :—		निवेश **	337,69,97,000
(क) सरकारी—		ऋण और अग्रिम :—	
(i) केंद्रीय सरकार	53,69,44,000	(i) केंद्रीय सरकार को	..
(ii) राज्य सरकारें	8,09,80,000	(ii) राज्य सरकारों को	88,22,78,000

देयताएँ	रुपये	प्राप्तियाँ	रुपये
(1)	(2)	(3)	(4)
(ख) बैंक—		ऋण और अग्रिम—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	594,79,96,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ×	78,33,50,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	13,96,30,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को × ×	306,31,65,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,58,13,000	(iii) दूसरों को	9,25,64,000
(iv) अन्य बैंक	44,46,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश—	
		(क) ऋण और अग्रिम—	
		(i) राज्य सरकारों को	67,81,59,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	14,66,13,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को
		(iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को	63,50,00,000
(ग) अन्य	542,28,94,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिपेंडरो से निवेश राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	11,16,98,000
देय जिल	148,44,63,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	47,54,82,000
अन्य देयताएँ	654,41,65,000	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण अग्रिम और निवेश—	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	235,98,62,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/ डिपेंडरो से निवेश
		अन्य प्राप्तियाँ	125,17,25 000
रुपये	2816,73,31,000	रुपये	2816,73,31,000

* नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

** राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

† राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं; परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

× रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 26,53,00,000/- रुपये शामिल हैं।

× × राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

RESERVE BANK OF INDIA

New Delhi, the 30th November, 1974

S. O. 3263.—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, for the week ended the 22nd day of November, 1974

Issue Department

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Gold Coin and Bullion :—		
Notes held in the Banking Department	40,93,28,000		(a) Held in India	182,52,68,000	
Notes in circulation	6063,56,52,000		(b) Held outside India	..	
Total Notes issued		6104,49,80,000	Foreign Securities	141,73,97,000	
			TOTAL		324,26,65,000
			Rupee Coin		14,88,85,000
			Government of India Rupee Securities		5765,34,30,000
			Internal Bills of Exchange and other Commercial paper		..
Total Liabilities		6104,49,80,000	Total Assets		6104,49,80,000

Dated the 27th day of November, 1974.

S. JAGANTHAN, Governor

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 22nd November, 1974

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	40,93,28,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Rupee Coin	3,61,000
		Small Coin	3,44,000
		Bills Purchased and Discounted :—	
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	284,00,00,000	(a) Internal	119,48,72,000
		(b) External	..
		(c) Government Treasury Bills	659,32,18,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	95,00,00,000	Balances Held Abroad*	611,23,15,000
		Investments**	337,69,97,000
		Loans and Advances to :—	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	265,00,00,000	(i) Central Government	
		(ii) State Governments@	88,22,78,000
Deposits :—		Loans and Advances to :—	
(a) Government		(i) Scheduled Commercial Banks†	78,33,50,000
(i) Central Government	53,69,44,000	(ii) State Co-operative Banks††	306,31,65,000
(ii) State Governments	8,09,80,000	(ii) Others	9,25,64,000
		Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
(b) Banks		(a) Loans and Advances to :—	
(i) Scheduled Commercial Banks	594,79,96,000	(i) State Governments	67,81,59,000
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	13,96,30,000	(ii) State-Cooperative Banks	14,66,13,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,58,13,000	(iii) Central Land Mortgage Banks	..
(iv) Other Banks	44,46,000	(iv) Agricultural Refinance Corporation	63,50,00,000

(c) Others	542,28,94,000	(b) Investment in Central Land Mortgage Bank	11,16,98,000
Bills Payable	148,44,63,000	Debentures Loans and Advances from	
Other Liabilities	654,41,65,000	National Agricultural Credit (Stabilisation)	
		Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative	
		Banks	47,54,82,000
		Loans, Advances and Investments from National	
		Industrial Credit (Long Term Operations)	
		Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development	235,98,62,000
		Bank	
		(b) Investment in bonds/debentures issued by	
		the Development Bank	..
		Other Assets	125,17,25,000
	Rupees		Rupees
	2816,73,31,000		2816,73,31,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

⑦Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

†Includes Rs. 26,53,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

††Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated, the 27th day of November, 1974.

S. JAGANNATHAN, Governor

क्रा० प्रा० 3264.—रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में नवम्बर, 1974 की 29 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा नई दिल्ली, 6 दिसंबर, 1974

दणू विभाग

वेयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में			सोने का सिक्का और बुलियन :		
रखे हुए नोट	35,30,61,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,52,68,000	
संचालन में नोट	5974,71,72,000		(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	..	
			विदेशी प्रतिभूतियां	141,73,97,000	
आरो किये गये					
कुल नोट		6010,02,33,000			
			जोड़		324,26,65,000
			रुपए का सिक्का		15,41,61,000
			भारत सरकार की रुपया		
			प्रतिभूतियां		5670,34,07,000
			देशी विनिमय बिल और		
			दूसरे वाणिज्य-पत्र		..
कुल वेयताएं		6010,02,33,000	कुल आस्तियां		6010,02,33,000

एस० जगन्नाथन, गवर्नर

तारीख 4 दिसंबर 1974

29 नवम्बर 1974 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	प्रास्तियां	रुपये
शुक्ता पूंजी	5,00,00,000	नोट	35,30,61,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	5,35,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	284,00,00,000	छोटा सिक्का	3,58,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	95,00,00,000	अरोदे और भुनाये गये बिल (क) बैसी	126,56,42,000
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	265,00,00,000	(ख) विदेशी	..
जमा राशियां —		(ग) सरकारी खजाना बिल	589,03,10,000
(क) सरकारी		विदेशों से रखा हुआ बकाया *	594,58,82,000
(i) केन्द्रीय सरकार	59,18,69,000	निवेश**	432,82,49,000
(ii) राज्य सरकारें	8,22,65,000	ऋण और अग्रिम —	
(ख) बैंक		(i) केन्द्रीय सरकार को	..
(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	575,92,86,000	(ii) राज्य सरकारों को (१)	73,32,09,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	16,09,94,000	ऋण और अग्रिम —	
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	156,12,000	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को	51,15,00,000
(iv) अन्य बैंक	1,36,98,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को††	308,37,30,000
(ग) अन्य	536,27,09,000	(iii) दूसरों को	10,53,14,000
देय बिल	146,31,72,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से	
अन्य देयताएं	665,32,07,000	ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) ऋण और अग्रिम —	
		(i) राज्य सरकारों को	67,81,48,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	14,57,07,000
		(iii) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों को	..
		(iv) कृषि पुनर्वित्त नियम को	63,50,00,000
		(ख) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों के डिबेचरों में निवेश	11,16,98,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और	
		अग्रिम	
		राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	47,51,81,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से	
		ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	238,95,12,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किए गए ब्राह्मो/डिबे- चरों में निवेश	..
		अन्य प्रास्तियां	143,97,76,000
रुपये	2809,28,12,000	रुपये	2809,28,12,000

*नकदी, आबधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

††राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रवर्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को किये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

† रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(1)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीमांसी बिलों पर अग्रिम किये गये 11,80,00,000 रुपये शामिल हैं।

††राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रवर्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

मुस० जगन्नाथन, गवर्नर

[स. फा. 10(1)/74-70प्रो०-1]

ब. व. मीरबन्दाजी, प्रवर सचिव

RESERVE BANK OF INDIA

S.O. 3264.—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, for the week ended the 29th day of November, 1974

New Delhi, the 6th December, 1974

(Issue Department)

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	35,30,61,000		Gold Coin and Bullion :—		
Notes in circulation	5974,71,72,000		(a) Held in India	182,52,68,000	
			(b) Held outside India	..	
Total Notes issued		6010,02,33,000	Foreign Securities	141,73,97,000	
			Total		324,26,65,000
			Rupee Coin		15,41,61,000
			Government of India		
			Rupee Securities		5670,34,07,000
			Internal Bills of Exchange and other Commercial paper		..
Total Liabilities	6010,02,33,000		Total Assets		6010,02,33,000

Dated the 4th day of December, 1974.

S. JAGANNATHAN,
Governor.

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 29th November, 1974

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	35,30,61,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Rupee Coin	5,35,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	284,00,00,000	Small Coin	3,58,000
		Bills Purchased and Discounted :—	
		(a) Internal	126,56,42,000
		(b) External	..
		(c) Government Treasury Bills	589,03,10,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	95,00,00,000	Balances Held Abroad*	594,58,82,000
		Investments**	432,82,49,000
		Loans and Advances to :—	
		(i) Central Government	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	265,00,00,000	(ii) State Governments@	73,32,09,000
Deposits :—		Loans and Advances to :—	
(a) Government		(i) Scheduled Commercial Banks†	51,15,00,000
(i) Central Government	59,18,69,000	(ii) State Co-operative Banks††	308,37,30,000
(ii) State Governments	8,22,65,000	(iii) Others	10,53,14,000
		Loans Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
(b) Banks		(a) Loans and Advances to :—	
(i) Scheduled Commercial Banks	575,92,86,000	(i) State Governments	67,81,48,000
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	16,09,94,000	(ii) State Co-operative Banks	14,57,07,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,56,12,000	(iii) Central Land Mortgage Banks	..
(iv) Other Banks	1,36,98,000	(iv) Agricultural Refinance Corporation	63,50,00,000
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	11,16,98,000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	47,51,81,000
		Loans Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	

(c) Others	536,27,09,000	(a) Loans and Advances to the Development Bank	238,95,12,000
Bills Payable	146,31,72,000	(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
Other Liabilities	665,32,07,000	Other Assets	143,97,76,000
	Rupees 2809,28,12,000		RUPEES 2809,28,12,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

*Includes Rs. 11,80,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

++Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund. Dated the 4th day of December 1974.

[No. F. 10(1)/74B.O.1]

S. JAGANATHAN, Governor.

C.W. MIRCHANDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1974

का० आ० 3265.—बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (2) के उपबन्ध नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक लि०, कलकत्ता पर 5 नवम्बर, 1975 तक, उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि वे उक्त बैंक द्वारा कलकत्ता स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लि० के अंशों की धारकता से सम्बन्ध है।

[सं० 15(2) बी० ओ० 3-74]

से० भा० उपायनकर, अवर सचिव

New Delhi, the 27th November, 1974

S.O. 3265.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act shall not apply to the National & Grindlays Bank Ltd., Calcutta, till the 5th November, 1975 in so far as they relate to its holdings in the shares of Calcutta Steam Navigation Company Ltd.

[No. 15(2)-B.O. III/74]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1974

का०आ० 3266.—जमा बीमा निगम अधिनियम 1961 (1961 का 47) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से परामर्श के पश्चात् एतद्द्वारा जमा बीमा निगम की प्राधिकृत पूंजी को 1 जनवरी, 1975 से 1.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.00 करोड़ रुपये करती है।

[सं० एफ० 6/8/74-बी० ओ०-1]

ड० ज० मुकेशकर, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1974

S.O. 3266.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961 (47 of 1961), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby increases the authorised capital of the Deposit Insurance Corporation from Rs. 1.50 crores to Rs. 2.00 crores with effect from the 1st January, 1975.

[No. F. 6/8/74-BO. I]

D. M. SUKTHANKAR, Director

आदेश

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1974

का० आ० 3267.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 53) की धारा 45 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री वर्द्धमान कोम्रापरेटिव बैंक लिमिटेड, के संबंध में केन्द्रीय सरकार वित्त मंत्रालय, (बैंकिंग विभाग) के 6 दिसम्बर, 1974 के आदेश मोघन स्पेगन आदेश संख्या एफ० 8/8/74-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में अंक, अक्षर और शब्द "7 दिसम्बर, 1974" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "7 फरवरी, 1975" लिखे जायेंगे।

[सं० एफ० 8(8)/74-ए० सी०]

के० भवानी, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th December, 1974

S.O. 3267.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of Moratorium of the Government of India in the Ministry of Finance Department

of Banking) No. F. 8/8/74-AC, dated the 6th September, '74 in respect of the Shree Vardhaman Co-operative Bank Ltd., namely :—

In the said Order, for the figures, letters and word "7th December, 1974", the figures, letters and word "7th February, 1975" shall be substituted.

[No. F. 8(8)/74-AC]

K. BAVANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1974

क्र० प्रा० 3268.—औद्योगिक बिन निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) के खण्ड 21 के उपखण्ड (2) के अनुसरण में, भारतीय औद्योगिक बिन निगम के निदेशक मण्डल की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार एतद्-

द्वारा उक्त निगम द्वारा जनवरी, 1975 में जारी किये जाने वाले और 1 जनवरी, 1976 को परिपक्व होने वाले बाण्डों पर देय व्याज की दर 9% (नौ प्रतिशत) प्रतिवर्ष निर्धारित करती है।

[सं० 2 (49)आई०एफ० 1/74]

म कु० वेकटाचलम, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 5th December, 1974

S.O. 3268.—In pursuance of sub-section (2) of Section 21 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948), the Central Government, on the recommendations of the Board of Directors of the Industrial Finance Corporation of India, hereby fixes 9 per cent (Nine per cent) per annum as the rate of interest payable on the bonds to be issued by the said Corporation in January, 1975 and maturing on the 1st January, 1976.

[No. 2(49)IF. I/74]

M. K. VENKATACHALAM, Joint Secy.

आयकर आयुक्त कार्यालय, उड़िसा

भुवनेश्वर, 20 जुलाई, 1974

आय-कर

क्र० प्रा० 3269.—जुक्ति आयकर अधिनियम 1961 की धारा 287 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के मतानुसार जनहित को ध्यान में रखते हुए, करदाताओं का नाम जितकी आय व्यक्ति हिन्दू अविभाजित परिवार के हैगियत में एक लाख से अधिक पर निर्धारण हुआ है एवं सभी फर्म व्यक्तियों की संस्था, कम्पनी जितका आय निर्धारण 1973-74 के वित्त वर्ष में 10 लाख से अधिक पर हुआ है, आयकर आयुक्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिये नामों का निम्नलिखित रूप में प्रकाशन करते हैं।

क्र० सं०	करदाताओं का नाम एवं पता	हैगियत	कर निर्धारण वर्ष	आय विवरण का अंक निर्धारित आय	कर दाताओं द्वारा कर देन की राशि	करदाता द्वारा कर भुगतान
1	2	3	4	5	6	7
1.	महावीर प्रसाद अग्रवाला प्रोप्राइटर—सिकिरिया एंड कम्पनी मालगोशम, कटक।	व्यक्ति	1971-72	रु० 8,403	रु० 1,50,000	रु० 1,46,716
2.	सिताराम अग्रवाला, बौध	हिन्दू अविभाजित परिवार	1973-74	रु० 1,58,174	रु० 1,62,520	रु० 1,17,319

[संख्या रिकवरी V-5/74-75]

मा० एम० इन्क्यू० ए० खान

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX, ORISSA

Bhubaneswar, the 20th July, 1974

Income-Tax

S. O. 3269.—Whereas in pursuance of Section 287 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government of the opinion that it is expedient in the public interest to publish the names of Individuals and Hindu Undivided Families assessed on an income of more than Rupees one lakh and names of all Firms, Association of persons and Companies assessed on an income of more than rupees Ten Lakhs during the Financial year 1973-74, the Commissioner of Income-tax, Orissa, Bhubaneswar being authorised this behalf publishes such names as below:-

Sl. No.	Names and address of the assessee	Status	Asstt. year	Figures of income returned	Income assessed	Tax Payable by the assessee	Tax paid by the assessee
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mahavir Prasad Agarwalla, Prop. :- Sikiria & Co., Malgo-down, Cuttack.	Individual	1971-72	Rs. 8,403	Rs. 1,50,000	Rs. 1,46,716	Nil
2.	Sitaram Agarwalla, Boudh	H.U.F.	1973-74	Rs. 1,58,174	Rs. 1,62,520	Rs. 1,17,319	Rs. 1,17,319

[No. Recy, V-5/74-75]

M. W. A. KHAN, Commissioner

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1974

क्र० आ० 3270.—चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 41 के साथ पठित धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 45 के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य शक्तियों का, जहाँ तक उनका सम्बन्ध चाय व्यर्थ (नियंत्रण) आदेश, 1959 के उपबन्धों के उल्लंघन पर अभियोजन मंजूर करने से है, प्रयोग चाय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा भी किया जा सकता है लेकिन शर्त यह होगी कि किसी अभियोजन के बारे में मंजूरी देने से पूर्व वह अपने समक्ष उपलब्ध मामलों के आधार पर अपना यह समाधान कर लेगा कि ऐसे अभियोजन के लिए प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है।

राष्ट्रपति के नाम में आदेश।

[सं० जे-13011(1)/74-प्लांट (ए)।

बी० पी० माथुर, उप-सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 5th December, 1974

S.O. 3270.—In exercise of the powers conferred by section 47, read with section 41, of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under section 45 of the said Act, in so far as they relate to sanctioning prosecution for the contravention of the provisions of the Tea Waste (Control) Order, 1959, may also be exercised by the Chairman of the Tea Board, subject to the condition that before sanctioning any prosecution, he shall, on the basis of the material before him, satisfy himself that prima facie a case exists for such prosecution.

By order and in the name of the President.

[No. J. 13011(1)/74-Plant(A)]

B. P. MATHUR, Dy. Secy.

उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

हैदराबाद, 13 सितम्बर, 1974

क्र० आ० 3271.—सर्वश्री माइसोपैक एसोसिएट्स, नं० 86, नेताजी रोड, कुप्पम, चित्तूर जिला को अप्रैल-मार्च 1973 अवधि के लिए नीति के अनुसार मसाले मुद्रा क्षेत्र में (1) स्वीकृत प्राकृतिक सुगंधित तेल की मर्चा (2) अप्रैल-मार्च 1973 के लिए नीति के परिशिष्ट के अनुसार स्वीकृत एरोमेटिक रसायनों की मर्चा (3) रेजिनायड्स (4) नखला एवं (5) 1000 रुपये तक मिन्थेटिक सुगंधित तेल आयात के लिए 5000 रुपये का एक आयात लाइसेंस सं० पी/एस/1738639/सी/एसएम एक्स/46/डब्ल्यू/33-34 दिनांक 8-2-1973 स्वीकृत किया गया था।

उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुविधि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति के लिए उस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस बिल्कुल उपयोग किए बिना ही खो गया है।

अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूँ कि लाइसेंस का मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई है और निवेश देना हूँ कि आवेदक को उक्त लाइसेंस की अनुविधि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति जारी की जानी चाहिए। लाइसेंस की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति एतद्वारा रद्द की जाती है।

[फा० सं० 157/एमएसएस आई/एन पी/एसएम० 72/हैद]

(Office of the Deputy Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

Hyderabad, the 7th September, 1974

S.O. 3271.—M/s. Mysopack Associates, No. 86, Netaji Road, Kappam, Chittoor Distt. were granted an import licence No. P/S/1/38639/C/XX/46/W/33-34 dt. 8-2-1973 for Rs. 5000 for the items (1) Permissible items of Natural Essential Oils as per A.M. 73 Policy (2) Permissible items of Aromatic Chemicals as per Appendix 28 to A.M. 73 policy (3) Resinoids (4) Nakhla and (5) Synthetic Essential Oils upto Rs. 1000 for import from General Currency Area.

They have applied for a duplicate copy of the Exchange Control Purposes copy of the licence on the ground that the Original licence has been lost without having been utilised at all.

In support of their contention they have filed an affidavit. I am satisfied that the Original Exchange Control purposes copy of the licence is lost and direct, that a duplicate Exchange Control Purposes Copy of licence should be issued to the applicant. The Original Exchange Control Purposes Copy of the licence is hereby cancelled.

[File No. M. 157/SSJ/NP/A.M. 72/Hyd.]

हैदराबाद, 4 अक्तूबर, 1974

क्र० आ० 3272.—सर्वश्री एम० ए० एंड कंपनी नं० 10-5-252 नई बस्ती अहमद नगर, हैदराबाद को सामान्य मुद्रा क्षेत्र में (1) 2500 रुपये तक सरणीबद्ध एवं निरोध से भिन्न स्वीकृत किस्म के प्राकृतिक सुगंधित तेल मर्चों, एवं (2) 1000 रुपये तक थिमोल के आयात के लिए 3500 रुपये (तीन हजार पांच सौ रुपये मात्र) के लिए सर्वश्री शक्ति इन्डस्ट्रीज, हैदराबाद के नाम में प्राधिकार पत्र के साथ एक आयात लाइसेंस सं० पी/एस/1743-130/सी/एसएस एक्स/डब्ल्यू/37-38 दिनांक 20-2-74 स्वीकृत किया गया था।

उन्होंने प्राधिकार पत्र के साथ लाइसेंस की अनुविधि सीमासूक्त प्रयोजन प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि प्राधिकार पत्र के साथ मूल लाइसेंस बिल्कुल उपयोग किए बिना ही खो गया है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूँ कि प्राधिकार पत्र के साथ लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है और निदेश देता हूँ कि आवेदक को प्राधिकार पत्र के साथ लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रति जारी की जानी चाहिए। लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति एतद्वारा रद्द की जाती है।

[फा० संख्या एम-116/एम एस आई/एन पी/ए एम/74/002999/हैद०]

Hyderabad, the 4th October, 1974

S.O. 3272.—M/s. M.A. and Company, No. 10-5-252, New Basti, Ahmed Nagar, Hyderabad-28, were granted an import licence No. P/S/1743130/C/XX/50/W/37-38 dated 20-2-1974 for Rs. 3,500/- (Rupees three thousand five hundred only) for the items (1) permissible varieties of Natural Essential Oils other than banned and canalised upto Rs. 2,500 and (2) Thymol upto Rs. 1,000 for import from General Currency Area with Letter of Authority in favour of M/s. Shakthi Industries, Hyderabad.

They have applied for a duplicate copy of the Customs Purposes Copy of the licence with Customs Purposes Copy of letter of Authority on the ground that the original licence with Letter of Authority has been lost without having been utilised at all.

In support of their contention they have filed an affidavit. I am satisfied that the original Customs Purposes Copy of the licence with Letter of Authority is lost and direct that a duplicate Customs Purposes Copy of licence with Letter of Authority should be issued to the applicant. The original Customs Purposes Copy of the licence is hereby cancelled.

[File No. M-116/SSI/NP/AM 74/002999]HYD]

हैदराबाद, 10 अक्टूबर, 1974

फा० प्रो० 3273:—सर्वश्री एम० बी० इन्डस्ट्रीज न० 10-5-263, न्यू अहमदनगर, हैदराबाद को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से (1) 2500 रुपए तक सरणीबद्ध एवं निषेध से भिन्न स्वीकृत किस्म के प्राकृतिक सुगंधित तेल (2) 1000 रुपए तक थिमोल के आयात के लिए, 3500 रुपए का शक्ति इन्डस्ट्रीज, हैदराबाद के नाम में प्राधिकार पत्र के साथ एक आयात लाइसेंस सं० पी/एम/1743422/सी/एक्स एक्स/50/डब्ल्यू/37-38 दिनांक 12-3-74 स्वीकृत किया गया था।

उन्होंने प्राधिकार पत्र के साथ लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि प्राधिकार पत्र के साथ मूल लाइसेंस बिल्कुल उपयोग किए बिना ही खो गया है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूँ कि प्राधिकार पत्र के साथ लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है और निदेश देता हूँ कि आवेदक को प्राधिकार पत्र के साथ लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रति जारी की जानी चाहिए। लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति एतद्वारा रद्द की जाती है।

[संख्या एम-114/एस एम आई/एन पी/ए एम 74/002970/हैद०]

Hyderabad, the 10th October, 1974

S.O. 3273.—M/s. M.B. Industries, No. 10-5-263, New Ahmednagar, Hyderabad were granted and import licence No. P/S/1743422/C/XX/50/W/37-38 dated 12-3-1974 for Rs. 3,500 for the items (1) permissible varieties of Natural Essential Oils other than canalised, banned upto Rs. 2,500 and (2) Thymol upto 1,000 for import from General Currency Area with Letter of Authority in favour of Shakthi Industries Hyderabad.

They have applied for a duplicate copy of the Customs Purposes copy of the licence with Customs Purposes Copy of Letter of Authority on the ground that the original licence with Letter of Authority has been lost without having been utilised at all.

In support of their contention they have filed an affidavit. I am satisfied that the original Customs Purposes Copy of the licence with Letter of Authority is lost and direct that a duplicate Customs Purposes Copy of the licence with Letter of Authority should be issued to the applicant. The original Customs Purposes Copy of the licence is hereby cancelled.

[No. M-114/SSI/NP/AM 74/002970]HYD.]

फा० प्रो० 3274.—सर्वश्री जे० आर० बिस्कुट फैक्ट्री न० 105-267, फर्स्ट लेन्गर, हैदराबाद-28 को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से (1) 2500 रुपए तक सरणीबद्ध एवं निषेध से भिन्न स्वीकृत किस्म के प्राकृतिक सुगंधित तेल मर्चों और (2) 1000 रुपए तक थिमोल के आयात के लिए, 3500 रुपए के लिए सर्वश्री शक्ति इन्डस्ट्रीज, हैदराबाद के नाम में प्राधिकार पत्र के साथ एक आयात लाइसेंस सं० पी/एम/1743423/सी/एक्स एक्स/50/डब्ल्यू/37-38 दिनांक 12-3-74 स्वीकृत किया गया था।

उन्होंने प्राधिकार पत्र के साथ लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि प्राधिकार पत्र के साथ मूल लाइसेंस बिल्कुल उपयोग किए बिना ही खो गया है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है, मैं संतुष्ट हूँ कि प्राधिकार पत्र के साथ लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है और निदेश देता हूँ कि आवेदक को प्राधिकार पत्र के साथ लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रति जारी की जानी चाहिए। लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति एतद्वारा रद्द की जाती है।

[संख्या जे-32/एस एस आई/एन पी/ए एम 74/002968/हैद०]

एम० एम० नाइकर्णी, उप-मुख्य नियंत्रक

S.O. 3274.—M/s. J.R. Biscuit Factory, No. 105-267, First Lancer, Hyderabad-28 were granted an import licence No. P/S/1743423/C/XX/50/W/37-38 dated 12-3-1974 for Rs. 3,500 (Rupees three thousand and five hundred only) for the items (1) Permissible varieties of Natural Essential Oils other than canalised and banned upto Rs. 2,500 and (2) Thymol upto Rs. 1,000 for import from General Currency Area with Letter of Authority in favour of M/s. Shakthi Industries, Hyderabad.

They have applied for a duplicate copy of the Customs Purposes Copy of the licence with Customs Purposes Copy of Letter of Authority on the ground that the original licence with Letter of Authority has been lost without having been utilised at all.

In support of their contention they have filed an affidavit. I am satisfied that the original Customs Purposes Copy of the licence with letter of authority is lost and direct, that a duplicate custom Purposes Copy of the licence with letter of Authority should be issued to the applicant. The Original Customs Purposes Copy of the licence is hereby cancelled.

[No. I-32/SSI/NP/AM 74/002968/HYD]

P. GOVINDA RAJU, Dy. Chief Controller

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय,

आदेश

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1974

क्रा० प्र० 3275.—सर्वश्री अरि केमिकल इन्डस्ट्रीज, बालगढ़ राह, सोनीपत का अप्रैल-मार्च, 74 अवधि के लिए लाइसेंस सं० पी/एम/1806014, पी/एम/1806015 और पी/एम/1806016 सब का दिनांक 31-3-74 तमाम सामान्य मुद्रा क्षेत्र, यू० के० और रुपया भुगतान क्षेत्र से अग्रिम उपयोग परिकृत रमायनों के लिए 21518 रु०, 10758 रु० और 10759 रुपये मूल्य के लिए प्रदान किए गए थे।

पार्टी ने सूचना दी है कि उपर्युक्त लाइसेंस (मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रतियां और सीमाशुल्क निकासी प्रतियां) बिल्कुल भी उपयोग किए बिना खा गये/अस्थानस्थ हो गए हैं, और उनको रद्द करने के लिए आवेदन किया है। उपर्युक्त कथन के समर्थन में पार्टी ने आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियार्विधि पुस्तक, 1974-75 के पैरा 320 में यथा अपेक्षित एक शपथ पत्र दाखिल किया है।

आयात नियंत्रण आदेश 1955, विनाक 7 दिसम्बर, 1955 के खंड 9 (सी सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ये लाइसेंसेसों की पूर्वाधिक सीमाशुल्क निकासी प्रतियों और मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रतियों को रद्द करने का आदेश देता है।

के० एन० कपूर, उप-मुख्य नियंत्रक,

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक

[सक्रिय पी/ए-15/ए एम 74/ए यू-एच एच/सी एल ए/3915]

(Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports)

(Central Licensing Area)

ORDER

New Delhi, the 22nd October, 1974

S.O. 3275.—M/s. Auro Chemical Industries Balgarh Road, Sonapat were granted licences Nos. P/S/1806014, P/S/1806015 & P/S/1806016 all dated 31-3-1974 for Rs. 21,518, Rs. 10,758 and Rs. 10,759 on GCA, UK & RPA respectively for April-March, 74 period for the end use Fine Chemicals.

The party have intimated that the above said licences (Exchange and Customs copies) have been lost/misplaced without having been utilised at all, and have requested for cancellation thereof. Party have filed an affidavit in support of above statement as required under para 320 of ITC Hand Book of Rules and Procedure 74-75.

In exercise of the powers conferred on me under section 9(CC) of import control order 1955 dated 7th December, 1955, I order the cancellation of the aforesaid customs and exchange/control purposes copies of the licences.

[No. P/A-15/A.M. 74/AU-HH/CLA/3915]

K. N. KAPOOR, Dy. Chief Controller

for Jt. Chief Controller.

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1974

क्रा० प्र० 3276.—सर्वश्री लार्सन एण्ड टुब्रो लि०, बम्बई को 69,71,424 रुपये के लिए एक आयात लाइसेंस सं० पी/सी/2067733/एस/आई बी/52/एच/39-40 दिनांक 7-9-1974 प्रदान किया गया था। उन्होंने दो प्रतियों में माल की सूची के साथ आयात लाइसेंस की अनुलिपि जारी करने के लिए हज़ा आधार पर आवेदन किया है कि माल की सूची के साथ मूल आयात लाइसेंस (सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति दोनों) किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकरण में पंजीकृत कराए बिना और बिल्कुल ही उपयोग किए बिना खा गया/अस्थानस्थ हो गया है। इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है।

तदनुसार मैं संतुष्ट हूँ कि दो प्रतियों में माल की सूची के साथ उक्त मूल आयात लाइसेंस (दोनों प्रतियां) खो गया है। इसलिए समय समय पर यथा संगोहित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के उपखंड 9(सी सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री लार्सन एण्ड टुब्रो लि०, बम्बई, को जारी किया गया उक्त लाइसेंस सं० पी/सी/2067733/एस/आई/बी/42/एच/39-40 दिनांक 7-9-1974 एतद् द्वारा रद्द किया जाता है।

2. उक्त आयात लाइसेंस की अनुलिपि लाइसेंसधारी को भ्रम से जारी की जा रही है।

[सक्रिय 35(74)(8)/सी जी-3]

एम० ए० शेखत, उप-मुख्य नियंत्रक

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 30th November, 1974

S.O. 3276.—M/s. Larsen & Tubro Ltd., Bombay were granted an import licence No. P/C/2067733/S/IB/52/H/39-40 dated 7-9-1974 for Rs. 69,71,424/-. They have applied for the issue of a duplicate import licence alongwith the list of goods in duplicate of the said licence on the ground that the original import licence (both customs purpose and exchange control purpose copies) alongwith list of goods has been lost/misplaced without having been registered with any customs authorities and utilised at all. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit.

I am accordingly satisfied that the original said import licence (both copies) alongwith list of goods in duplicate has been lost. Therefore, in exercise of the powers conferred under Sub-clause 9(cc) of the imports (Control)

order 1955 as amended from time to time the said licence No. P/C/2067733/S/IB/52/H/39-40 dated 7-9-1974 issued to M/s. Larsen and Tubro Ltd., Bombay is hereby cancelled.

2. A duplicate of said import licence is being issued separately to the licensee.

[No. 35(74)(8)/CG.III]

S. A. SHAN, Dy. Chief Controller

औद्योगिक विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(भारतीय मानक संस्था)

नई दिल्ली 28 नवम्बर, 1974

क्र० प्र० 3277.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन लाइसेंसों के व्योरे नीचे दिए गए हैं, वे लाइसेंस-धारी द्वारा अपने नाम में परिवर्तन कर लेने के फलस्वरूप 1 सितम्बर 1974 से रद्द कर दिए गए हैं।

लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक
सी एम/एल-718 29-6-1964	सेमस अर्जना आयरन स्टोन कं० 1439-40, लोनी रोड, दिल्ली शाहदारा, दिल्ली-32	संरचना हस्तान (मानक किस्म)	IS: 226-1969
सी एम/एल-719 29-6-1964	"	संरचना हस्तान (माधारण किस्म)	IS: 1977-1969

[सं० एम० डी० डी०/55:718]

ए० के० गुप्ता, उपमहानिदेशक

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT,
SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi, the 28th November, 1974

S. O. 3277.—In pursuance of sub-regulation (4) of Regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulation 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution, hereby notifies that the licences, particulars of which are given below, have been cancelled with effect from 1 September, 1974 as the name of the licensee has changed:

Licence No. & Date	Name and address of the Licensee	Article/process Covered by the Licence	Relevant Indian Standard
CM/L-718 29-6-1964	M/s Ajanta Iron & Steel co., 1439-40, Loni Road, Delhi Shahdara Delhi -32	Structural Steel (Standard Quality)	IS:226-1969
CM/L-719 29-6-1964	—do—	Structural Steel (Ordinary Quality)	IS:1977-1969

[No. MDD/55:718]

A. K. GUPTA, Deputy Director General

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1974

क्र० प्र० 3278.—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में मलाया प्लान से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप-लाइन भारतीय तेल निगम लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यह: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लक्ष्मी को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपायबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप मध्यम प्राधिकारी भारतीय तेल निगम लिमिटेड, मलाया कोयाली/मथुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, "डोली"-33बी, हरिहर सोसाइटी, राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति बिनिदिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसका मुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

तालुका : मेहमदाबाद	जिला : रवेडा	गुजरात : राज्य	सीमा	
गांव	सर्वेक्षण संख्या	एक	ए	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
खुमानारबाड	553/4	0	04	96
	561	0	16	80
	560/2	0	00	96
	562/1/सी	0	00	16
	652/1/ए+बी	0	11	68
	559	0	11	04
	572/4	0	06	88
	572/5	0	05	92
	572/3	0	03	68
	572/2	0	04	00
	572/1	0	00	96
	573/2	0	03	20
	574/2	0	02	08
	574/1	0	03	20
	574/4	0	09	76
	576/2	0	19	36
	577	0	13	28
	580/1	0	03	84

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
कुमावत-जारी	515/8	0	03	68	खेड़ा-जारी	441	0	09	44
	515/6	0	13	12		452	0	11	20
	515/7	0	00	32		652	0	16	80
	515/1	0	04	00		651	0	17	76
	513/5	0	07	52		644	0	16	96
	513/4	0	00	16		976	0	12	16
	513/2	0	05	60		977	0	02	88
	492/1+2	0	20	00		979	0	20	16
	494/6	0	00	48		981	0	09	12
	491/1	0	04	96		983	0	02	88
	490	0	01	76		969	0	10	08
	495/13	0	08	80		968	0	06	24
	495/12	0	01	12		821	0	13	92
	495/11	0	07	52		967	0	02	56
	495/9	0	03	20		958/5	0	17	12
	495/6	0	00	48		957	0	12	48
	495/5	0	01	92		956/4	0	09	12
	495/4	0	05	92		935	0	13	12
	495/3	0	80	00		1059	0	01	12
	497	0	07	36		1060	0	21	28
	85/1	0	00	32		1058	0	01	44
	84/4	0	13	12		1065	0	15	36
	84/1/1/प/1/2/बी	0	08	48		1125	0	29	60
	84/3	0	00	08		1156	0	00	80
	84/1/1	0	01	44		1193	0	10	72
	83/2	0	07	52		1192	0	06	88
	82/3	0	01	28		1191/1	0	05	28
	83/1	0	00	32		1190/4	0	07	36
	82/3	0	12	96		1190/3	0	01	12
	82/1	0	00	48		1207/7	0	03	20
	80/2	0	11	04		1207/6	0	11	36
	80/1	0	06	72		1207/5	0	01	76
	96/3	0	05	28		1207/4	0	03	48
	95/2	0	09	44		1207/2	0	12	80
	96/1	0	02	40		1208	0	04	32
	97	0	21	76		1209/2	0	07	20
	73	0	12	80		1209/1	0	00	32
	74	0	00	16		1213	0	11	24
	70	0	13	28		1212	0	01	92
	71/1	0	08	32		1216	0	00	16
	68/1	0	04	64		1217	0	08	64
	69/2	0	09	44		1218	0	06	40
	65	0	46	40		1177	0	03	36
						1176	0	06	36
खेड़ा	439/3	0	25	92		1175	0	08	22
	439/2	0	14	40		1283	0	12	32
	439/1	0	01	28		1285	0	00	96
	440/3	0	19	52		1286	0	10	08
	440/2	0	08	64		1287	0	07	20
	440/1	0	11	04		1295	0	02	72

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
बेड़ा-जारी	1294	0	10	88	बसना खुद-जारी	303	0	23	72
	1297	0	00	16		302/ए	0	15	20
	1293	0	00	16		298	0	08	96
	1308	0	16	80		299	0	10	08
	1307	0	00	48		300	0	08	68
	1309	0	07	52					
	1310	0	20	64	समझा	405	0	06	40
	1313	0	00	16		406	0	00	08
	1311	0	02	56		407	0	17	76
	1312	0	26	56		408	0	26	61
						13	0	06	50
दीवारा	240	0	05	12		419	0	21	19
	239	0	49	76		371	0	08	00
	241	0	03	68		420	0	17	44
	230	0	14	50		271	0	06	75
	235	0	19	84		272	0	03	86
	236	0	00	32		273	0	10	44
	237	0	11	68		277	0	07	65
	205	0	08	48		275	0	20	16
	206/ए+बी	0	05	22		305	0	46	56
	204	0	12	96		254	0	29	98
	201	0	17	25		253	0	20	48
	200	0	30	40		251	0	28	32
	273	0	25	92		249	0	12	48
	186	0	00	96		197	0	10	08
	276	0	07	75		198	0	30	83
	277	0	25	28		207	0	05	36
	281	0	14	72		208	0	19	84
	280	0	08	96		224	0	12	09
	284	0	15	52		223	0	08	68
						222	0	12	00
बसना खुद	3	0	28	33		221	0	06	00
	6	0	00	16		216	0	00	60
	4/बी	0	09	28		217	0	12	00
	4/ए	0	18	30		219	0	15	18
	5	0	00	16		228	0	10	12
	211	0	11	50		229	0	10	12
	208	0	06	00					
	212	0	06	07	सरसा	157	0	10	12
	213/ए	0	06	07		158	0	19	22
	326/बी	0	16	32		154/1	0	11	13
	326/ए	0	01	79		155	0	08	09
	323	0	01	17		168	0	04	05
	324/बी	0	00	32		165	0	09	11
	324/ए	0	06	40		166	0	33	39
	228	0	13	78		177	0	02	02
	284	0	18	80		178	0	07	20
	320	0	11	20		194	0	05	06
	319	0	00	18		193	0	11	13
	285/ए	0	02	40		192	0	11	13

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
सरमा-जारी	206	0	09	76	विदज-जारी	881	0	20	37
	191	0	20	23		880/2	0	10	88
	189	0	08	09		883/2	0	03	55
	224	0	81	76		883/1	0	06	58
	215	0	11	13		891/4	0	05	12
	216	0	15	08		891/3	0	01	32
	240/1	0	23	68		891/2/सो	0	06	88
	237	0	02	08		891/2/बी	0	07	08
	238	0	08	00		891/2/ए	0	03	20
	239	0	15	01		891/1	0	01	92
	251	0	00	64		890/3	0	00	62
	248	0	10	72		896	0	01	76
	260	0	03	84		894	0	01	28
	256	0	00	04		902	0	10	72
	259	0	11	20		903	0	05	12
	257/2	0	03	68		687	0	15	18
	257/1	0	00	48		686	0	13	40
	493	0	11	10		645	0	02	53
	264	0	04	16		685	0	14	41
	330/1	0	00	64		646/1	0	00	06
	331	0	05	12		657/2	0	11	41
	333	0	01	28		657/1	0	05	82
	332	0	11	84		659	0	00	89
	329/1	0	00	96		660	0	07	59
	329/2	0	04	32		661	0	06	62
	336/4	0	03	68		662/2	0	09	61
	336/1	0	02	88		663/1	0	05	06
	336/3	0	06	24		631/6	0	07	08
	337/2	0	08	00		632/1	0	00	06
	337/1	0	00	32		631/4	0	04	55
	335	0	06	40		664	0	02	53
	376	0	15	20		631/1	0	04	55
	375	0	13	50		630/1	0	05	31
	373	0	06	40		630/2	0	02	52
	374	0	05	40		623	0	05	31
	372	0	02	08		624/3	0	04	05
	371	0	07	20		624/2	0	01	52
	370	0	00	64		624/1	0	06	07
	380	0	11	04		615/3	0	00	50
	366	0	16	00		616/2	0	03	04
	365	0	00	32		616/1	0	08	09
	364	0	24	80		492/2	0	00	06
	363	0	00	40		493/1	0	05	06
	362	0	22	40		493/2	0	04	81
	388	0	01	30		494	0	06	57
विदाज	861	0	06	56		495/2	0	05	06
	860	0	16	32		507	0	05	57
	859	0	09	22		506	0	06	07
	873	0	06	40		505/2	0	04	81
	857	0	00	88		504/2	0	07	33

SCHEDULE

1	2	3	4	5
बिदाज-जारी	504/1	0	00	12
	524/1	0	08	07
	524/2	0	04	05
	525/1	0	01	26
	526	0	06	83
	27/1	0	10	88
	404/2	0	04	30
	404/3	0	10	12
	404/1	0	02	52
	403	0	05	06
	402	0	08	60
	395	0	25	29
	428	0	00	76
	394/4	0	08	09
	394/3	0	00	25
	394/2	0	01	52
	394/1	0	07	08
	393	0	06	07

[संख्या 12017/6/74-एल एण्ड एल-1]

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 23rd November, 1974

S.O. 3278.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its Intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali/Mathura Pipeline Project, "DOLI" 33-B. Harihar Society, Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

110 GI/74—3.

Taluka : MEHMEDABAD District : KHEDA

GUJARAT STATE

Village	Survey No.	Extent		
		H.	A.	Sq. M.
Khumarvad	553/4	0	04	96
	561	0	16	80
	560/2	0	00	96
	562/1/C	0	00	16
	562/1/A & B	0	11	68
	559	0	11	04
	572/4	0	06	88
	572/5	0	05	92
	572/3	0	03	68
	572/2	0	04	00
	572/1	0	00	96
	573/2	0	03	20
	574/2	0	02	08
	574/1	0	03	20
	574/4	0	09	76
	576/2	0	19	36
	577	0	13	28
	580/1	0	03	84
	515/8	0	03	68
	515/6	0	13	12
	515/7	0	00	32
	515/1	0	04	00
	513/5	0	07	52
	513/4	0	00	16
	513/2	0	05	60
	492/1+2	0	20	00
	494/6	0	00	48
	491/1	0	04	96
	490	0	01	76
	495/13	0	08	80
	495/12	0	01	12
	495/11	0	07	52
	495/9	0	03	20
	495/6	0	00	48
	495/5	0	01	92
	495/4	0	05	92
	495/3	0	80	00
	497	0	07	36
	85/1	0	00	32
	84/4	0	13	12
	84/1/1/A	0	08	48
	1/2/B			
	84/3	0	00	08
	84/1/1	0	01	44
	83/2	0	07	52
	82/3	0	01	28
	83/1	0	00	32
	82/2	0	12	96
	82/1	0	00	48
	80/2	0	11	04
	80/1	0	06	72
	96/3	0	05	28
	95/2	0	09	44
	96/1	0	02	40
	97	0	21	76
	73	0	12	80
	74	0	00	16
	70	0	13	28
	71/1	0	08	32
	68/1	0	04	64
	69/2	0	09	44
	65	0	46	40
Kheda	439/3	0	25	92
	439/2	0	14	40
	439/1	0	01	28
	440/3	0	19	52
	440/2	0	08	64
	440/1	0	11	04
	441	0	09	44

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Khajda (Contd.)	452	0	11	20	Vasna Khurd	3	0	28	33
	653	0	16	80		6	0	00	16
	651	0	17	76		4/B	0	09	28
	644	0	16	96		4/A	0	18	30
	976	0	12	16		5	0	00	16
	977	0	02	88		211	0	11	50
	979	0	20	16		208	0	06	00
	981	0	09	12		212	0	06	07
	983	0	02	88		213/A	0	06	07
	969	0	10	08		326/B	0	16	32
	968	0	06	24		226/A	0	01	79
	821	0	13	92		323	0	01	17
	967	0	02	56		324/B	0	00	32
	958/5	0	17	12		324/A	0	06	40
	957	0	12	48		228	0	13	78
	956/4	0	09	12		284	0	18	80
	955	0	13	12		320	0	11	20
	1059	0	01	12		319	0	00	18
	1060	0	21	28		285/A	0	02	40
	1058	0	01	44		303	0	23	72
	1065	0	15	36		302/A	0	15	20
	1125	0	29	60		298	0	08	96
	1156	0	00	80		299	0	10	08
	1193	0	10	72		300	0	08	68
	1192	0	06	88					
	1191/1	0	05	28	Samadra	405	0	06	40
	1190/4	0	07	36		406	0	00	08
	1190/3	0	01	12		407	0	17	76
	1207/7	0	03	20		408	0	26	61
	1207/6	0	11	36		13	0	06	50
	1207/5	0	01	76		419	0	21	19
	1207/4	0	03	48		371	0	08	00
	1207/2	0	12	80		420	0	17	44
	1208	0	04	32		271	0	06	75
	1209/2	0	07	20		272	0	03	86
	1209/1	0	00	32		273	0	10	44
	1213	0	14	24		277	0	07	65
	1212	0	01	92		275	0	20	16
	1216	0	00	16		303	0	46	56
	1217	0	08	64		254	0	29	98
	1218	0	06	40		253	0	20	48
	1177	0	03	36		251	0	28	32
	1176	0	06	56		249	0	12	48
	1175	0	08	22		197	0	10	08
	1283	0	12	32		198	0	30	83
	1285	0	00	96		207	0	05	36
	1286	0	10	08		208	0	19	84
	1287	0	07	20		224	0	12	09
	1295	0	02	72		223	0	08	68
	1294	0	10	88		222	0	12	00
	1297	0	00	16		221	0	06	00
	1293	0	00	16		216	0	00	60
	1308	0	16	80		217	0	12	00
	1307	0	30	48		219	0	15	18
	1309	0	07	52		228	0	10	12
	1310	0	20	64		229	0	10	12
	1313	0	00	16					
	1311	0	02	56	Sarsa	157	0	10	12
	1312	0	26	56		158	0	19	22
						154/1	0	11	13
						155	0	08	09
						168	0	04	05
						165	0	09	11
Dadarda	240	0	05	12					
	239	0	49	76					
	241	0	03	68					
	230	0	14	50					
	235	0	19	84					
	236	0	00	32					
	237	0	11	68					
	205	0	08	48					
	206/A + B	0	05	22					
	204	0	12	96					
	201	0	17	25					
	200	0	30	40					
	273	0	25	92					
	186	0	00	96					
	276	0	07	75					
	277	0	25	28					
	281	0	14	72					
	280	0	08	96					
	284	0	15	5					

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Sarsa (Contd.)	166	0	33	39	Bidaj (Contd.)	880/2	0	10	88
	177	0	02	02		883/2	0	03	55
	178	0	07	20		883/1	0	06	58
	194	0	05	06		891/4		05	12
	193	0	11	13		891/3	0	04	32
	192	0	11	13		891/2/C	0	06	88
	206	0	09	76		891/2/B	0	07	08
	191	0	20	23		891/2/A	0	3	20
	189	0	08	09		891/1/	0	01	92
	224	0	81	76		890/3	0		62
	215	0	11	13		896	0	01	76
	216	0	15	08		894	0	01	28
	240/1	0	23	68		902	0	10	72
	237	0	02	08		903	0	05	12
	238	0	08	00		687	0	15	18
	239	0	15	04		686	0	13	40
	251	0	00	64		645	0	02	53
	248	0	10	72		685	0	14	41
	260	0	03	84		646/1	0	00	06
	256	0	00	04		657/2	0	14	41
	259	0	11	20		657/1	0	05	82
	257/2	0	03	68		659	0	00	89
	257/1	0	00	48		660	0	07	59
	493	0	14	40		661	0	06	62
	264	0	04	16		662/2	0	09	61
	330/1	0	00	64		663/1	0	05	06
	331	0	05	12		631/6	0	07	08
	333	0	01	28		632/1	0	00	06
	332	0	11	84		631/4	0	04	55
	329/1	0	00	96		664	0	02	53
	329/2	0	04	32		631/1	0	04	55
	336/4	0	03	68		630/1	0	05	31
	336/1	0	02	88		630/2	0	02	57
	336/3	0	06	24		623	0	05	31
	337/2	0	08	00		624/3	0	04	05
	337/1	0	00	32		624/2	0	01	52
	335	0	06	40		624/1	0	06	07
	376	0	15	20		615/3	0	00	50
	375	0	13	50		616/2	0	03	04
	373	0	06	40		616/1	0	08	09
	374	0	05	40		492/2	0	00	06
	372	0	02	08		493/1	0	05	06
	371	0	07	20		493/2	0	04	81
	370	0	00	64		494	0	06	57
	380	0	11	04		495/2	0	05	06
	366	0	16	00		507	0	05	57
	365	0	00	32		506	0	06	07
	364	0	24	80		505/2	0	04	81
	363	0	00	40		504/2	0	07	33
	362	0	22	40		504/1	0	00	12
	388	0	01	30		524/1	0	06	07
						524/2	0	04	05
Bidaj	861	0	06	56		525/1	0	01	26
	860	0	16	32		526	0	06	83
	859	0	09	22		527/1	0	10	88
	873	0	06	40		404/2	0	04	30
	857	0	00	88		404/3	0	10	12
	881	0	20	37					

1	2	3	4	5
Bidaj (Contd.)	404/1	0	02	52
	403	0	05	06
	402	0	08	60
	395	0	25	29
	428	0	00	76
	394/4	0	08	09
	394/3	0	00	25
	394/2	0	01	52
	394/1	0	07	08
	393	0	06	07

[No. 12017/6/74-L&L-II]

क्र० 3279.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पत्तन से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय तेल निगम लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

धोरयनः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एनडुगाबध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः, अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसके उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है ।

उक्त भूमि में हितवश कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, पलाया कोयानी/मथुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, "डोली"-33 बी, हरिहर सोसाइटी, राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सूनवाई व्यक्तिः हो या किसी व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

तालुका:- बबोदरा जिला:-बबोदरा गुजरातः राज्य

गाँव	सर्वेक्षण सख्या	सीमा		
		एच०	ए०	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
रनोली	353	0	03	68
	355	0	06	40
	356	0	02	02
	367	0	07	20
	371	0	01	00
	370	0	02	56
	427	0	07	20
	428	0	00	10
	430	0	06	64
	424	0	01	18

1	2	3	4	5
रनोली (जारी)	432	0	05	28
	421	0	06	14
	434/2	0	04	00
	437	0	02	24
	438	0	02	40
	440	0	03	56
	441	0	01	37
	443	0	05	87
	451	0	01	15
	450	0	05	44
	449	0	00	04
	470	0	00	42
	471	0	05	44
	477	0	02	48
	479	0	02	80
	480	0	02	30
	490	0	00	71
	489	0	02	24
	484	0	02	56
	488	0	00	25
	486	0	02	82
	487	0	02	30
	463/1	0	04	48

पबमाला	688	0	08	80
	689	0	02	08
	690	0	03	36
	736/6	0	13	60
	714	0	00	80
	735/3	0	09	95
	735/1	0	03	92
	733	0	07	30
	736/2/ए	0	20	80
	738	0	04	69
	736/2/बी	0	31	32

नानवैसरी	426/1	0	03	51
	426/2	0	65	12
	426	0	15	74
	421	0	06	10
	422/2	0	04	25
	422/1	0	06	84
	423	0	19	52
	416	0	04	32
	415/3	0	03	44
	415/1	0	01	60
	441	0	00	25
	442	0	05	12
	337	0	05	28
	334	0	03	46

1	2	3	4	5
मानदेसरी (जारी)	355	0	03	44
320/1/ए		0	01	78
320		0	04	32
319/6		0	04	33
318		0	02	56
317		0	03	36
346		0	01	60
348		0	07	68
308		0	05	20
307/7		0	04	00
307/6		0	01	60
307/5		0	00	42
307/4		0	02	56
306		0	03	84
305		0	02	40
291		0	00	36
282		0	04	69
283		0	04	80
270		0	08	64
253		0	06	08
262/1		0	05	44
262		0	00	90
254		0	00	64
255		0	07	20
256		0	02	24
280		0	00	08
259		0	06	56

कजलपुर	299	0	04	48
	300	0	00	16
	304/3	0	02	48
	305	0	03	36
	306	0	05	28
	307	0	00	56
	312	0	00	10
	311/3	0	03	84
	311/2	0	01	92
	316	0	02	74
	315	0	00	14
	317	0	02	96
	280/2	0	02	72
	279	0	02	88
	278	0	08	14
	18	0	07	67
	19	0	15	00
	20	0	18	32
	1	0	77	46
	30	0	11	84
	31/1	0	12	33

1	2	3	4	5
कजलपुर (जारी)	33	0	01	45
	6	0	11	20
	55/1	0	05	95

[संख्या 12017/6/74 एम एण्ड एल-2]

S.O. 3279.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land prescribed in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act. 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its Intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali/Mathura Pipeline Project, "DOLI" 33-B, Harihar Society, Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Taluka:-VADODARA

District:-VADODARA

GUJARAT STATE

Village	Survey No.	Extent		
		H.	A.	Sq. M.
1	2	3	4	5
Ranoli	353	0	03	68
	355	0	06	40
	356	0	02	02
	367	0	07	20
	371	0	01	00
	370	0	02	56
	427	0	07	20
	428	0	00	10
	430	0	06	64
	424	0	01	18
	432	0	05	28
	421	0	06	14
	434/2	0	04	00
	437	0	02	24
	438	0	02	40
	440	0	03	56
	441	0	01	37
	443	0	05	87
	451	0	01	15
	450	0	05	44
	449	0	00	04
	470	0	00	42
	471	0	05	44
	477	0	02	48
	479	0	02	80

1	2	3	4	5
Ranoli (contd.)	480	0	02	30
	490	0	00	71
	489	0	02	24
	484	0	02	56
	488	0	00	25
	486	0	02	82
	487	0	02	30
	463/1	0	04	48
Padmala	688	0	08	80
	689	0	02	08
	690	0	03	36
	736/8	0	13	60
	714	0	00	80
	735/3	0	09	95
	735/1	0	03	92
	733	0	07	30
	736/2/A	0	20	80
	738	0	04	69
	736/2/B	0	31	32
Nandesari	426/1	0	03	51
	426/2	0	65	12
	426	0	15	74
	421	0	06	10
	422/2	0	04	25
	422/1	0	06	81
	423	0	19	52
	416	0	04	32
	415/3	0	03	44
	415/1	0	01	60
	441	0	00	25
	442	0	05	12
	337	0	05	28
	334	0	03	46
	335	0	03	44
	320/1/A	0	01	76
	320	0	04	32
	319/6	0	04	33
	318	0	02	56
	317	0	03	36
	346	0	01	60
	348	0	07	68
	308	0	05	20
	307/7	0	04	00
	307/6	0	01	60
	307/5	0	00	42
	307/4	0	02	56
	306	0	03	84
	305	0	02	40
	291	0	00	36
	292	0	04	69
	293	0	04	80
	270	0	08	64
	253	0	06	08
	262/1	0	05	44
	262	0	00	90
	254	0	00	64
	255	0	07	20
	256	0	02	24
	260	0	00	08
	259	0	06	56
Fajalpur	299	0	04	48
	300	0	00	16
	304/3	0	02	48
	305	0	03	36
	306	0	05	28
	307	0	00	56
	312	0	00	10
	311/3	0	03	84
	311/2	0	01	92
	316	0	02	74
	315	0	00	14
	317	0	02	96
	280/2	0	02	73
	279	0	02	88
	278	0	08	14
	18	0	07	67

1	2	3	4	5
Fajalpur (contd.)	19	0	15	00
	20	0	18	32
	1	0	77	46
	30	0	11	84
	33/1	0	12	33
	33	0	01	45
	6	0	11	20
	55/1	0	05	95

[No. 12017/6/74-L&L/II]

क्र० 3280—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पत्तन से उषर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोपियम के परिवहन के लिए पाइप-लाइन भारतीय तेल निगम लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी साहनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब, पेट्रोपियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राण्य एतद्वारा किया है।

उक्त भूमि में हितवादी कोई व्यक्ति, उस भूमि के बीच पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, सलाया कोयाली/मथुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, "डोली" 33-बी, हरिहर सोमाहटी, राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुतवादी व्यक्तिता को किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

तालुका : राजकोट	जिला : राजकोट	राज्य गुजरात			
गांव	सर्वेक्षण संख्या	सीमा			
		एच.ए.	बर्न	मी०	
1	2	3	4	5	
गवर्गवाव	413	1	40	63	
	359	0	46	54	
	512/पी०-1	0	14	16	
	361	0	32	37	
	373	0	16	19	
	411	0	22	26	
	410	0	06	07	
	409	0	33	39	
	408	0	13	15	
	512/पी०-2	0	21	25	
	406	0	36	42	
	404	0	28	33	
	512/पी०/3	0	10	12	

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
गवर्दिदाव—जारी	401	0	25	29	ना लपार—जारी	69पी	0	02	02
	399	0	19	22		186 पी/1	0	12	14
	398	0	01	01		186 पी/2	0	15	18
	396 एण्ड 397	0	22	26		187	0	05	06
	501	0	25	28					
	500	0	10	12	स्त्रिजाडिया	170	0	15	18
	502	0	12	32		155/1	0	10	12
	499	0	09	60		154/1पी/1	0	24	28
	498	0	44	16		154/1पी/2	0	27	32
	496	0	18	10		143/1	0	02	02
	497	0	23	20		142/1	0	13	15
	505/1	0	20	32		141 पी/1	0	12	14
	21 पी०/1	0	50	59		140	0	13	15
	21 पी०/2	0	12	14		141 पी/2	0	13	15
	20 पी/1	0	18	21		120	0	20	23
	20 पी/2	0	08	09		121	0	14	16
	20 पी-3	0	08	09		124	0	31	36
	20 पी/4	0	20	23		125	0	15	18
	511	0	24	28		126	0	14	16
	180 पी०	0	11	49		127	0	23	27
	181	0	19	22		131	0	02	02
	182	0	43	50		130	0	29	34
	184	0	24	28		88 पी/1	0	18	21
	185	0	47	55		88 पी/2	0	17	20
	193	0	26	30		97 पी/1	0	07	08
	168 पी/1	0	15	18		87 पी/2	0	07	08
	168 पी/2	0	15	18		86	0	02	02
	168 पी/3	0	20	23		73 पी/1	0	24	28
	166	0	21	25		73 पी/2	0	22	26
	165	0	33	39					
	161	0	21	25	सनीमरा	104	0	80	94
	159	0	26	30		105	0	15	18
	157	0	26	30		106	0	38	45
	156	0	03	04		107 पी/1	0	17	20
						107 पी/2	0	80	90
						107 पी/3	0	22	26
						110	0	45	48
राजगढ़	15	0	15	18					
	16	0	10	12	सिथाना	197	0	20	23
	23	0	15	18		199	0	56	66
	22	0	27	32		192	0	48	56
	32 पी/1	0	24	28		191	0	68	80
	32 पी/2	0	18	21		361 पी/2	0	24	28
	41 पी/1	0	37	43		361 पी/4	0	19	22
	41 पी/2	0	20	23		124/2	0	44	52
	46	0	38	45		124/1	0	48	56
	47	0	17	20		125	0	19	22
	49	0	02	02		128	0	01	01
	50 पी/1	0	26	30		129	0	46	54
	51	0	61	71		130	0	29	34
नागलपार	72 पी	0	06	07					
	65 पी	0	25	29					
	59 पी	0	96	11					

1	2	3	4	5
मथुरा (मियाता)	20/3 पी/1	0	08	09
	20/3 पी/2	0	17	20
	33 पी/1	0	18	21
	33 पी/2	0	03	04
	32/2-ए	0	06	07
	32/2-बी	0	06	07
	33 पी/3	0	12	14
मकवास	15/2 बी.ए.एम.	0	29	34
	20 पी/1	0	07	08
	20 पी/2	0	19	22
	17 पी	0	05	08
	16 पी	0	16	19

[संख्या 12017/6/74-एल एण्ड एल-3]

पी० पी० गुप्ता, उप सचिव

S.O. 3280.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its Intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali/Mathura Pipeline Project, "DOLI" 33-B. Harihar Society, Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Taluka: Rajkot	District: Rajkot	Gujarat: State		
Village	Survey No.	Extent		Sq.M.
		H.	A.	Sq.M.
1	2	3	4	5
Gavaridad	413	1	40	63
	359	0	46	54
	512/P1	0	14	16
	361	0	32	37
	373	0	16	19
	411	0	22	26
	410	0	06	07
	409	0	33	39
	408	0	13	15
	512/P2	0	21	25
	406	0	36	42
	404	0	28	33
	512/P3	0	10	12

1	2	3	4	5
Gavaridad—contd.	401	0	25	29
	399	0	19	22
	398	0	01	01
	396 & 397	0	22	26
	501	0	25	28
	500	0	10	12
	502	0	12	32
	499	0	09	60
	498	0	44	16
	496	0	18	40
	497	0	23	20
	505/1	0	20	32
	21 P/1/	0	50	59
	21 P/2	0	12	14
	20 P/1	0	18	21
	20 P/2	0	08	09
	21 P/3	0	08	09
	20 P/4	0	20	23
	511	0	24	28
	180/P	0	41	48
	181	0	19	22
	182	0	43	50
	184	0	24	28
	185	0	47	55
	193	0	26	30
	168 P/1	0	15	18
	168 P/2	0	15	18
	168 P/3	0	20	23
	166	0	21	25
	165	0	33	39
	161	0	21	25
	158	0	26	30
	157	0	26	30
	156	0	03	04

Rajgad	15	0	15	18
	16	0	10	12
	23	0	15	18
	22	0	27	32
	32 P/1	0	24	28
	32 P/2	0	18	21
	41 P/1	0	37	43
	41 P/2	0	20	23
	46 P	0	38	45
	47	0	17	20
	49	0	02	02
	50 P/1	0	26	20
	51	0	61	71
Nagalpar	72 P	0	06	07
	65 P	0	25	29
	59 P	0	96	11
	63 P	0	02	02
	186 P/1	0	12	14
	186 P/2	0	15	18
	187	0	05	06

Khijadia	170	0	15	18
	155/1	0	10	12
	154/1 P/1	0	24	28
	154/1 P/2	0	27	32
	143/1	0	02	02
	142/1	0	13	15
	141 P/1	0	12	14
	140	0	13	15
	141 P/2	0	13	15
	120	0	20	23
	121	0	14	16
	124	0	31	36
	125	0	15	18
	126	0	14	16
	127	0	23	27
	131	0	02	02
	130	0	29	34
	88 P/1	0	18	21
	88 P/2	0	17	20
	87 P/1	0	07	08
	87 P/2	0	07	08
	86	0	02	02
	73 P/1	0	24	28
	73 P/2	0	22	26

1	2	3	4	5
Sanosara	104	0	80	94
	105	0	15	18
	106	0	38	45
	107 P/1	0	17	20
	107 P/2	0	08	09
	107 P/3	0	22	26
	110	0	45	48
Jhiyana	197	0	20	23
	199	0	56	66
	192	0	48	56
	191	0	68	80
	361 P/2	0	24	28
	361 P/4	0	19	22
	124/2	0	44	52
	124/1	0	48	56
	125	0	19	22
	128	0	01	01
	129	0	46	54
	130	0	29	34
Machhudem (Jhiyana)	20/3 P/1	0	08	09
	20/3 P/2	0	17	20
	33 P/1	0	18	21
	33 P/2	0	03	04
	32/2-A	0	06	07
	32/2-B	0	06	07
	33 P/3	0	12	14
Vankvad	15/2 DAM	0	29	34
	20 P/1	0	07	08
	20 P/2	0	19	22
	17 P	0	05	06
	16 P	0	16	19

[No. 12017/6/74-L&L-III]

P. P. GUPTA, Dy. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

परिवहन पक्ष

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1974

क्रा० आ० 3281—डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5 क की उप-धारा (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० क्रा० आ० 3074, तारीख 23 अगस्त, 1968 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को, उक्त धारा 5 क की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित कोचीन डॉक श्रम बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और कोचीन पोर्टन न्याय के अध्यक्ष को उक्त बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित करती है, अर्थात्—

केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य—

- (1) अध्यक्ष, कोचीन पोर्टन न्याय, कोचीन।
- (2) उपाध्यक्ष, कोचीन डॉक श्रम बोर्ड, कोचीन।
- (3) उप-श्रम आयुक्त, एर्नाकुलम्।
- (4) सहायक श्रम-आयुक्त (केन्द्रीय), एर्नाकुलम्।

डॉक कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य—

- (1) श्री एम० के० राघवन् } कोचीन थूरमगा थेजिलाली यूनियन
- (2) ए० ए० कोचुन्नी } के प्रतिनिधि

110GI/74-4

(3) श्री जी० एम० धारा सिंह—कोचीन पोर्टन थेजिलाली यूनियन के प्रतिनिधि

(4) श्री के० एम० राजन्—कोचीन डॉक कर्मचारी एसोसिएशन के प्रतिनिधि

डॉक कर्मचारों के नियोजकों और नौवहन कम्पनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य—

- (1) श्री के० जी० भगत } यूनाइटेड स्टीवेजर्स एसोसिएशन
- (2) श्री के० जे० हरगोल } आफ कोचीन (प्राइवेट) लिमिटेड के प्रतिनिधि

(3) श्री के० जी० टामन—इण्डियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि।

(4) श्री ई० टी० वी० एम मेनन—विदेशी नौवहन हितों के प्रतिनिधि

[सक्रिया-बी 14012/1/71/पी एण्ड डी/एस डी

बी० शंकरलिंगम्, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 2nd December, 1974

S.O. 3281.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3074, dated the 23rd August, 1968, the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Cochin Dock Labour Board established under sub-section (1) of the said section 5A and nominates the Chairman, Cochin Port Trust as Chairman and the said Board namely:—

- (1) The Chairman, Cochin Port Trust, Cochin.
- (2) The Deputy Chairman, Cochin Dock Labour Board, Cochin.
- (3) The Deputy Labour Commissioner, Ernakulam.
- (4) The Assistant Labour Commissioner (Central), Ernakulam.

Members representing the Dock workers:

- (1) M. K. Raghavan—Representatives of the Cochin.
- (2) Shri A. A. Kochunny—Thuramugha Thozhilali Union.
- (3) Shri G. S. Dhara Singh—Representative of the Cochin Port Thozhilali Union.
- (4) Shri K. A. Rajan—Representative of the Cochin Dock Employees Association.

Members representing the employers of Dock Workers and Shipping Companies:

- (1) Shri K. G. Bhagat.
- (2) Shri Herschell—Representatives of the United Stevedores Association of Cochin (Pvt.) Limited
- (3) Shri K. G. Thomas—Representative of the Indian National Shipowners' Association.
- (4) Shri E.T.V.S. Menon—Representative of the Overseas Shipping Interests.

[No. V-14012/1/71/P&D/LD]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

New Delhi, the 30th November, 1974

S.O. 3282.—The following draft of certain Scheme for the Dock Workers of the port of Bombay, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government

DRAFT SCHEME

1 Short title and commencement—(1) The Scheme may be called the Bombay Foodgrain Handling Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1974 (hereinafter referred to as "the Scheme").

2 Objects and application—(1) The objects of the Scheme are to ensure greater regularity of employment for the foodgrain handling workers in the port of Bombay and to secure that an adequate number of dock workers is available for the efficient performance of dock work

(2) The Scheme relates to the Port of Bombay and applies to the classes or descriptions of dock work and dock workers set out in Schedule I

(3) The Scheme shall apply to registered foodgrain handling workers and registered employers

(4) Nothing in this Scheme shall apply to any class or description of dock work and dock workers in the Indian Naval Dockyard, Bombay.

3 Definition—In this Scheme, unless the context otherwise requires:—

- (a) "Act" means the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948),
- (b) "Administrative Body" means the Administrative Body appointed under clause 4,
- (c) "Board" means the Bombay Dock Labour Board constituted under the Act,
- (d) "Chairman" means the Chairman of the Board,
- (e) "Deputy Chairman" means the Deputy Chairman of the Board,
- (f) "Daily worker" means a registered dock worker who is not a monthly worker,
- (g) "dock employer" means the person by whom a dock worker is employed or is to be employed and includes a group of dock employers formed under clause 15(1)(d),
- (h) "dock work" means operations at places or premises to which the Scheme relates, ordinarily performed by dock workers of the classes or descriptions to which the Scheme applies,
- (i) "employers register" means the register of dock employers maintained under the Scheme;
- (j) "Labour Officer" means the Labour Officer appointed by the Administrative Body under clause 12,
- (k) "monthly worker" means a registered dock worker who is engaged by a registered employer or a group of such employers on monthly basis under a contract which requires for its termination a least one month's notice on either side,
- (l) "Personnel Officer" means the Personnel Officer appointed by the Board under clause 5,
- (m) "register or record" means the register or record of dock workers maintained under the Scheme,

(n) "registered dock worker" means a foodgrain handling worker whose name is for the time being entered in the register or record,

(o) "registered employer" means a dock employer whose name is for the time being entered in the employers register,

(p) "reserve pool" means a pool of registered dock workers who are available for work, and who are not for the time being in the employment of a registered employer or a group of dock employers as monthly workers,

(q) "rules" means the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules 1962

(r) "vessel" means an ocean-going vessel or ship whose gross registered tonnage is not less than 350 tonnes and shall include barges discharged from a lash ship but shall not include the Bombay Port Trust crafts,

(s) "week" means the period commencing from the mid night of Saturday and ending on the midnight of the next succeeding Saturday

4 Administrative Body—(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette appoint the Bombay Stevedores Association Limited or any other authority to be the Administrative Body for the purpose of carrying on the day-to-day administration of the Scheme

(2) The Administrative Body shall, subject to the supervision and control of the Board and the Chairman and subject to the provisions of clause 44, carry on the day-to-day administration of the Scheme

(3) The Central Government may for sufficient cause remove any Administrative Body appointed under sub-clause (1)

Provided that the Administrative Body shall not be removed unless it has been given a reasonable opportunity of being heard

5 Personnel Officer and other servants of the Board—The Board may appoint a Personnel Officer and such other officers and servants and pay them such salaries and allowances and specify such terms and conditions of service as it deems fit

Provided that no post the maximum salary of which exclusive of allowances is rupees one thousand two hundred and fifty and above per mensem shall be created, and no appointment to such post shall be made by the Board except with the previous approval of the Central Government

Provided further that the sanction of the Central Government shall not be necessary to any appointment in a leave vacancy of a duration of not more than three months

6 Functions of Board—(1) The Board may take such measures as it may consider desirable for furthering the objectives of the Scheme set out in clause 2, including measures for:

- (a) ensuring the adequate supply and the full and proper utilisation of dock labour for the purpose of facilitating the rapid and economic turn-round of vessels and the speedy transit of goods through the Port,
- (b) regulating the recruitment and entry into and the discharge from the Scheme and the allocation of registered dock workers in the reserve pool to registered employers,
- (c) determining and keeping under review in consultation with the Administrative Body the number of registered employers and registered dock workers from time to time on the registers or records and the increase or reduction to be made in the numbers in any such register or record,
- (d) keeping adjusting and maintaining the employers' registers, entering or re-entering therein the name of any dock employer and, where circumstances so

require, removing from the register the name of any registered employer, either at his own request or in accordance with the provisions of the Scheme;

- (e) keeping, adjusting and maintaining from time to time such registers or records, as may be necessary, of registered dock workers including any registers or records of registered dock workers who are temporarily not available for dock work and whose absence, has been approved by the Administrative Body and, where circumstances so require, removing from any register or record the name of any registered dock worker either at his own request or in accordance with the provisions of the Scheme;
- (f) the grouping or regrouping of all registered dock workers into such groups as may be determined by the Board after consultation with the Administrative Body and thereafter reviewing the grouping of any registered dock worker on the application of the Administrative Body or of the registered dock worker;
- (g) making provisions for the training and welfare of registered dock workers including medical service in so far as such provision does not exist apart from the Scheme;
- (h) levying and recovering from registered employers contributions, in respect of the expenses of the Scheme;
- (i) making provision for health and safety measures in places where registered dock workers are employed in so far as such provision does not exist apart from the Scheme;
- (j) maintaining and administering the Dock Workers Welfare Fund and recovering from all registered employers contribution towards the Fund in accordance with the rules framed by the Board and recovering from all registered employers contribution of the Fund framed under clause 54;
- (k) maintaining and administering a Provident Fund Gratuity Fund, a Voluntary Retirement Fund and any other fund/or funds created for specific purposes for registered dock workers.
- (l) borrowing or raising money and issuing debentures or other securities and, for the purpose of securing any debt or obligation, mortgaging or charging all or any part of the property of the Board.

(2) The income and property of the Board from whatever source derived shall be applied solely towards the objects of the Scheme including, health, safety, training and welfare measures for registered dock workers (including assistance by way of grant of loan or otherwise to co-operative societies formed for the exclusive benefit of dock workers and the staff of the Board) and no portion thereof shall be paid or transferred directly or indirectly by way of dividend, bonus or otherwise by way of benefit to the members of the Board; provided that nothing herein shall prevent the payment of reasonable and proper remuneration and expenses to any officer or servant of the Board or to any member of the Board in return for any service actually rendered to the Board, nor prevent the payment of interest at a reasonable rate on money lent or reasonable and proper rent for premises demised or let, by any member to the Board nor prevent the incurring of expenditure on welfare measures, if any, for the staff of the Board.

(3) The Board shall cause proper accounts to be kept of the cost of operating the Scheme and of all receipts and expenses under the Scheme.

(4) The Board shall submit to the Central Government—

- (i) as soon as may be after the first day of April in every year and not later than the thirty-first day October an annual report on the working of the Scheme during the preceding year ending the thirty-first day of March together with an audited balance sheet; and

- (ii) copies of proceedings of the meetings of the Board.

7. Responsibilities and duties of the Board in meeting.—The Board in meeting shall be responsible for dealing with all matters of policy and in particular may:—

- (a) fix the number of workers to be registered under various categories;
- (b) increase or decrease the number of workers in any category on the register from time to time as may be necessary after a periodical review of the registers and anticipated requirements;
- (c) sanction the temporary registration of a specific number of workers in any category for a specific period;
- (d) consider registration of new employers on the recommendation of the Chairman;
- (e) prescribe forms, records registers, statement and the like required to be maintained under the Scheme;
- (f) determine the wages, allowances and other conditions of service, and refix the guaranteed minimum wages in a month after annual review;
- (g) fix the rate of levy under clause 52(1);
- (h) fix the rate of contribution to be made by registered employers to the Dock Workers Welfare Fund and the Voluntary Retirement Fund;
- (i) appoint, abolish or reconstitute Committees under clause 36;
- (j) sanction the annual budget;
- (k) appoint the Personnel Officer;
- (l) subject to the provisions of clause 5 sanction creation of posts and make appointments to such posts;
- (m) make recommendations to the Central Government about changes in Scheme I;
- (n) make recommendations to the Central Government about any modifications in the Scheme;
- (o) endeavour to settle disputes about which a request for adjudication has been made to the Central Government by the parties concerned and report to the Government the results of such endeavours;
- (p) discuss statistics of output of labour and turn-round of ships and record its observations and directions;
- (q) sanction the opening of accounts in such scheduled Banks as it may direct and the operation of such accounts by such persons as the Board may from time to time direct; and
- (r) sanction and create fund or funds for specific purposes.

8. Annual Estimates.—The Chairman shall, at a special meeting to be held before the end of February in each year lay before the Board the annual budget as received from the Administrative Body under clause 11(i) of this Scheme, for the year commencing on the first day of April then next ensuing in such details and form as the Board may, from time to time, prescribe. The Board shall consider the estimate so presented to it and shall, within four weeks of its presentation, sanction the same either unaltered or subject to such alterations as it may deem fit.

9. Responsibilities and duties of Chairman.—(1) The Chairman shall have full administrative and executive powers to deal with all matters relating to the day-to-day administration of the Scheme and in particular:—

- (a) to ensure that the decisions of the Board in regard to the adjustment of the workers' registers are carried out expeditiously;
- (b) to ensure that the sanctions for temporary registration of workers are carried out without delay;
- (c) (i) to supervise and control the working of the Administrative Body;

- (u) to take suitable steps if any irregularities are detected by him or brought to his notice
- (d) to ensure in consultation with ship owners or shipping agents that proper and adequate supervision is provided by the registered employers over the workers employed on their ships,
- (e) to ensure that the provisions of the Scheme in regard to transfer and promotion of workers are carried out,
- (f) to constitute Medical Boards when required,
- (g) to ensure that conditions, laid down in the Scheme, for the registration of employers are complied with by them,
- (h) to ensure that all forms, registers, returns and documents, stated under the Scheme, are properly maintained,
- (i) to ensure that suitable statistics in regard to the output of labour and the turn round of ships are compiled and placed before the Board every quarter with appropriate remarks and explanations,
- (j) (i) to sanction the creation of posts the maximum salary of which exclusive of allowances is upto rupees one thousand per month,
- (ii) to make appointments to posts the maximum salary of which exclusive of allowances is upto rupees one thousand per month,
- (k) to take disciplinary action against workers and employers in accordance with the provisions of the Scheme.
- (l) to allow relaxation in the maximum number of shifts per worker per week or per month, and to report such cases to the Board,
- (m) to declare that there has been a 'go-slow' and to take action as authorised under the Scheme,
- (n) to declare a 'state of emergency' and to take action as authorised under the Scheme,
- (o) to make a report, when necessary, to the Central Government under rule 6 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962,
- (p) to sanction the transfer of a monthly worker to the reserve pool at the request of the employer or the worker, as provided for in the Scheme,
- (q) to deal with appeals from workers and employers under clauses 47 and 48,
- (r) to fill an unexpected vacancy in the post of Deputy Chairman for a period of less than one month and report such matter to the Central Government for approval, and
- (s) to discharge all other duties and responsibilities specifically vested in the Chairman under the Scheme

(2) The Chairman may subject to such conditions as he may think fit, delegate in writing to the Deputy Chairman any of the functions under sub clause (1) excepting those mentioned in items (j), (ju), (m), (n), (o), (q), (r) and (s) so however, such delegation shall not divest the Chairman of his powers

10 Responsibilities and duties of the Deputy Chairman—The Deputy Chairman shall be a whole time officer of the Board and shall assist the Chairman in the discharge of his functions and in particular shall—

- (a) discharge all functions relating to disciplinary action against registered employers and registered dock workers to the extent permitted under clause 44,
- (b) exercise such other functions as are delegated to him in writing by the Chairman,
- (c) function as Chairman of Committees of the Board of which he may be nominated as a member,
- (d) preside over the meetings of the Board in the absence of the Chairman, and

- (e) make appointments to the posts, the maximum salary of which exclusive of allowances is not more than seven hundred and fifty rupees per mensem

11 Functions of the Administrative Body—Without prejudice to the powers and functions of the Board, the Chairman and the Deputy Chairman the Administrative Body shall be responsible for the administration of the Scheme and shall in particular be responsible for—

- (a) keeping, adjusting and maintaining the employers' register, entering or reentering therein the name of any dock employer and where circumstances so require, removing from the register the name of any registered employer, either at his own request or in accordance with the provisions of the Scheme,
- (b) keeping, adjusting and maintaining from time to time such registers or records as may be necessary, of dock workers, including any registers or records of dock workers who are temporarily not available for dock work and whose absence has been approved by the Administrative Body and where circumstances so require removing from any register or record the name of any registered dock worker either at his own request or in accordance with the provisions of the Scheme,
- (c) the employment and control of registered dock workers available for work when they are not otherwise employed in accordance with the Scheme,
- (d) the grouping or regrouping of registered dock workers in accordance with the instruction received from the Board in such groups as may be determined by the Board,
- (e) the allocation of registered dock workers in the reserve pool who are available for work to registered employers and for this purpose, the Administrative Body shall—
 - (i) be deemed to act as an agent for the employer,
 - (ii) make the fullest possible use of registered dock workers in the reserve pool,
 - (iii) keep the record of attendance, at call stands or control points of registered dock workers,
 - (iv) provide for the maintenance of records of employment and earnings
 - (v) subject to the allotment of work by rotation under clause 29(3), allocate workers in accordance with clause 19 and 30, and
 - (vi) make necessary entries in the Attendance Card and Wage slip of workers in the reserve pool as laid down in clause 27,
- (f) (i) the collection of levy, contribution to the Dock Workers' Welfare Fund or any other contribution from the employers as may be specified under the Scheme,
- (ii) the collection of workers' contribution to the Provident Fund Insurance Fund or any other fund which may be constituted under the Scheme,
- (iii) the payment as agent of the registered employer to each daily worker of all earnings properly due to the worker from the employer and the payment to such workers of all monies payable by the Board to those workers in accordance with the provisions of the Scheme
- (g) appointing subject to budget provision such officers and servants from time to time as may be necessary,

Provided that the creation of posts the maximum salary of which exclusive of allowances is above rupees five hundred and seventy five per month and appointment of persons to such posts shall be subject to clauses 6(1) and 9(1)(i)

- (h) the keeping of proper accounts of the cost of operating the Scheme and of all receipts and expenses under it, and making and submitting to the Board and annual report and audited balance sheet,

- (i) the framing of the Budget annually, submitting the same to the Board on or before the 15th day of February in each year and getting it approved by the Board;
- (j) maintaining complete service records of all registered dock workers; and
- (k) such other functions as may from time to time, subject to the provisions of the Scheme, be assigned to it by Board, the Chairman or the Deputy Chairman.

12. Labour Officer.—The Administrative Body when it consists of employers of dock workers shall appoint a Labour Officer or Labour Officers with the approval of the Board. The Labour Officer shall, under the supervision and control of the Administrative Body, carry out such functions as may be assigned to him by that Body consistent with the provisions of the Scheme.

13. Functions of the Personnel Officer.—The Personnel Officer shall assist the Deputy Chairman generally in the discharge of his duties and shall in particular carry out the functions vested in him under clause 44 of the Scheme.

14. Officers appointed by the Central Government for proper working of the Scheme.—(1) Notwithstanding the provisions of Clauses 4, 5, 11 and 13, the Central Government may in its discretion appoint, from time to time, in consultation with the Chairman of the Board one or more officer and entrust to such officer or officers such functions as it may deem fit for the proper working of the Scheme.

(2) The officer or officers appointed under sub-clause (1) shall be subject to the general supervision and control of the Chairman and be paid from the funds of the Board. Such officer or officers shall hold office for such period and on such terms and conditions as the Central Government may determine.

15. Maintenance of Registers, etc.—(1) Employers' Register:

- (a) There shall be a register of employers.
- (b) In so far as the application of the Scheme to foodgrain handling workers is concerned, every employer who on the date of commencement of the Scheme is listed under the Bombay Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1957 shall be deemed to have been registered under the Scheme.
- (c) Persons other than those who are deemed to have been registered under item (b) shall not be registered as foodgrain handling employers unless the Board considers it expedient and necessary to do so, and in no case shall a person be registered until he has been licensed in that behalf by the Bombay Port Trust.
- (d) The Board may, subject to such conditions as it may with the previous approval of the Central Government prescribe in this behalf, permit persons registered under item (b) and (c), to form one or more groups, and each group so formed shall be treated as one employer only for employment of monthly workers;

Provided that the Board shall have power to make with the previous approval of the Central Government such alterations or modifications in the conditions prescribed, as it may deem necessary from time to time.

Provided further that the Board may revoke, from such date as it may specify, the permission given to any group of employers, if after giving an opportunity to the group of employers to show cause against the proposal and after considering its representations, if any, the Board is satisfied that the group of employers has failed to comply, in part or in full with the conditions specified for the formation of such groups and thereupon the said group shall stand dissolved from such date.

(2) Workers' Registers.—(a) The workers' registers shall be maintained in the forms specified by the Board for this purpose.

(b) The registers of foodgrain handling workers shall be as under, namely:

- (i) Monthly Register—Register of workers who are engaged by each foodgrain handling employer on contract on monthly basis and who are known as monthly workers.
- (ii) Reserve Pool Register—Register of workers other than those on the monthly register and known as Reserve Pool Workers. This register shall include a sub-pool of foodgrain workers to fill casual vacancies in categories. The workers included in such a sub-pool shall be known as leave reserve workers.

16. Classification of workers in Registers.—(1) The Board shall arrange for the classification of workers by categories in the registers.

(2) Dock workers registered under the Scheme shall be classified into:

- (a) Mukadams;
- (b) Loaders;
- (c) Fillers;
- (d) Stitchers;
- (e) Palawallas;
- (f) Dock Mazdoors;
- (g) Machine Mazdoors;
- (h) Tank Mazdoors.

17. Fixation of number of workers on the register.—(1) The Board shall in consultation with the Administrative Body and with the previous approval of the Central Government determine, before the commencement of registration in any category, the number of workers required in that category.

(2) The Board shall in consultation with the Administrative Body and subject to the approval of the Central Government periodically determine the number of workers required in each category and arrange to adjust the workers' registers accordingly.

(3) A registered employer or a group of employers may, subject to such conditions as may be specified by the Board in this behalf, increase the number of workers on the monthly registers by selecting workers from the reserve pool.

18. Registration of existing and new workers.—(1) (a) Any dock worker who, on the date of commencement of the Scheme, is already listed under the Bombay Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1957 shall be deemed to have been registered under this Scheme.

(b) The qualification for new registration shall be such age as may be prescribed by the Board having regard to the local conditions but not exceeding 40 years. Only Indian nationals who are physically fit, capable and having experience shall be eligible for registration.

Provided that in the case of ex-service personnel the age limit may be relaxed up to 45 years by the Dock Labour Board.

(c) Registration of workers in any new category shall be done from among workers who have been or were working in the Port on any such date as the Board may specify in this behalf and selection for registration shall be made as far as possible on the basis of seniority, as determined by the length of service rendered by a worker in that category and notified by the Board. In cases where the said seniority list is not available, selection shall be made on such other basis as the Board may determine, provided that the worker is medically fit and is not more than 40 years of age.

(2) The Board may from time to time permit the registration of workers temporarily for such period and on such terms and conditions of service as the Board may specify:

Provided that the workers registered temporarily shall be entitled to attendance allowance under clause 32 and shall have the same obligations as registered dock workers in the reserve pool.

(3) Any fresh recruitment, whether on a temporary or permanent basis in any category in which dock workers have already been registered under the Scheme shall be done from amongst workers registered with the local Employment Exchange. If, however, the requirement exceeds the number of suitable men available on the register of the Employment Exchange on the day of the requisition, direct recruitment after absorbing suitable men from the Employment Exchange register may be made.

(4) New Workers registered under item (b) of sub-clause (1) will be on probation for a period of three months before being placed on a permanent basis on the registers.

(5) Notwithstanding any other provision of the Scheme, where the Board is of opinion that a dock worker has secured his registration by furnishing false information in his application or by withholding any information required therein, or where it appears that a worker has been registered improperly or incorrectly, the Board in meeting may direct the removal of his name from the registers:

Provided that before giving such direction, the Board shall give him an opportunity of showing cause why the proposed direction should not be issued.

(6) The following principles shall apply in respect of registration in other categories which may after the commencement of the Scheme, be included in Schedule I—

- (a) Before a worker is registered in any of the above categories, the Board shall under clause 17(1) make a thorough investigation with a view to arriving at an estimate of the number of workers in that category that are likely to be required out of all the bona fide workers in that category who may then be working in the docks.
- (b) There shall be a provisional registration based on the anticipated requirements and the mere fact that a worker has been working before in the port shall not automatically entitle him to registration.
- (c) After the provisional registration has been completed, the booking in rotation shall start without allowing, at that stage any financial benefits other than wage which accrue to registered workers under the scheme.
- (d) A reassessment of the requirement shall be made after six months in the light of the actual employment obtained by workers provisionally registered and the provisional registration shall then be adjusted accordingly. The payment of attendance allowance under clause 32 only shall commence from that time.
- (e) The working under these conditions shall be examined after a year of introduction of the rotational booking with a view to fixing the number of days for which the guaranteed minimum wages under clause 31 should be paid.

From then onwards the workers shall be entitled to all the benefits under the scheme.

- (f) The minimum number of days in a month for which wages are guaranteed under clause 31 to categories of workers previously registered shall not automatically be claimed by workers of the categories to be registered after the date of enforcement of the Scheme.

Such minimum number of days may vary from category to category as determined under item (e) above.

- (g) The wages of the workers in categories which may be registered after the enforcement of the Scheme, shall be such as may be fixed by the Board from time to time.

AGE OF RETIREMENT :

19. Promotion and transfer of workers.—(1) The age of retirement under the scheme shall be 58 years.

Provided that where the existing age of retirement for any category of workers is 60 years that practice shall continue for the present incumbents.

(2) A vacancy, other than a casual vacancy, in any category of dock workers in a reserve pool register shall ordinarily be filled by promotion of a worker from the next lower category.

(3) A vacancy other than a casual vacancy, in any category of monthly workers may be filled only by promotion from lower categories of monthly workers of the same employer or group of employers, or, if no person is suitable for promotion from lower categories of monthly workers of the same employer or group of employers, by transfer of a dock worker in the same or a superior category from the reserve pool who may be selected by a registered employer or a group of employers.

Explanation.—The criteria for promotion shall ordinarily be :—

- (a) seniority,
- (b) merit and fitness for work in the category to which promotion is to be made, and
- (c) record of past service.

NOTE :—A transfer from the reserve pool register to the monthly register in the same category or vice versa shall not be deemed to be a promotion.

(4) The Chairman or the Deputy Chairman may for sufficient and valid reasons allow the transfer of a monthly worker to the reserve pool on a request in writing of the employer or the worker explaining fully the reasons for the transfer provided that such transfer shall be subject to the fulfilment of any contract subsisting between the monthly worker and his employer regarding termination of employment. No transfer shall take place without the prior approval of the Chairman or the Deputy Chairman.

(5) If the services of a monthly worker are terminated by any employer for an act of indiscipline or misconduct, he may apply to the Board for employment in the reserve pool. The Deputy Chairman on behalf of the Board shall then decide on the merits of the case whether or not the worker should be employed and if so, whether in the same or a lower category.

(6) If a monthly worker is transferred to or employed in the reserve pool under sub-clause (3) or sub-clause (4), as the case may be, his previous service shall be reckoned for all benefits in the reserve pool and the employer shall transfer to the Board all benefits that have accrued to the worker in respect of his previous service as if such service had not been transferred. The employer shall in particular contribute to the Board such amount as may be appropriate towards the worker's leave, Provident Fund or gratuity that may be due to him on the date of such transfer.

20. Medical Examination.—(1) A new worker before registration shall undergo, free of charge, a medical examination for physical fitness by a Medical Officer, nominated, by the Chairman for this purpose. A worker found medically unfit by a Medical Officer may apply in writing to the Chairman for examination by a Medical Board. On receipt of such a request, the Chairman shall set up a Medical Board. The decision of the Medical Board shall be final and a worker who is medically unfit shall not be entitled to registration.

(2) If the Administrative Body deems it necessary, a worker shall undergo free of charge, a medical examination by a Medical Board to be constituted by the Chairman. The decision of the Medical Board shall be final. If a worker is found permanently unfit by the Medical Board the Chairman shall terminate his services forthwith.

21. Facilities for training.—The Board shall make such provision for training of dock workers as it may deem necessary.

22. Registration fee.—A registration fee of rupees two shall be payable to the Board by each worker at the time of registration under the Scheme.

23. Supply of cards.—(1) Every registered worker shall be supplied free of cost with an Identity Card, an Attendance Card and Wage slips in the forms specified by the Board.

(2) In case of loss of a card, a fresh card shall be issued but the cost thereof which will be fixed by the Board, shall be payable by the worker concerned.

24. "Service Records" for registered workers.—A "Service Record" for every monthly and daily worker shall be maintained by the Administrative Body in a form, to be specified by the Board which shall contain, among other things, a complete record of disciplinary actions taken against the worker, promotions, commendations for good work and other matters. Such details in respect of monthly workers shall be supplied to the Administrative Body by the registered employers.

25. "Record Sheets" for registered employers.—The Personnel Officer shall maintain a "Record Sheet" in respect of each registered employer in a form to be specified by the Board which shall contain, among other things, a complete record of disciplinary actions taken against the registered employer.

26. Surrender of cards.—A worker's card shall be surrendered to the Administrative Body in the following circumstances, namely :—

- (a) when proceeding on leave for three days or more;
- (b) when retiring from service;
- (c) when dismissed or discharged from service;
- (d) when temporarily suspended; or
- (e) on death.

Provided that the employer of a monthly worker will also surrender the card of the worker to the Administrative Body in circumstances specified at item (a) to (e).

27. Entries in Attendance Card and Wage Slip.—(1) A registered dock worker in the reserve pool shall hand over to the Administrative Body at the time he is allocated for work to a registered employer his Attendance Card. The Administrative Body shall make necessary entries in the Attendance Card in respect of the period of work done by the worker and return it to him before the expiry of his engagement. For each day of work, the Administrative Body shall supply as soon as possible a wage slip showing the wages earned by a worker.

(2) A monthly worker shall hand over to his employer at the time he is allotted work on a ship his Attendance Card. The said employer shall make necessary entries in the card in respect of the period of work done by the worker and return it to him before the conclusion of his allotted work. For each day of work, the employer shall supply as soon as possible a wage slip showing the wages earned by a worker.

28. Employment of workers.—(1) A monthly worker of a particular category attached to a registered employer or a group of employers shall be entitled to be employed for work in that category by that employer or group of employers, in preference to any worker of the same category in the reserve pool.

(2) If the number of workers on the monthly register in a particular category is not sufficient for the work available, the workers on the reserve pool register in that category shall be employed.

(3) A monthly worker of one employer or a group of employers shall not be employed by another employer or group

of employers except with the previous approval of the Chairman or the Deputy Chairman.

29. Employment in shifts.—(1) Dock workers shall be employed in shifts.

(2) (a) A dock worker shall not ordinarily be employed in two consecutive shifts on each of the two successive days. In no case shall a dock worker be employed in three consecutive shifts.

(b) A dock worker in the reserve pool shall not be employed for more than 9 shifts a week or 33 shifts in a month.

(c) Normally a monthly worker shall not be employed for more than 6 shifts in a week or 27 shifts in a month, but when a worker in the reserve pool who has not reached the maximum limit of employment defined in item (b) is not available, a monthly worker may be employed upto 9 shifts in a week or 33 shifts in a month.

(d) In special circumstances, the Chairman may relax temporarily the restrictions under items (b) and (c) to the extent necessary.

(e) Workers working more than one shift in a day will be entitled to the normal rate of wages for work in each shift.

(3) Workers of each category on the reserve pool register shall be allotted work by rotation.

(4) Where work is carried on by a gang, the allotment of workers by rotation shall be by gangs.

30. Filling up of casual vacancies.—(1) Casual vacancies in monthly gangs shall be filled up in the following manner, namely :—

(i) When a Mukadam is absent, the vacancy shall be filled by a Loader in the employment of the employer, provided such Mukadam is not allocated to any other job. If no such Mukadam is available the seniormost foodgrain handling worker in the same gang available for work shall work as a Mukadam for the shift.

(ii) Vacancies of foodgrain handling mazdoors shall be filled by foodgrain handling mazdoors in the employment of the employer, provided such mazdoors are not allocated to any other job. When no such workers are available, the vacancies shall be filled by workers of the same category from the reserve pool.

(2) Casual vacancies in the reserve pool gangs shall be filled up in the following manner, namely :—

(a) When a Mukadam is absent, the vacancy shall be filled by a Mukadam on attendance allowance. If no Mukadam is on attendance allowance, the senior-most foodgrain handling mazdoor in the same gang available for work shall work as a Mukadam.

(b) Vacancies of foodgrain handling mazdoors shall be filled by foodgrain handling mazdoors on attendance allowance, or by leave reserve workers if any.

(c) In filling up vacancies otherwise than by promotion in the same gang, the principle of rotation shall be followed: Provided that where work is carried on by a gang, the allotment of workers by rotation shall be by gangs.

31. Guaranteed Minimum Wages in a month.—(1) A worker in the reserve pool register shall be paid wages at least for twelve days in a month at the wage rate, inclusive of dearness allowance as specified by the Board appropriate to the category to which he permanently belongs, even though no work is found for him for the minimum number of twelve days in a month. The days on which work is allotted to the worker shall be counted towards the twelve days mentioned above. The guaranteed minimum wages in a month shall be :

- (a) for the number of days for which the wages are guaranteed in a month subject to the condition that the worker attended for work on all days of the month as directed by the Administrative Body; or
- (b) proportionate to the number of days on which the worker attended for work provided he was excused from attendance on all the remaining days of the month.

(2) Subject to the provisions of sub-clause (1), the minimum number of days in a month for which wages are guaranteed may be fixed by the Board for each year on the basis of the monthly average employment obtained by the workers in the reserve pool in the lowest categories of foodgrain handling workers during the preceding year: Provided that—

- (i) the number so fixed shall not in any case be more than 21 and not less than 12;
- (ii) the workers already listed under the Bombay Un-registered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1957, shall continue to be eligible for the same minimum guaranteed wages as admissible to them before the commencement of the Scheme.

NOTE :—The method of assessing the average employment is detailed in Schedule II.

(3) The minimum number of days for which wages shall be guaranteed under sub-clauses (1) and (2) shall not automatically apply to workers in new categories that may be registered after the date of enforcement of the Scheme. The minimum number of days for which wages shall be guaranteed to these categories shall be determined under clause 18(6)(e). The annual refixation of the minimum number of days as under sub-clause (2) shall be done independently in their case also.

Explanation :—For the purpose of this clause,

- (a) 'day' shall mean a shift; and
- (b) 'month' shall not include the days of weekly off.

32. Attendance Allowance: Subject to the other provisions of the Scheme, a worker on the reserve pool register who is available for work but for whom no work is found shall be paid attendance allowance exclusive of dearness allowance at the rate of rupee per day for the days on which during a calendar month he attended for work as directed by the Administrative Body and no work was found for him:

Provided that the Board may allow payment of attendance allowance exclusive of dearness allowance at such higher rate not exceeding rupees two as it may deem necessary:

Provided further that no attendance allowance shall be payable for any day for which full wages, inclusive of dearness allowance, have been paid under clause 31 or otherwise or under clause 34.

33. Employment for a shift: No worker in the reserve pool register shall be employed for a period of less than a shift and where the work for which a worker has been engaged is completed during the working period of the shift he shall undertake such other work in or at the same or another vessel or berth as may be required by the same

employer for the remainder of the period and if no such other work is made available to him, he shall be paid for the entire shift:

Provided that if he is subject to piece-rate wages or incentive wages under any agreement entered into between the registered employers and registered dock workers or any decision of the Board he shall be paid at the rates laid down therein.

34. Payment of wages when work is not made available after engagement. When a worker in the reserve pool presents himself for work and for any reason the work for which he has attended cannot commence or proceed and no alternative work can be found for him he shall be entitled to daily wage rate appropriate to the category to which he belongs inclusive of any allowance, provided he continues to be available throughout the remainder of the shift and accepts such alternative employment as may be offered to him by the Administrative Body;

Provided that in the case of a worker who is subject to the piece rate system of wages under the Award, the payment, if any, due to him under this clause, shall be reduced by the amount of idle time payment made, if any in respect of the same period.

35. Holidays.—Each dock worker shall be entitled in a year to such number of holidays with pay and at such rates as may be prescribed by the Board under clause 41. Any payment made under this clause shall be exclusive of the payment calculated under clause 31.

36. Committees.—The Board may appoint one or more committees to whom it may entrust such of its functions as it may deem necessary to facilitate compliance with the provisions of the Scheme and may abolish or reconstitute them as it may deem necessary. Persons who are not members of the Board may, if necessary, be nominated as co-opted members of a committee. Such co-opted members, however, shall not have any right to vote.

37. Obligations of registered dock workers.—(1) Every registered dock worker shall be deemed to have accepted the obligations of the Scheme.

(2) A registered dock worker in the reserve pool who is available for work shall be deemed to be in the employment of the Board.

(3) A registered dock worker in the reserve pool who is available for work shall not engage himself for employment under a registered employer unless he is allocated to that employer by the Administrative Body.

(4) A registered dock worker in the reserve pool who is available for work shall carry out the directions of the Administrative Body and shall,—

(a) report at such call stands or control points and at such times as may be specified by the Administrative Body and shall remain at such call stands or control points :—

(i) throughout the period of the shift, if instructed by the Administrative Body to that effect, on payment of such retention allowance as may be specified by the Board; or

(ii) for such period, not exceeding one hour, as may be specified; and

(b) accept any employment in connection with dock work, whether in the category in which he has been registered or in any other category registered in other schemes administered by the Board for which he is considered suitable temporarily or permanently.

(5) A registered dock worker who is available for work when allocated by the Administrative Body for employment under a registered employer shall carry out his duties in accordance with the directions of such registered employer or his authorised representative or supervisor and the rules of the port or place where he is working.

38. Obligations of registered employers.—(1) Every registered employer shall accept the obligations of the Scheme.

(2) Subject to the provisions of clause 28, a registered employer shall not employ a worker other than a dock worker who has been allocated to him by the Administrative Body in accordance with the provisions of clause 11(e).

(3) A registered employer shall in accordance with arrangements made by the Administrative Body submit all available information of his current and future labour requirements.

(4) A registered employer shall lodge with the Administrative Body, unless otherwise directed, particulars of work done by dock workers on time-rate or piece-rate and such other statistical data as may be required in respect of the dock workers engaged by him.

(5) (i) A registered employer shall pay to the Administrative Body in such manner and at such times as the Board may direct the levy payable under clause 52(1) and the gross wages due to daily workers.

(ii) A registered employer shall make payments as contributions to the Dock Workers Welfare Fund under clause 54.

(6) A registered employer shall keep such records as the Board may require, and shall produce to the Board or to such persons as may be designated by the Board upon reasonable notice all such records and any other documents of any kind relating to registered dock workers and to the work upon which they have been employed and furnish such information relating thereto as may be set out in any notice or direction issued by or on behalf of the Board.

39. Restriction on employment—(1) No person other than a registered employer shall employ any worker on dock work nor shall a registered employer engage, for employment or employ a worker on dock work unless that worker is a registered dock worker.

(2) Notwithstanding the foregoing provisions of this clause :—

(a) Where the Administrative Body is satisfied that—

- (i) dock work is emergently required to be done ; and
- (ii) It is not reasonably practicable to obtain a registered dock worker for that work ;

the Administrative Body may, subject to any limitations imposed by the Board, allocate to a registered employer a person who is not a registered dock worker. In selecting such workers the local Employment Exchange organisation shall, as far as possible, be consulted :

Provided that, whenever, unregistered workers have to be employed, the Administrative Body shall obtain, if possible, the prior approval of the Chairman to the employment of such workers, and where this is not possible, shall report to the Chairman within 24 hours the full circumstances under which such workers were employed and the Chairman shall duly inform the Board of such employment at the next meeting ;

(b) the Board may, subject to such conditions as it may specify, permit employment of unregistered workers on a holiday, if dock work is required to be done on that day, to the extent registered workers are not available for work;

(c) in the case referred to in items (a) and (b) the person so employed as aforesaid by a registered employer shall, for the purposes of clause 38 (4), (5) and (6) and clause-41 be treated in respect of that dock work as if he were a daily worker.

(3) A registered worker in the reserve pool may, provided he fulfils fully his obligations under clause 37, take up occasional employment under employers other than those registered under the scheme on those days on which he is not allocated for work by the Administrative Body.

40. Circumstances in which the Scheme ceases to apply:

(1) The Scheme shall cease to apply to a registered dock worker when his name has been removed from the register or record in accordance with the provisions of the Scheme.

(2) The Scheme shall cease to apply to a registered employer when his name has been removed from the employer's register in accordance with the provisions of the Scheme.

(3) Nothing in this clause shall affect any obligation incurred or right accrued during any time when the person was a registered dock worker or a registered employer.

41. Wages, allowances and other conditions of service of workers.—Without prejudice to the provisions of any agreement entered into between the registered employers and registered dock workers it shall be, unless otherwise specifically provided for in the Scheme, an implied condition of the contract between a registered dock worker (whether in the reserve pool or on the monthly register) and registered employer that—

(a) The rates of wages, allowances and overtime, hours of work, rest intervals, holidays, and pay in respect thereof and other conditions of service shall be such as may be specified by the Board for each category of workers; and

(b) the fixation of wage period, time for payment of wages and deductions from wages shall be in accordance with the provisions of the Payment of Wages, Act, 1936 (4 of 1936).

42. Pay in respect of unemployment or under-employment of arrears of Dearness allowance, wages and other allowances.—(1) Subject to the conditions set out in this clause and clause 43 when in any wage period, a registered dock worker in the reserve pool is available for work but is not given employment or full employment, he shall be entitled to receive from the Board such amounts as may be admissible to him under clauses 31, 32 and 34.

(2) The conditions subject to which a registered dock worker is entitled to the said payment, if any, from the Board are that—

(a) he attended as directed at the call stands or control points; and

(b) his attendance was recorded.

(3) In case of any revision of dearness allowance or grant of revised wages or other allowances, with retrospective effect, in pursuance of any agreement entered into between the registered employers and registered dock workers or any decision of the Board or recommendation of any Board or body set up or of any order made, by the Central Government, the Board may, out of its funds, pay the registered workers arrears upto the date of the agreement entered into between the registered employers and registered dock workers or any decision of the Board or, as the case may be of the recommendation or order, if the Board so decides.

43. Disentitlement to payment.—(1) A registered dock worker who while in the reserve pool fails without adequate cause to comply with the provisions of clause 37 (4) (a) or (b), or fails to comply with any lawful order given to him by or on behalf of the Board, may be proceeded with in accordance with sub-clause (3).

(2) A registered dock worker in the reserve pool, who, while in employment to which he has been allocated by the Administrative Body, fails without any adequate cause to comply with the provisions of clause 37(5) or fails to comply with any lawful orders given to him by his employer, may have his engagement terminated and may be returned to the reserve pool and whether or not he is so returned may be reported in writing to the Labour Officer. When a registered dock worker is so returned to the reserve pool, the Administrative Body shall endorse his Attendance Card accordingly.

(3) The Labour Officer shall consider any matter arising under sub-clause (1) or (2) and if, after investigating the

matter, he notifies the registered dock worker that he is satisfied that the registered dock workers has failed to comply with a lawful order as aforesaid, the registered dock worker shall not be entitled to any payment, or to such part of any payment under clause 42 as the Labour Officer thinks fit in respect of the wage period in which such failure occurred or continues.

44. Disciplinary Procedure.—(1) (i) The Personnel Officer on receipt of the information whether on a complaint or otherwise, that a registered employer has failed to carry out the provisions of the Scheme may after investigating the matter, give him a warning in writing, or

(ii) Where in his opinion, a higher penalty is merited, he shall report the case to the Deputy Chairman, who may then cause such further investigation to be made as he may deem fit and take any of the following steps as regards that employer, that is to say, he may—

- (a) censure him and record the censure in his record sheet; or
- (b) subject to the approval of the Board and after one month's notice in writing given to the registered employer inform the Administrative Body that the name of the employer shall be removed from the employers' register for such period as determined by the Board or permanently in case of a grave offence.

(2) A registered dock worker in the reserve pool, who fails to comply with any of the provisions of the Scheme, or commits any act of indiscipline or misconduct, may be reported in writing to the Labour Officer who may after investigating the matter take any of the following steps as regards that worker, that is to say, he may—

- (a) determine that, for such period as he thinks proper, that worker shall not be entitled to any payment or part payment under clause 42;
- (b) give him a warning in writing ; or
- (c) suspend him without pay for a period not exceeding three days.

(3) (a) Where in a case reported to the Labour Officer under sub-clause (2) he is of the opinion that the act of indiscipline or misconduct is so serious that the dock worker should not be allowed to work any longer, the Labour Officer may, pending investigation of the matter, suspend the worker and report immediately to the Deputy Chairman, who after preliminary investigation of the matter shall pass orders thereon whether the worker should, pending final orders, remain suspended or not;

(b) Where a dock worker has been suspended by an order under item (a), he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance equivalent to one-half of the basic wages dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances ;

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the worker, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.

(c) The subsistence allowance so paid shall not be recoverable or liable to forfeiture in any case whatsoever ;

(d) Where a dock worker is found not guilty he shall be entitled to such payments as the Administrative Body certifies that the worker would have received on the time-rate basis or under clause 32 had he not been suspended, provided that the amounts so payable shall be reduced by the amount of subsistence allowance payable or already paid during a particular period,

(4) Where, in the opinion of the Labour Officer a higher punishment than that provided in sub-clauses (2) and (3) is merited, he shall report the case to the Deputy Chairman.

(5) On receipt of the written report from the Labour Officer under sub-clause (4) or from the employers or any other person that a registered dock worker in the reserve pool has failed to comply with any of the provisions of the Scheme or has committed an act of indiscipline or misconduct or has consistently failed to produce the standard or detum output or has been inefficient in any other manner, the Deputy Chairman may make or cause to be made such further investigation as he may deem fit, and thereafter take any of the following steps, as regards the worker concerned, that is to say, he may impose any of the following penalties :—

- (a) determine that for such period as he thinks proper, the worker shall not be entitled to any payment or part payment under clause 42;
- (b) give him a warning in writing;
- (c) suspend him without pay for a period not exceeding three months;
- (d) terminate his services after giving 14 days' notice or 14 days' wages inclusive of dearness allowance in lieu thereof; or
- (e) dismiss him.

(6) Before any action is taken under this clause the person concerned shall be given an opportunity to show cause why the proposed action should not be taken against him, and such person may, if he so desires, adduce evidence in respect of such action.

(7) The Administrative Body shall be informed simultaneously about the action taken under this clause.

(8) Notwithstanding anything contained in this clause and in clause 43, the powers vested in the authority specified in column (1) of the Table below under the provisions specified in column (2) of the said Table, shall also be exercisable by the authority specified in the corresponding entry in column (3) of the said table in such cases as the last named authority may specify in writing in this behalf.

TABLE

Authority empowered to take action.	Power given under	Authority empowered to take action in ecified cases.
1	2	3
1. Labour Officer	Clauses 43 and 44	Administrative Body
2. Personnel Officer	Clause 44	Deputy Chairman or Chairman
3. Deputy Chairman	Clause 44	Chairman.

(9) Without prejudice to the powers of the Chairman under clauses 45 and 51, a registered dock employer shall have full powers to take disciplinary action against monthly workers employed under him.

45. Special Disciplinary powers of Chairman.—(1) Notwithstanding anything contained in the Scheme, if the Chairman is satisfied that a 'go-slow' has been resorted to by any gang of registered dock workers or by any such individual worker and is being continued or repeated by the same gang of workers, or workers of different gangs or workers on the same or different ships, he may make a declaration in writing to that effect.

(2) When a declaration under sub-clause (1) has been made, it shall be lawful for the Chairman—

(i) in the case of monthly workers, to take, without prejudice to the rights of the registered employers, such disciplinary action including dismissal, against such workers, as he may consider appropriate; and

(ii) in the case of registered dock workers in the reserve pool to take such disciplinary action including dismissal against such worker, as he may consider appropriate and also to order forfeiture of their guaranteed minimum wages and attendance allowance for the wage period or periods in which the 'go-slow' has been resorted to.

(3) The Chairman may take disciplinary action—

(i) Where the 'go-slow' is resorted to by a gang, against all the members of the gang; and

(ii) where the 'go-slow' is resorted to by a worker, against the worker concerned.

(4) Before any disciplinary action is taken under this clause against any dock worker or gang of dock workers such worker or gang shall be given an opportunity to show cause why the proposed action should not be taken against him or it:

Provided that the Chairman may, before giving an opportunity to show cause under this sub-clause suspend from work any worker or gang of workers immediately after a declaration has been made under sub-clause (1).

(5) (a) Where a worker has been suspended pending enquiry, he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance equivalent to one half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances:

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the worker, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.

(b) the subsistence allowance so paid shall not be recoverable or liable to forfeiture in any case whatsoever;

(c) where a dock worker is found not guilty, he shall be entitled to such payments in respect of the period of his suspension as the Administrative Body may certify that the worker would have received on the time rate basis or under clause 32 had he not been suspended; provided that the amounts so payable shall be reduced by the amount of subsistence allowance already paid during that period.

(6) Any registered dock worker who is aggrieved by an order of the Chairman under sub-clause (2) may, within 30 days of the date of receipt of the order, prefer an appeal to the Central Government.

46. Termination of employment.—(1) The employment of a registered dock worker in the reserve pool shall not be terminated except in accordance with the provisions of the Scheme.

(2) A registered dock worker in the reserve pool shall not leave his employment with the Board except by giving fourteen days' notice in writing to the Board or forfeiting fourteen days' wages inclusive of dearness allowance in lieu thereof.

(3) When the employment of a registered dock worker with the Board has been terminated under sub-clause (1) or (2) above, his name shall forthwith be removed from the register or record by the Administrative Body.

47. Appeals by workers.—(1) Save as otherwise provided in this clause, a worker in the reserve pool who is aggrieved

by an order passed by an authority specified in column (1) of the table below under the provisions specified in column (2) of the said Table may prefer an appeal against such order to the authority specified in column (3) of the said Table.

TABLE

Authority passing order	Order made under	Appellate Authority
1	2	3
Labour officer or Administrative Body	Clause 43 or 44	Deputy Chairman
Deputy Chairman	Clause 44	Chairman
Chairman	Clause 44	Central Government

(2) A worker who is aggrieved by an order—

(i) placing him in a particular group in the register or record; or

(ii) refusing registration under clause 18; or

(iii) requiring him under clause 37 (4) (b) to undertake any work which is not the same category to which he belongs,

may prefer an appeal to the Chairman.

(3) Any dock worker who is aggrieved by an order under clause 19(4) may prefer an appeal to the Chairman.

(4) No appeal shall lie where due notice has been given of the removal of the name of a registered worker from the register or record in accordance with the instructions of the Board, if the ground of removal is that the registered dock worker falls within a class or description of dock workers whose names are to be removed from the register or record in order to reduce the size thereof:

Provided that an appeal shall lie to the Chairman where the registered dock worker alleges that he does not belong to the class or description of dock workers referred to in the instructions of the Board.

(5) Every appeal referred to in sub-clauses (1), (2), (3) and (4) shall be in writing and preferred within 14 days of receipt of the order appealed against:

Provided that the appellate authority may for reasons to be recorded, admit an appeal preferred after the expiry of 14 days.

(6) The appellate authority may after giving an opportunity to the appellant to be heard, if he so desires, and reasons to be recorded in writing, pass such order as it thinks fit.

(7) Every order passed under sub-clause (6) shall be communicated to the appellant.

(8) An appellant shall not be entitled to be represented by a legal practitioner before the appellate authority but he shall be entitled to be represented by a representative of the registered trade union of which he is a member or by a registered dock worker.

48. Appeals by employers.—(1) (a) A registered employer who is aggrieved by an order of the Personnel Officer under clause 44(1)(i) may appeal to the Deputy Chairman, who shall decide the same.

(b) If a registered employer is aggrieved by an original order of the Deputy Chairman under clause 44(1)(ii), he may

appeal to the Chairman, who shall decide the same. In the case of an appeal against an order under clause 44(1)(ii)(b) the Chairman shall as the case may be, had passed the order, for the purpose of satisfying himself forthwith refer the matter to the Central Government. The Central Government shall make such an order on the appeal as it thinks fit.

(2) An employer who has been refused registration under clause 15(1)(c) may appeal to the Central Government through the Chairman. The Central Government shall make such order on the appeal as it thinks fit.

(3) If a registered employer is aggrieved by any original order of the Chairman against him under clause 44, he may prefer an appeal to the Central Government. The Central Government shall make such order on the appeal as it thinks fit.

(4) Every appeal referred to in sub-clauses (1), (2) and (3) shall be in writing and preferred within 14 days of the receipt of the order appealed against.

Provided that the appellate authority may, for reasons to be recorded, admit an appeal preferred after the expiry of 14 days.

(5) An appellant shall not be entitled to be represented by a legal practitioner before the appellate authority but he shall be entitled to be represented by a representative of the association of registered employers of which he is a member or by a registered employer.

49 Power of revision of the Chairman and Deputy Chairman.—Notwithstanding anything contained in the Scheme, the Chairman, in the case of an order passed by the Deputy Chairman under clause 44, or the Deputy Chairman, in the case of an order passed by the Personnel Officer or the Labour Officer, as the case may be, under the said clause, may, at any time, call for the record of any proceeding in which the Deputy Chairman or the Personnel Officer or the Labour Officer, as the case may be, had passed the order, for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety thereof and may pass such order in relation thereto as he may think fit.

Provided that the Chairman or the Deputy Chairman shall not pass any order under this clause which may prejudicially affect the interest of any person without giving such person a reasonable opportunity of being heard.

50 Stay of order in case of certain appeals.—Where an appeal is lodged by a dock worker in accordance with the provisions of clause 47 against an order of termination of service on 14 days' notice or where an appeal is lodged by an employer in accordance with the provisions of Clause 48 against an order removing his name from the employer's register under clause 44(1)(ii)(b), the appellate authority may suspend the operation of the order appealed from pending the hearing and disposal of the appeal.

51 Special provisions for action in an emergency.—(1) If at any time the Chairman is satisfied that an emergency has arisen which will seriously affect the working of the port, he may, by order in writing and for such period as he may from time to time specify therein, make a declaration to that effect.

Provided that no such declaration shall be made except with the previous approval of the Central Government.

(2) So long as an order under sub-clause (1) is in force, the following provisions shall apply, namely—

(i) if any allegation is made that a registered employer has failed to carry out the provisions of the Scheme, the Chairman may, after holding a summary inquiry into the allegation, take any of the following steps as regards that employer, that is to say, he may—

- (a) give the registered employer a warning in writing, or
- (b) direct that the name of the registered employer shall be removed forthwith from the employers' register either permanently or for such period as he may determine.

Provided that no such removal under sub-item (b) shall be made except after giving the employer a reasonable opportunity of being heard.

(ii) if any allegation of indiscipline, "go-slow" or misconduct is made against a registered dock worker, the Chairman may suspend him forthwith pending inquiry, hold a summary inquiry into the allegations and take any one or more of the following steps against that worker, that is to say, he may—

- (a) determine that for such period as he thinks proper that worker shall not be entitled to any payment under clause 42;
- (b) give him a warning in writing,
- (c) suspend him without pay for a period not exceeding three months;
- (d) terminate his services after giving 14 days' notice or 14 days' wages inclusive of dearness allowance in lieu thereof, or
- (e) dismiss him.

Provided that no such termination under sub-item (d) or dismissal under item (e) shall be made except after giving the worker a reasonable opportunity of being heard.

(iii) (a) Where a worker has been suspended pending enquiry, he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance equivalent to one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances.

Provided that where such inquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the worker, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.

(b) the subsistence allowance so paid shall not be recoverable or liable to forfeiture in any case whatsoever,

(c) Where a dock worker is found not guilty, he shall be entitled to such payments in respect of the period of his suspension as the Administrative Body may certify that the worker would have received on the time rate basis or under clause 32 had he not been suspended, provided that the amount so payable shall be reduced by the amount of subsistence allowance already paid during that period.

(3) The provisions of the Scheme relating to disciplinary action against registered employers and registered dock workers shall not apply to any order passed by the Chairman under sub-clause (2).

(4) Any registered dock worker or registered employer who is aggrieved by an order passed by the Chairman under sub-clause (2), may within 30 days of the date of receipt of the order, prefer an appeal to the Central Government.

(5) Notwithstanding anything contained in the Scheme, so long as an order under sub-clause (1) is in force, the Chairman may authorise the employment of the unregistered workers directly by registered employers and payment to such unregistered workers, directly.

52 Cost of operating the Scheme.—(1) The cost of operating the Scheme shall be defrayed by payments made by registered employers to the Board. Every registered employer shall pay to the Board such amount by way of levy in respect of reserve pool workers together with and at the same time as the payment of gross wages due from him under clause 38(5) (i), as the Board may, from time to time, specify by a written notice to registered employers and the amount payable by way of such levy shall not be less than such amount as the Board may fix as the minimum payable by every registered employer. If considered necessary, the Board may require any registered employer to pay such amount by way of levy in respect of monthly workers at such rate as it may determine.

(2) In determining what payments are to be made by registered employers under sub-clause (1), the Board may fix different rates of levy for different categories of work or workers, provided that the levy shall be so fixed that the same rate of levy will apply to all dock employers who are in like circumstances.

(3) The Board shall not sanction any levy exceeding hundred per cent of the estimated total wage bill calculated on the basis of the daily wage rate without the prior approval of the Central Government.

(4) A registered employer shall on demand make a payment to the Board by way of deposit, or provide such other security for the due payment of the amount referred to in sub-clause (1) as the Board may consider necessary.

(5) The Administrative Body shall furnish from time to time to the Board such statistics and other information as may reasonably be required in connection with the operation and financing of the Scheme.

(6) If a registered employer fails to make the payment due from him under sub-clause (1) or any other amount due and payable to the Board in any other capacity or amount within the time specified by the Administrative Body, the Administrative Body shall serve a notice on the employer to the effect that, unless he pays his dues within three days from the date of receipt of the notice, the supply of registered dock workers to him shall be suspended. On the expiry of the notice period, the Administrative Body shall suspend the supply of registered dock workers to a defaulting employer until he pays his dues.

53. **Provident Fund, Gratuity and Voluntary Retirement Fund.**—(1) Without prejudice to any agreement entered into between the registered employers and registered dock workers, the Board in respect of the workers in the reserve pool and the registered employers, in respect of their monthly workers, shall frame and operate rules providing for contributory provident fund. The rules shall provide for the rate of contributory provident fund. The rules shall provide for the rate of contribution from the workers and the employers, the manner and method of payment and such other matters as may be considered necessary:

Provided that the rules applicable to monthly workers shall not be less favourable than those relating to workers in the reserve pool.

(2) Without prejudice to any agreement entered into between the registered employers and registered dock workers, the Board shall frame rules for payment of gratuity to registered workers.

(3) The Board shall, if necessary, make suitable provisions for a voluntary Retirement Fund and shall frame rules for the same.

54. **Dock Workers Welfare Fund.**—Cost of amenities, welfare and healthy measures called the Dock Workers Welfare Fund which shall be maintained by the Board. Contributions to this Fund shall be made by all registered employers at such rate as may be, determined by the Board. The Board shall frame rules for contribution to, maintenance and operation of Employment) Scheme 1957 is hereby repealed:

55. **Penalties:** A contravention of clause 39 shall be punishable with imprisonment for a period not exceeding three months in respect of a first contravention or six months in respect of any subsequent contravention or with fine not exceeding five hundred rupees in respect of a first contravention or one thousand rupees in respect of any subsequent contravention or with both imprisonment and fine as aforesaid.

56. **Repeal and savings.**—On the commencement of this Scheme, the Bombay Un-registered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme 1957 is hereby repealed:

Provided that any order made, right accrued, penalty incurred or anything done or any action taken under the said

Scheme shall so far as may be, deemed to have been made, accrued, incurred or done or taken under this Scheme and any reference in any instrument to any provision of the said Scheme shall be deemed to be a reference to the corresponding provision of this Scheme.

SCHEDULE I

[See clause 2(2)]

Classes or descriptions of dock work and dock workers to which the Scheme applies:—

- (1) Foodgrain and fertiliser handling work.
- (2) The following categories of foodgrain handling workers:—
 - (a) Mukadams
 - (b) Loaders
 - (c) Fillers
 - (d) Stitchers
 - (e) Palawalas
 - (f) Tank Mazdoors
 - (g) Machine Mazdoors
 - (h) Dock Mazdoors

SCHEDULE II

(See clause 31)

The minimum number of days in a month for which wages are guaranteed should be assessed on the basis of average employment during the preceding 12 months according to the following procedure:—

- (a) Supposing an assessment is being made in the month of October, 1956, the total number of gang workers in the reserve pool (including Leave Reserve Workers but excluding Mukadams) as on the 1st October 1955 and the 31st October 1955 should be ascertained. The average strength, on the register, of these categories should be ascertained by adding the two figures and dividing by 2.
- (b) The total number of man-shifts worked by gang workers of the categories referred to in (a) during the month should be ascertained, from the daily employment statistics.
- (c) The total number of man-days of authorised or unauthorised leave taken by the above workers should be ascertained. This figure should be divided by the number of working days in the month to ascertain the average number of workers away on leave.
- (d) The figure ascertained as in (c) should be deducted from the average obtained as in (a) to arrive at the effective strength of workers available during the month.
- (e) The figure of man-shifts ascertained under (b) should be divided by the effective strength ascertained as in (d). The figure arrived at will be the average number of days of employment during the month of October, 1955.
- (f) The above process should be repeated for the remaining 11 months from November 1955 to September 1956.
- (g) The average employment figures for the 12 months should be added and divided by 12.
- (h) The figures arrived at in (g) above should be fixed as the minimum number of days for which wages will be guaranteed for the following 12 months ending the 30th September, 1957.

The following example will illustrate:—

Suppose the total number of gang workers (excluding Mukadams) and Leave Reserve Workers in the reserve in the reserve pool as on the 1st October 1955	2,000
-Do- the 31st October 1955	1,950
	3,950
Average strength on the register for the month	$\frac{3,950}{2} = 1,975$
Total number of man-shifts worked by the workers of the above categories in October, 1955	36,000
Total number of man-days of authorised or unauthorised Leave taken by the workers	5,250
Number of working days in the said month (31 days of the month less one non-working day)	30
	$\frac{5,250}{30} = 175$
Average number of workers away on Leave	
Effective strength available during the month	$1,975 - 175 = 1,800$
Average employment for the month of October, 1955	$\frac{36,000}{1,800} = 20$ days

The same procedure will be followed to arrive at the average employment for the remaining 11 months. Let us assume the figures are as follows:—

October, 1955	...	20
November, 1955	...	21
December, 1955	...	18
January, 1956	...	20
February, 1956	...	18
March, 1956	...	19
April, 1956	...	20
May, 1956	...	19
June, 1956	...	18
July, 1956	...	19
August, 1956	...	20
September, 1956	...	16
Total		228

The number of days for which wages will be guaranteed for the next 12 months ending 30th September, 1957 will be 228

12 = 19 days.

[No. V-11025/4/74-P&D/LD]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

(सम्पदा निदेशालय)

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1974

का० प्रा० 3283.—राष्ट्रपति ने निश्चय किया है कि सरकारी आवास आक्टन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियमावली, 1963 के पू० नि० 317-ख-2(ख) के उपबंधों के अनुसार अग्रणी आक्टन वर्ष 1 जनवरी, 1975 को प्रारम्भ होगा और 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त होगा।

[मि० सं० 12033(7)/74-नी० 2]

प्रभाकर कुलकर्णी, सम्पदा उपनिदेशक (नीति)

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

(Directorate of Estates)

New Delhi, the 3rd December, 1974

S.O. 3283.—The President is pleased to decide that the next Allotment Year, in terms of the provisions of S.R.

317-B-2(b) of the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963, shall commence on the 1st of January, 1975 and shall end on the 31st December, 1977.

[F. No. 12033(7)/74-Pol. II]

P. B. KULKARNI, Deputy Director (Policy)

श्रम मंत्रालय

प्रादेश

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 1974

का० प्रा० 3284.—यतः ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट, सुन्दर नगर से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों ने, जिनका प्रतिनिधित्व ब्यास सतलुज लिंक वर्कर्स यूनियन सुन्दर नगर ने किया है, केन्द्रीय सरकार को संयुक्त रूप से आवेदन किया है कि उक्त आवेदन में उपर्युक्त और इससे उपायध्व अनुसूची में दिए गए मामलों की बाबत औद्योगिक विवाद को, जो उनके बीच विद्यमान है, औद्योगिक अधिकरण को निर्देशित किया जाए;

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त ब्यास सतलुज लिंक वर्कर्स यूनियन, सुन्दर नगर कर्मचारियों की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० आर० सोधी होंगे जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करनी है।

अनुसूची

क्या ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट, सुन्दर नगर में नियोजित स्टाफ्फ और मरफाई करने वाले ग्रीष्म और शीतकालीन वस्त्रों के मुफ्त प्रदाय के हकदार है। यदि हाँ, तो कब से और किस सान पर?

[स० एल०-42012/32/74/एन०आर०-III]

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 8th October, 1974

S.O. 3284.—Whereas the employers in relation to Beas Sutlej Link Project, Sundernagar and their workmen represented by Beas Sutlej Link Workers Union, Sundernagar have jointly applied to the Central Government for reference of an industrial dispute that exists between them to an Industrial Tribunal in respect of the matter set forth in the said application and reproduced in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government is satisfied that the said Beas Sutlej Link Workers' Union, Sundernagar represents the majority of the workmen;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri H. R. Sodhi shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute to the said Tribunal for adjudication.

SCHEDULE

Whether the sweepers and cleaners employed at Beas Sutlej Link Project, Sundernagar are entitled to supply of free summer and winter uniforms? If so, since when and at what scale?

[No. L. 42012/32/74/LR.III]

आवेश

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 1974

का० आ० 3285.—यत् इसमें उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद श्री जी० एन० बोराह, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, डिब्रूगढ़ (असम) के समक्ष लम्बित है,

और यत् न्याय के उद्देश्य और पक्षकारों की सुविधा के लिए उक्त विवाद का निपटान बिना और विलम्ब के किया जाना चाहिए;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 33ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री जी० एन० बोराह, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, डिब्रूगढ़ से उक्त विवाद से सम्बद्ध कार्यवाही वापस लेती है और उसे उक्त कार्यवाही के निपटाने के लिए श्री ई० के० मोइदु, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को इस आदेश के साथ अन्तर्गत करती है कि उक्त अधिकरण, उस कार्यवाही में आगे कार्यवाही उसी प्रक्रम से करेगा जिस पर वह उसे अन्तर्गत की जाती है और विधि के अनुसार उसका निपटान करेगा।

अनुसूची

विवाद के पक्षकार	औद्योगिक विवाद की निर्देश संख्या और तारीख
आयल इंडिया लिमिटेड, दुलियाजान और उनके कर्मकार/जिनका प्रतिनिधित्व इंडियन ओयल कर्मचारी यूनियन दुलियाजान करती है।	25(9)/68-एल० आर० I (एल० आर० 4) दिनांक 27 जनवरी, 1971।

[संख्या एल-30025(4)/74-एल० आर० 4]

ORDER

New Delhi, the 16th October, 1974

S.O 3285.—Whereas the industrial dispute specified in the Schedule hereto annexed is pending before Shri G.N. Borah, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Dibrugarh (Assam);

And, Whereas for the ends of justice and convenience of the parties, the said dispute should be disposed of without further delay;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and Sub-section (1) of section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby withdraws the proceedings in relation to the said dispute from Shri G.N. Borah, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Dibrugarh and transfers the same to Shri E.K. Moidu, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Calcutta for the disposal of the said proceedings with the direction that the said Tribunal shall proceed with the proceedings from the stage at which it is transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Parties to the dispute	Reference No. and date of Industrial Dispute
Oil India Limited, Duliajan and their workmen represented by Indian Oil Worker's Union, Duliajan.	25(9)/68-LR I (LR IV), dated the 27th January, 1971.

[No. L-30025(4)/73-LR IV]

प्रादेश

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 1974

का० आ० 3286.—यत् इसमें उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद श्री जी० एन० बोराह, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, डिब्रूगढ़ (असम) के समक्ष लम्बित पड़ा है ;

और यत् न्याय करने के लिए और पक्षकारों की सुविधा के लिए उक्त विवाद का निपटान बिना और विलम्ब के किया जाना चाहिए,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 33ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद से सम्बद्ध कार्यवाही को श्री जी० एन० बोराह, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, डिब्रूगढ़ से वापस लेती है और उसे उक्त कार्यवाही के निपटाने के लिए श्री ई० के० मोइदु, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को इस आदेश के साथ अन्तर्गत करती है कि उक्त अधिकरण आगे की कार्यवाही उसी प्रक्रम से शुरू करेगा जिस पर वह उसे अन्तर्गत की गयी है और विधि के अनुसार उसका निपटान करेगा।

अनुसूची

विवाद के पक्षकार	औद्योगिक विवाद की निर्देश संख्या और तारीख
असम आयल कंपनी लि० डिगबोई और उनके कर्मकार जिनका प्रतिनिधित्व ए० ओ० सी० श्रमिक यूनियन, हाकधर डिगबोई, असम करती है।	एल-30011(3) 72-एल० आर० 4, दिनांक 5 दिसम्बर, 72

[संख्या एल-30011(3) 72-एल० आर० 4]

ORDER

New Delhi, the 19th October, 1974

S.O. 3286.—Whereas the industrial dispute specified in the Schedule hereto annexed is pending before Shri G. N. Borah, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Dibrugarh (Assam);

And, whereas for the ends of justice and convenience of the parties, the said dispute should be disposed of without further delay;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and sub-section (1) of section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby withdraws the proceedings in relation to the said dispute from Shri G. N. Borah, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Dibrugarh and transfers the same to Shri E. K. Moidu, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Calcutta for the disposal of the said proceedings with the direction that the said Tribunal shall proceed with the proceedings from the stage at which it is transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Parties to the dispute	Reference No. and date of Industrial Dispute
Assam Oil Company Limited, Digboi and their workmen represented by A.O.C. Labour Union P.O. Digboi Assam.	L-30011 (3)/72—LR IV dated the 5th December, 72

[No. L-30011(3)/72-LR. IV]

आदेश

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 1974

क्र० प्र० 3287.—यत्. केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स डालमिया इण्टरनेशनल, हौस्पेट की बी० आर० एच० लौह अयस्क खानों के रेजिग ठेकेदार, श्री एम० रामन और उनके कर्मचारियों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और यत्. केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय निर्णय के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० सी० कोशुर होंगे, जिनका मुख्यालय बंगलूर में होगा और उक्त विवाद उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्याय निर्णय के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स डालमिया इण्टरनेशनल हौस्पेट की बी० आर० एच० लौह अयस्क खानों के रेजिग ठेकेदार, श्री एम० रामन की श्री आई० नागप्पा, माटैर की सेवाओं को, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 25क के उपबन्धों का अनुसरण किए बिना 31 मार्च, 1974 से, समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो श्री आई० नागप्पा किस अनुवोध का हकदार है?

[एन-26011/12/74-एल०आर०-4]

ORDER

New Delhi, the 21st October, 1974

S.O. 3287.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between Shri M. Raman, Raising Contractor of B.R.H. Iron Ore Mines of Messrs Dalmia International, Hospet and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri M. C. Kannur as Presiding Officer with headquarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of Sri M. Raman, Raising Contractor of B.R.H. Iron Ore Mines of Messrs Dalmia International, Hospet in terminating the services of Sri Y. Nagappa, Sorter with effect from the 31st March, 1974 without following the provisions of section 25F of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), is justified? If not, to what relief Sri Y. Nagappa is entitled?"

[No. L-26011/12/74-LR-IV]

आदेश

क्र० प्र० 3288.—यत्. केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स जयपुरिया चाहना कले

माहन्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता-13 के स्वामित्वधीन रायकमान चाहना कले माहन्स के प्रबन्ध तन्त्र से सम्बन्धित नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यत्. केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय निर्णय के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण (संख्या 2) धनबाद को न्याय निर्णय के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स जयपुरिया चाहना कले माहन्स (प्राइवेट) लिमिटेड की रायकमान स्थित रायकमान चाहना कले माहन्स, डाकबर अम्धारी, जिला सिंहभूम के प्रबन्धतन्त्र की, उनकी रायकमान चाहना कले माहन्स में निम्न वर्णित कर्मचारियों को 13 मई, 1974 से 15 मई, 1974 तक रोजगार देने से इनकार करने की कार्यवाही न्यायोचित थी? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुवोध के हकदार हैं?

कर्मचारी जिनके लिये तालाबन्दी की गई

खदान अनुभाग

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. श्री पिडोबाम | 2. श्रीमति भुक्को |
| 3. श्रीमति पुष्पा | 4. श्री दासनायक |
| 5. श्रयबिराजी | 6. श्रीमति रूपी |
| 7. श्रीमति शरवती | 8. श्री कोरा कोरो |
| 9. श्रीमति निरासो | 10. श्रीमति सुमित्रा |
| 11. श्री पुराध धारो | 12. श्रीमति मावित्री |
| 13. श्रीमती बन्दी | 14. श्री जोराहूर |
| 15. श्रीमति सुलतानी | 16. श्रीमति जिमा |
| 17. श्री गजधर | 18. श्रीमति खोरिसो |
| 19. श्रीमति रोमा | 20. श्री कैलाश |
| 21. श्रीमति बिन्दासो | 22. श्रीमति गुलापो |
| 23. श्री बंनुधर | 24. श्रीमति गोमो |
| 25. श्रीमति दोस्मा | 26. श्री मुरजन |
| 27. श्रीमति निरासो-II | 28. श्रीमति लुचोना |
| 29. श्री अघिरो | 30. श्रीमति घस्मी |
| 31. श्रीमति सारो | 32. श्री रेंसो |
| 33. श्रीमति सोमवारी | 34. श्रीमति रांधी |
| 35. श्रीमति नेगी | 36. श्रीमति जूनिया |
| 37. श्री सुकलाल | 38. श्रीमति सुनाई |
| 39. श्रीमति रांधी | 40. श्री नाथो |
| 41. श्रीमति ह्दायर | 42. श्रीमती पेपली |
| 43. श्री भगवान | 44. श्रीमती मनजीन |
| 45. श्रीमति बोमु | 46. श्री रघुनाथ |
| 47. श्रीमती मेंजो | 48. श्रीमति पेपली |
| 49. श्री छानन्व | 50. श्रीमति रबिबारी |
| 51. श्रीमति पामभती | 52. श्री भानु |
| 53. श्रीमति लामा | 54. श्रीमति लूथरी |
| 55. श्री मोनभो | 56. श्रीमति सूभी |
| 57. श्रीमति सुह | 58. श्री बुहडु |
| 59. श्रीमति कायरी | 60. श्रीमति कायरी |
| 61. श्रीमति जाम्बी | 62. श्री चरण |

63 श्रीमति कमला	64 श्रीमति सुनिका	159 श्री सुना	160 श्री सुबान
65 श्री रामतिया	66 श्रीमति सोबारी	161 श्री गोधरा	162 श्री सोनातन
67 श्रीमति मेझाजी	68 श्री रुपा	163 श्री मुजा	164. श्री सोनु
69 श्रीमति सुरु	70 श्रीमति दोस्मा	165 श्री कोणा	166. श्री रोदी
71 उच्चा	72 श्रीमति बेलो	167 श्री धासी राम	168 श्री खुलो
73 श्रीमति लालमोती	74 श्री साम्ना		
75 श्रीमति मोती	76 श्रीमती पोदनी		
77 श्रीमति सहसू	78 श्रीमति बांगोई		तीसरी पारी
79 श्रीमति रागवारी	80 श्री मुकलाल	169 श्री कुसनु	170 श्री रोरो
81 श्रीमती भाजमोकी	82 श्री फिरसोन		धुलाई अनुभाग
83 श्रीमति मन्नी	84 श्रीमति माझी	171 श्री दिवाकारो	172 श्री दडका
84 श्री धोनी	86 श्रीमति सवनी	173 श्री जम्भू	174 श्री सनातन
87 श्रीमति बिराज	88 श्री ओईवान	175 श्री रोतना	176. श्री रूप सिंह
		177. श्री नन्वी	178 श्री मानकौरो
		179. श्री मडाई	
			जाली की धुलाई
			पहली पारी
89 श्रीमती सोहटो	90 श्रीमति ओसबिन	180 श्रीमति कुनी	181 श्रीमति सोबानी
91 श्रीमति जयमोनी	92 श्रीमति कोन्को	182 श्रीमति राधो	183 श्रीमति जुवधो
93 श्रीमति ब्रिमला	94 श्रीमति खुबानी		
95 श्रीमति पारो	96 श्रीमति रोबारी		
97 श्रीमति जम्बा	98 श्रीमति यस्मोती		
99 श्रीमति शकमणी	100 श्रीमति मोन्ती		
101 श्रीमति वास I	102 श्रीमति दोमु II		
103 श्रीमति नोनिटा	104 श्रीमति कोनसोला		
105 श्रीमति सुबानी	106 श्रीमति गुरुबानी	184 श्री पितम	
107 श्रीमति हारो	108 श्रीमति सुरजो	185 श्री सामु	186 श्री सिंगा
		187 श्री रोया	188 श्री बेस्वा
		189 श्री रसिका	190 श्री कृष्ण
		191 श्री साधो	192 श्री सोबान
		193 श्री जाबिरा	194 श्री वासो
		195 श्री रघुनाथ	196 श्री गोगा
		197 श्री जाबा	
			पम्प खलासी
109 श्रीमति नरा	110 श्रीमति जोझी	198. श्री धर्जुन	199 श्री किन्ता
111 श्रीमति भोगिनी	112 श्रीमति मुक्ता	200. श्री कारिया	201 श्री रान्सी
113 श्रीमति साबु	114. श्रीमति सोझी	202 श्री सिबो	
115 श्रीमति पोडी	116 श्रीमति कुलमोती		
117 श्रीमति फुलमोती II	118 श्री दोसमोती		
119 श्रीमति मोम्का	120 श्रीमति सुशीला		
121 श्रीमति कोकिलो	122 श्रीमति हेमो		
123 श्रीमति सारवनी	124 श्रीमति दोयामोती		
125 श्रीमति मुजा	126 श्रीमति जम्पा		
127. श्रीमति गोरी	128 श्रीमति सुदेव I		
129 श्रीमति सुवेन II	130 श्रीमति लुप्री		
131 श्रीमति बिराज (सारो)	132 श्रीमति सारो	203 श्री सोमनाथ	204 श्री गोपी
133 श्रीमति मोनी	134 श्रीमति कुली	205 श्री पोदु	206 श्री रमेश
135 श्रीमति साधित्री	136 श्रीमति सीता	207 श्री सिंगा	208 श्री राधा
137. श्रीमति पोछना	138 श्रीमति चुर्मा	209 श्री जम्बल	210 श्री डोरू
139. श्रीमति दोरपति	140 श्रीमति ब्रिमला	211 श्री धासीराम नायक	
141. श्रीमति पानी	142 श्रीमति निरसा		
143 श्रीमति भेजो	144 श्रीमति दोस्मा		
145 श्रीमति नुजी	146 श्रीमति नातिका		
147 श्रीमति भेजा II			
			बेगिन कोरले
		212 श्री नरेश	
		213 श्री सुद्ध	214 श्री केसाई
		215 श्री गोपी	216 श्री मगन सिंह
		217 श्री मोन्धिया	218 श्री सागर
		219. श्री लाणु	220 श्री हारी
148 श्री ध्रम	150 श्री पांडु		
149 श्री रोबा	152 श्री जुमाल		
151 श्री कैलाश	154 श्री रामो	221. श्री प्रताप	222 श्रीमति कीदमा
153 श्री कोनगाला	156 श्री गुरुचरण	223 श्रीमति चामो	
155 श्री होरी	158 श्री सोबन		
157 श्री पोरनो			
159 श्रीमति कमला			

ORDER

S.O. 3288.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Raikaman China Clay Mines owned by Messrs Jaipuria China Clay Mines (Private) Limited, Calcutta-13 and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 2) Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Raikaman China Clay Mines of Messrs Jaipuria China Clay Mines (Private) Limited at Raikaman Post Office Andhari, District Singhbhum in refusing employment to the 222 workers mentioned below at their Raikaman China Clay Mines from the 13th May, 1974 to 15th May, 1974 was justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?"

Locked out Employees

(1) Quarry Section

1. Sri Pitobas
2. Smt. Mukho
3. Smt. Puspa
4. Sri Darunaik
5. Sri Biranchi
6. Smt. Rupee
7. Smt. Sarwati
8. Sri Kora Koro
9. Smt. Niraso
10. Smt. Sumitra
11. Sri Puradh Dhare
12. Smt. Sabitri
13. Smt. Chandri
14. Sri. Jorahar
15. Smt. Sultanti.
16. Smt. Jima
17. Sri. Gajadhar
18. Smt. Lorito
19. Smt. Roma
20. Sri. Kailash
21. Smt. Bilaso
22. Smt. Gulapo
23. Sri. Benudhar
24. Smt. Goml
25. Smt. Dosma
26. Sri. Surjan
27. Smt. Niraso II
28. Smt. Luchona
29. Sri. Adhiro
30. Smt. Namsi
31. Smt. Saro
32. Sri. Renso
33. Smt. Sombari
34. Smt. Randhi
35. Smt. Negi
36. Smt. Junia
37. Sri. Suklal
38. Smt. Sunai
39. Smt. Randhi
40. Sri. Natho

41. Smt. Indair
42. Smt. Pepli.
43. Sri. Bhagvan
44. Smt. Manjit
45. Smt. Dosu
46. Sri. Raghunath
47. Smt. Menjo
48. Smt. Pepli
49. Sri. Anand
50. Smt. Rabibari
51. Smt. Panbhati
52. Sri. Bhanu
53. Smt. Chama
54. Smt. Ludhri
55. Sri. Onumo
56. Smt. Sumi
57. Smt. Suru
58. Sri. Boldu
59. Smt. Kairi
60. Smt. Kiri
61. Smt. Jambi
62. Sri. Chran
63. Smt. Kamala
64. Smt. Sunika
65. Sri. Ramtia
66. Smt. Sobari
67. Smt. Menjhari
68. Sri. Rupa
69. Smt. Suru
70. Smt. Dosma
71. Uchba
72. Smt. Belo
73. Smt. Lalmoti
74. Sri. Lambra
75. Smt. Moti
76. Smt. Podni
77. Smt. Sahbhu
78. Smt. Bangoi
79. Smt. Raibari
80. Sri. Suklal
81. Smt. Bhajmoti
82. Sri. Kirson
83. Smt. Sabni
84. Smt. Manjhi
85. Sri. Ghono
86. Smt. Sabni
87. Smt. Biranjh
88. Sri. Oiban

SORTING SECTION

89. Smt. Soito
90. Smt. Osbin
91. Smt. Jaimoni
92. Smt. Konko
93. Smt. Bimla
94. Smt. Subani
95. Smt. Paro
96. Smt. Roibari
97. Smt. Chamba
98. Smt. Dosmoti
99. Smt. Rukmoni
100. Smt. Monti
101. Smt. Dosu I

102. Smt. Dosu II
103. Smt. Nonita
104. Smt. Konsola
105. Smt. Subani
106. Smt. Gurubari
107. Smt. Horo
108. Smt. Surjo

PLATFORM SECTION

109. Smt. Nra
110. Smt. Jobri
111. Smt. Bhomini
112. Smt. Mukta
113. Smt. Sandu
114. Smt. Sombri
115. Smt. Poti
116. Smt. Fulmoti
117. Smt. Fulmoti II
118. Smt. Dosmoti
119. Smt. Omka
120. Smt. Susila
121. Smt. Kokilo
122. Smt. Hemo
123. Smt. Sarwati
124. Smt. Dovamoti
125. Smt. Sudra
126. Smt. Champa
127. Smt. Gori
128. Smt. Suden I
129. Smt. Suden II
130. Smt. Ludri
131. Smt. Biranj (Saro)
132. Smt. Saro
133. Smt. Moni
134. Smt. Duti
135. Smt. Sabitri
136. Smt. Sita
137. Smt. Podna
138. Smt. Churmba
139. Smt. Daurpati
140. Smt. Bimla
141. Smt. Pani
142. Smt. Nitma
143. Smt. Menjo
144. Smt. Dosma
145. Smt. Nuji
146. Smt. Nanika
147. Smt. Menjo II

WASHING SECTION

148. Sri Dhram
149. Sri Roya
150. Sri Pandu
151. Sri Kailash
152. Sri Jumal
153. Sri Congala
154. Sri Ramo
155. Sri Hort
156. Sri Gurucharan
157. Sri Pono
158. Sri Soban
159. Sri Suna
160. Sri Goura
161. Sri Goura

162. Sri Sonotan
163. Sri Mutra
164. Sri Sonu
165. Sri Conga
166. Sri Robi
167. Sri Gasiram
168. Sri Sulo

THIRD SHIFT

169. Sri Kusnu
170. Sri Roro

WASHING SECTION

171. Sri Divakare
172. Sri Dundka
173. Sri Ghumbroe
174. Sri Sanatan
175. Sri Rotna
176. Sri Rupsing
177. Sri Nando
178. Sri Mankore
179. Sri Mandai

NET WORK WASHING

1ST SHIFT

180. Smt. Kuni
181. Smt. Sobari
182. Smt. Radhi
183. Smt. Juidho

PRESS SECTION

184. Sri Pitam
185. Sri Samu
186. Sri Singa
187. Sri Roya
188. Sri Beswa
189. Sri Basika
190. Sri Krishna
191. Sri Sagre
192. Sri Soban
193. Sri Jabira
194. Sri Daso
195. Sri Raghunath
196. Sri Gonga
197. Sri Joba

PUM KHALASI

198. Sri Arjuna
199. Sri Chinta
200. Sri Karia
201. Sri Ranso
202. Sri Sibo

GOODS TRANSPORTING

203. Sri Somnath
204. Sri Gopi
205. Sri Podu
206. Sri Ramesh
207. Sri Singa
208. Sri Ratha
209. Sri Jumbal
210. Sri Doru
211. Sri Gasi Ram Naik

WAGIN COLLE

- 212 Sri Naresb
213. Sri Budhu
- 214 Sri Kesai
- 215 Sri Gopi
- 216 Sri Mangal Singh
- 217 Sri Bondhla
- 218 Sri Sagar
219. Sri Lalu
- 220 Sri Jhari

QUARRY CONTINUED

221. Sri Pratap
- 222 Smt Kodma
223. Smt Chamu

[No L-29011(44)/74-LRI V]

आदेश

क्र०प्र० 3289.—यत् केन्द्रीय सरकार की राय है कि इस से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मेसर्स न्यू चुलिया कोल कम्पनी लिमिटेड की बागू बाक्सहाट खान, डाक घर लोहरडागा, जिला राँची के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और यत् केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (संख्या 1), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मेसर्स न्यू चुलिया कोल कम्पनी लिमिटेड की बागू बाक्सहाट खानो, डाकघर लोहरडागा, जिला राँची के प्रबन्धतन्त्र का 9 जनवरी, 1974 से निम्नलिखित 18 कर्मचारों को सेवान्मुक्त करना न्यायोचित था? यदि नहीं, तो ये कर्मकार किम अनुसूच के हकदार हैं?"

- 1 जनाल उद्दीन पुत्र जहीर उद्दीन।
- 2 इदरीश अशारी पुत्र जम्हीर अशारी।
- 3 जहीर अशारी पुत्र अलाही अशारी।
- 4 राबसन अशारी पुत्र बशीरशाह।
- 5 जेयारत शाह पुत्र बशीरशाह।
- 6 जमिल मलिक पुत्र स्मिर मलिक।
- 7 जहीर मलिक पुत्र बिराज मलिक।
- 8 रिजिक शैख पुत्र शैख नामिन।
- 9 शैख सुभानो पुत्र शैख जिलानी।
- 10 शैख नैरातु पुत्र शैख प्रबखाल अली।
- 11 सामुल मिरवाहा पुत्र दाखाल मिरवाहा।
- 13 इशाद मिरवाहा पुत्र इजमत मिरवाहा।
- 13 बिनोद उराव पुत्र सनिचरवा उराव।
- 14 बन्धु उराव पुत्र सनिचरवा उराव।
- 15 सोमे उराव पुत्र बुधु उराव।
- 16 मंगला उराव पुत्र जिजा उराव।
- 17 बिकाई उराव पुत्र धुधु उराव।
- 18 अजित उराव पुत्र मंगलु उराव।

[संएन-29011/32/74-एल०आर०-4]

ORDER

S.O. 3289.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bagru Bauxite Mine of Messrs New Churlia Coal Company Limited, Post Office Lohardaga, District Ranchi and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed,

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad constituted under section 7A of the said Act

SCHEDULE

"Whether the management of Bagru Bauxite Mines of Messrs New Churlia Coal Company Limited, Post Office, Lohardaga, District Ranchi was justified in discharging the following 18 workmen from work from the 9th January, 1974? If not; to what relief are these workmen entitled?"

- 1 Jalal uddin S/o Zahir uddin
- 2 Iderish Anshari S/o Zamhir Anshari.
- 3 Zahir Anshari S/o Alabi Anshari
- 4 Rabson Anshari S/o Bashir Shah.
- 5 Jeyarat Shah S/o Bashir Shah
- 6 Zamil Malik S/o Smir Malik
- 7 Zamhir Malik S/o Biraj Malik.
- 8 Rijik Sheikh S/o Sk Namin
- 9 Sk Subhani S/o Sk Zilani
- 10 Sk Nanatu S/o Sk Akbal Ali
- 11 Samul Mirdaha S/o Dakhil Mirdaha
- 12 Ishad Mirdaha S/o Ijamat Mirdaha.
- 13 Binod Uraon S/o Sancharwa Uraon
- 14 Bandhu Uraon S/o Sancharwa Uraon
- 15 Some Uraon S/o Budu Uraon.
- 16 Mangla Uraon S/o Jiya Uraon.
- 17 Bifai Uraon S/o Ghundu Uraon
- 18 Azit Uraon S/o Manglu Uraon "

[No. L-29011/32/74-LRIV]

आदेश

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1974

क्र०प्र० 3290.—यत् केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में भारतीय खाद्य निगम तमिलनाडु से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और यत् केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० पालनिअप्पन होंगे जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

1. क्या भारतीय खाद्य निगम की क्षेत्र-वार चौकीदारों की कुल संख्या के आधार पर की बजाय यूनिट-वार आधार पर हर 9 से 15 तक चौकीदारों के लिये एक प्रधान चौकीदार और हर दो प्रधान चौकीदारों के लिये एक जमादार का माप-दण्ड लागू करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो कर्मचारी किस अनुतोष के हकदार हैं ;

2. क्या भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धन के लिये भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी यूनियन के संयुक्त सचिव श्री पी० गोपाद्रि का पाण्डेचेरी से तूतीकोरिन को स्थानान्तरित करना न्यायोचित था ? यदि नहीं तो श्री गोपाद्रि किस अनुतोष के हकदार हैं ?

3. क्या भारतीय खाद्य निगम के लिये उन कर्मचारियों को जिनकी सेवा में सतत सेवा का एक वर्ष पूरा करने से पूर्व अल्प अवधियों का अंग हो गया था सतत सेवा का फायदा न देना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो ये कर्मचारी किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[स० एल० 42012/43/73/एल० आर० III]

ORDER

New Delhi, the 26th October, 1974

S.O. 3290.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Food Corporation of India, Tamilnadu and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Thiru T. Palaniappan shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

1. Whether the Food Corporation of India is justified in applying the yardstick of one Head Watchman for every 9 to 15 watchmen and one Jamadar for every two Head Watchmen on a unit-wise basis instead of basing on the total strength of watchmen regionwise ? If not, to what relief are the employees entitled ?

2. Whether the management of the Food Corporation of India was justified in transferring Shri P. Seshadri, Joint Secretary of the Food Corporation of India employees Union, from Pondicherry to Tuticorin ? If not, to what relief is Shri Seshadri entitled ?

3. Whether the Food Corporation of India is justified in not granting the benefit of continuous service to those employees who had short periods of break in service before completing one year of continuous service ? If not, to what relief are these employees entitled ?

[No. L. 42012/43/73/LR.III]

आदेश

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1974

का०आ० 3291.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी पी० टी० पालानी-अप्पन होंगे जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, त्रिचूर-1 के प्रबन्धन की, सर्वश्री टी० ए० अण्डप्पन और पी० के० रापाई बालकों की बैंक की कार चलाने और उनकी देखभाल करने का कार्य उनको सौंपे जाने के उनके दावे से बंचित रखने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मचारों किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[स० एल०-12011/6/74-एल० आर०-III]

ORDER

New Delhi, the 7th November, 1974

S.O. 3291.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the South Indian Bank Limited, and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Thiru T. Palanappan shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the South Indian Bank Limited, Head Office, Trichur-1 in depriving Messrs T. A. Andappan and P. K. Rapai, drivers, of their claim of being entrusted with the work of driving and maintaining the cars of the Bank is justified? If not, to what relief are the said workmen entitled?

[No. L-12011/6/74-LR.III.]

आदेश

का०आ० 3292.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में न्यू बैंक आफ इण्डिया से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री ए० आर० सोही होंगे जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा, और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या न्यू बैंक आफ इण्डिया के प्रबंधन की, श्री यमुना प्रसाद चपरासी की, उसके द्वारा तीन मास की सेवा पूरी कर लिये जाने के पश्चात् पुष्टि न करने और उसकी सेवाये समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो वह किस अनुसूची का हकदार है?

[सं० एन०-12012/37/73-एल आर III]

ORDER

S.O. 3292.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the New Bank of India and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri H. R. Sodhi shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Is the action of the management of the New Bank of India in not confirming Shri Yumna Parsad, Peon, after completion of three months' service by him and terminating his services justified? If not, to what relief is he entitled?

[No. L-12012/37/73-LR. III]

आदेश

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1974

का० प्रा० 3293.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाध्व अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में नियोजकों श्री हजारीलालजी खान स्वामी बुधपुरा डाकघर गांव दाबी (जिला बूंदी) और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है।

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या श्री हजारीलालजी, खान स्वामी, गांव और डाक दाबी, जिला बूंदी (राजस्थान) की बुधपुरा बलुआ पत्थर खानों में नियोजित कर्मकार मजदूर राष्ट्रीय और तृतीय अवकाश दिनों की मजूरी के हकदार है?

[संख्या एन-29011(48)/74-एल०आर०४]

ORDER

New Delhi, the 8th November 1974

S.O. 3293.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers Shri Hazarilalji, Mine Owner, Budhpura, Post and Village Dabi (District Bundi) and his workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the workmen employed in Budhpura Sand Stone Mines of Shri Hazarilalji, Mine Owner, Village and Post Dabi, District Bundi (Rajasthan) are entitled to grant of paid National and Festival holidays?

[No. L-29011 (48)/74-LR. IV]

आदेश

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1974

का० प्रा० 3294.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाध्व अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में नियोजक श्री हजारीलालजी सरपंच, खान स्वामी, बुधपुरा, डाकघर और ग्राम दाबी (जिला बूंदी) और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या श्री हजारीलालजी, खान स्वामी, गांव और डाकघर दाबी, जिला बूंदी (राजस्थान) की बुधपुरा बलुआ पत्थर खान में नियोजित श्रमिकों की सेवा वर्ष 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71, 1971-72 के लिए मजदूरी के 20 प्रतिशत की दर से बोनस के संकाय की मांग न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार में से प्रत्येक वर्ष के लिए बोनस की किस प्रमाणा के हकदार है?

[संख्या एन०-29011(52)/74-एल आर०-4]

ORDER

New Delhi, the 11th November, 1974

S.O. 3294.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employer Shri Hazarilalji Sarpanch, Mine Owner, Budhpura, Post and Village Dabi (District Bundi) and his workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the demand of the workmen employed in Budhpura Sand Stone Mine of Shri Hazarilalji, Mine Owner, Village and Post Dabi, District Bundi (Rajasthan) for payment of bonus @ 20 per cent of wages

for the Accounting years 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71, 1971-72, is justified? If not, to what quantum of bonus are the workmen entitled for each of these years?

[No L-29011(52)/74-LR-IV]

आदेश

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1974

क्रा० आ० 3295 —यत केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स चौगुले एंड कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड, मार्गुगाओ बन्दरगाह (गोवा) के प्रबन्धनत्व से सञ्चालित नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और यत केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वाछनीय समझती है

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के षड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, (संख्या 2) बम्बई को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

‘क्या मैसर्स चौगुले एंड कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड, मार्गुगाओ बन्दरगाह (गोवा) के प्रबन्धनत्व की, पाले सौद्र भयस्क खाना के मुख्य मजदारी, श्री यू० दिनकर की सेवा को 12 जून, 1971 से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हक्कार है?’

[संख्या एल०-26012/12 74-एल० आर० 4]

ORDER

New Delhi, the 15th November, 1974

S.O. 3295.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Chowgule and Company (Private) Limited, Marmugao Harbour, (Goa) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed,

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, (No 2) Bombay constituted under section 7A of the said Act

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Messrs Chowgule and Company (Private) Limited, Marmugao Harbour (Goa) in terminating the services of Shri U Dinkar, Head Store Keeper, Pale Iron Ore Mines with effect from 12.6.1971 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?”

[No L-26012/12/74-LR IV]

आदेश

क्रा० आ० 3296 —यत केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बैंक आफ बड़ौदा से संबंध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है, और यत केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय निर्णयन के लिये निर्देशित करना वाछनीय समझती है

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एस० एच० जे० नकवी होंगे, जिनका मुख्यालय कानपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या बैंक आफ बड़ौदा के प्रबंधकों की, बैंक के रायबरेली स्थित शाखा के चौकीदार श्री गंगा बक्स सिंह को 17 नवम्बर, 1971 से पदभ्युक्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो वह किस अनुतोष का हक्कार है?

[स० एल-12012/64/74/एल० आर III]

ORDER

S.O. 3296.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri S H J Naqvi shall be the Presiding Officer, with headquarters at Kanpur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Bank of Baroda in dismissing Shri Gangabax Singh, Watchman of Rai Bareilly Branch of the Bank with effect from the 17th November, 1971 is justified? If not, to what relief is he entitled?

[No L 12012/64/74/LR III]

आदेश

क्रा० आ० 3297.—यत केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में ऐमोसिएटेड सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के स्वामित्वाधीन लखेरी चूना पत्थरखानो, डाकघर लेखेरी, जिला बूंदी, राजस्थान के प्रबन्धनत्व से सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है

और यत, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वाछनीय समझती है,

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

“क्या मैसर्स एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी लि० की लखेरी चूना पत्थर खानों, आकबर लखेरी, जिना बूंदी के प्रबन्धतंत्र की, 14 मई, 1974 से 20 मई, 1974 तक अपने श्रमिकों को चक्रामुक्त में कामबन्दी करने की कार्रवाई न्यायोचित थी। यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुसूची के हकदार हैं ;

[संख्या एल०-29011(54)/74-एल०भार० 4]

ORDER

S.O. 3297.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Lakheri Lime Stone Mines owned by Associated Cement Company Limited, Post Office Lakheri, District Bundi, Rajasthan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Lakheri Lime Stone Mines of Messrs Associated Cement Company Limited, Post Office Lakheri, District Bundi in laying off their workers in rotation from the 14th May, 1974 to the 20th May, 1974 was justified? If not, to what relief are the workers entitled?”

[No. L-29011(54)/74-LR. IV]

आदेश

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1974

क्रा० प्रा० 3298.—यत् केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में नियोजक, श्री भासी-लालजी, खान स्वामी, दाबी और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यत् केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या श्री भासीलालजी खान स्वामी, दाबी (जिला बूंदी) की बुध-पुरा बलुआ पत्थर-खान में नियोजित कर्मकारों की लेखा वर्ष 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71, और

1971-72 के लिए मजदूरी के 20 प्रतिशत की दर से बोनस के सदाश की मांग न्यायोचित है? यदि नहीं तो कर्मकार इनमें से प्रत्येक वर्ष के लिए बोनस की किस प्रमाणा के हकदार हैं।

[सं० एल० 29011(46)/74-एल०भार० 4]

ORDER

New Delhi, the 19th November, 1974

S.O. 3298.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers Shri Ghasilalji, Mine Owner, Dabi and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the demand of the workmen employed in Budh-pura Sand Stone Mine of Shri Ghasilalji, Mine Owner Dabi (District Bundi) for payment of bonus @ 20 per cent of wages for the accounting years 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71 and 1971-72 is justified? If not, to what quantum of Bonus are the workmen entitled for each of these years?

[No. L-29011(46)/74-LR. IV]

आदेश

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1974

क्रा० प्रा० 3299.—यत् अपने रेदी खान प्रतिष्ठान के बारे में मैसर्स गॉटे मिनरल्स मुकाम और आकबर। रेदी जिला रस्तागिर के प्रबन्ध-तंत्र और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय माइन मजदूर संघ, रेदी करता है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यत् उक्त कम्पनी और यूनियन ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक निश्चित करार द्वारा उक्त विवाद को उनमें वर्णित व्यक्ति में माध्यस्थता के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थता करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थता करार को, जो उसे 26 नवम्बर, 1974 को मिला था, एतद्वारा प्रकाशित करती है।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

के बीच

पक्षकारों के नाम :

नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले: मैसर्स गॉटे मिनरल्स, रेदी

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले: राष्ट्रीय माइन मजदूर संघ, रेदी

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री ए० एम० गुप्ता, क्षेत्रीय अमात्य (केन्द्रीय) बम्बई के माध्यस्थ के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है —

ORDER

New Delhi, the 30th November, 1974

S.O. 3299.—Whereas an industrial dispute exists between the management of Messrs. Gogte Minerals, AT and PO. Redi District Ratnagiri in respect of their Redi Mines Establishment and their workmen represented by Rashtriya Mine Mazdoor Sangh, Redi:

And whereas the said company and the Union have, by a written agreement in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to the arbitration of person mentioned therein and a copy of the arbitration agreement has been forwarded to the Central Government;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the said agreement which was received in it on 26th of November, 1974

AGREEMENT

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

Name of Parties :

Representing employers : M/s. Gogte Minerals, Redi.

Representing workmen : Rashtriya Mine Mazdoor Sangh, Redi.

It is hereby agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of Shri A. S. Gupta, Regional Labour Commissioner (Central), Bombay.

(i) Specific matters in dispute:—

"Whether the termination of employment of 163 workmen by the management of M/s. Gogte Minerals at their Redi Iron Ore Mines in the month of May, 1974 amounts to retrenchment or lockout? In either case whether this action of the management was legal and justified and if not, to what relief are these workmen entitled?"

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved:

(1) M/s Gogte Minerals, AT & Post: Redi, Dist. Ratnagiri in respect of their Redi Mines Establishment.

(2) Rashtriya Mine Mazdoor Sangh, Redi, representing the employees in the Mining Establishment of M/s. Gogte Minerals, Redi.

(iii) Name of the Union, if any, representing the workmen in question : Rashtriya Mine Mazdoor Sangh, Redi

(iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected : 163.

(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute : 163.

The Arbitrator shall make his award within a period of three months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the Award

पक्षकारों के हस्ताक्षर

(1) कृने मैसर्स गॉटे मिनेरल्स
(नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले)

(1) ह०/-
(बी० एम० राता)
ह०/-
(ए० बी० गॉटे)
सामोवा

(2) कृने राष्ट्रीय खान मजदूर संघ
(श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले)

ह०/-
(जी० रामाचन्द्रम्)
ह०/-
(बी० ए० गावाम)
महामंत्री

[संख्या एम०-29013/2/71-गल०आर०-1]

आर० कुंजीबापदम्, अवर सचिव

is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

We further agree that the decision of the arbitrator shall be binding on us.

Signature of the Parties.

(1) for M/s. Gogte Minerals
(Representing Employer)

(1) Sd/-

(B. S. RANA)

Sd/-

(G. RAMACHANDRAM)

Sd/-

(A. B. GOGTE)

Partner.

(2) for Rashtriya Mine Mazdoor Sangh
(Representing Workers)

Sd/-

(V. A. GAVAS)

General Secretary.

[No. L-29013/2/74-LR-IV]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1974

क्रा० प्रा० 3300.—यत् केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सेनापति सायमन्स इन्सुलेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, पोस्ट अचोलु, तालुक रामनगरम्, जिला बंगलूर जिसमें 14 नेता जी रोड, फेजर टाउन, बंगलूर-6, स्थित उसका प्रधान कार्यालय भी आता है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 की जनवरी, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एम० 35019(42)/74-पी० एफ० II]

New Delhi, the 28th November, 1974

S.O. 3300.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Senapathy Symons Insulations (Private) Limited, Post Acholu, Taluk Ramanagaram, District Bangalore, including its Head Office at 14 Netajee Road, Fraser Town, Bangalore-6 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1974.

[No. S-35019/42/74/PF-II]

क्रा० प्रा० 3301.—यत् केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राज मोटर्स, सं० 110-E, माउण्ट रोड, मद्रास-18 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 की जनवरी, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एम० 35019(57)/74-पी० एफ० II]

S.O. 3301.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Raj Motors, No. 110-E, Mount Road, Madras-18 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1974.

[No. S 35019(57)/74-PF. II]

क्रा० प्रा० 3302.—यत् केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मेटल परफोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जी० पी० इण्डस्ट्रियल एस्टेट, पोस्ट अफिम छाती, जिला बड़ौदा, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 1 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के अप्रैल के तीसरे दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एम० 35019(97)/73-पी० एफ० 2]

S.O. 3302.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Metal Perforation Private Limited, G. P. Industrial Estate, Post Office Chhatri, District Baroda have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of April, 1973

[No. S. 35019(97)/73-PF. II]

का० आ० 3303.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी, भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, विषय में आग्रह्यक जांच करने के पश्चात् 30 नवम्बर, 1973 से सैनर्स प्रोमर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, मणि महल 11/21 मैथ्यू रोड, मुम्बई-4, जिसमें "गिरिजा" एन्डवना, 4/3 कार्वे रोड, पूना स्थित उनकी शाखा भी सम्मिलित है, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए प्रितिदिष्ट करती है।

[स० एम० 35018(27)/74-पी० एफ० II(ii)]

S.O. 3303.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 30th day of November, 1973 the establishment known as Messrs Promer Sales Private Limited, Mani Mahal, 11/21 Mathew Road, Bombay-4 including its branch at "Girija" Erandavana 4/3 Karve Road, Poona for the purposes of the said proviso.

[No. S-35018/27/74-PF. II (ii)]

का० आ० 3304.—यत् केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सैनर्स प्रोमर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, मणि महल, 11/21 मैथ्यू रोड, मुम्बई-4, जिसमें "गिरिजा" एन्डवना, 4/3 कार्वे रोड, पूना स्थित उनकी शाखा भी सम्मिलित है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के नवम्बर के तीसरे दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[स० एम० 35018(27)/74-पी० एफ० 2(i)]

S.O. 3304.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Promer Sales Private Limited, Mani Mahal 11/21 Mathew Road, Bombay-4 including its branch at 'Girija' Erandavana, 4/3 Karve Road, Poona have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1973.

[No. S-35018/27/74-PF. II(i)]

का० आ० 3305.—यत् केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सैनर्स फॉर्मस आर्क फी एन्टरप्राइज, मोहराब हाऊस, 235 डाक्टर सी० एम० रोड, मुम्बई-1, जिसमें (1) 35, माउंट रोड, मद्रास-2 (2) आर्य भवन, जोर बाग, नई दिल्ली (3) 38/2 निर्मल चन्द्र स्ट्रीट, कलकत्ता-13 स्थित शाखाएँ शामिल हैं, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक

और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 के जून के तीसरे दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[स० एम० 35018(59)/72-पी० एफ० 2]

S.O. 3305.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Forum of Free Enterprise, Sohrab House, 235 Dr. D. N. Road, Bombay-1, including its branches at (1) 35, Mount Road, Madras-2 (2) Arya Bhavan, Jor Bagh, New Delhi (3) 38/2, Nirmal Chandra Street, Calcutta-13 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June 1971.

[No. S. 35018/59/72-PF. II]

का० आ० 3306.—यत् केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सैनर्स कान्टीन्यूअस स्टील कास्टिंग प्लांट, आर्केनम, तमिलनाडू नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के अक्टूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[स० एम० 35019(165)/73 पी० एफ०-2]

S.O. 3306.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Continuous Steel Casting Plant, Arkenam, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October 1973.

[No. S. 35019(165)/73-PF. II]

क्रा० प्रा० 3307.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स मैसूर प्रेसीजन डाईकस्टिंग्स (प्राइवेट) लिमिटेड, सातवां मील, टंकर रोड, दसतरखल्ली, बंगलोर-22 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के जून के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(161)/74-पी०एफ० 2]

S.O. 3307.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mysore Precision Diecastings (Private) Limited 7th Mile Tunkar Road Dasaraballi, Bangalore-22 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1974.

[No. S. 35019(161)/74-PF. II]

क्रा० प्रा० 3308.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात्, प्रथम अप्रैल, 1974 से मेसर्स लुधियाना यार्न सप्लाय एजेंसीज, पुराना कोतवाली, लुधियाना नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35019(144)/74-पी०एफ० 2(ii)]

S.O. 3308.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of April, 1974 the establishment known as Messrs Ludhiana Yarn Supply Agencies, Purana Kotwali, Ludhiana for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(144)/74-PF. II(ii)]

क्रा० प्रा० 3309.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स लुधियाना यार्न सप्लाय एजेंसीज, पुराना कोतवाली, लुधियाना नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 की अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(144)/74-पी०एफ० 2(i)]

S.O. 3309.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ludhiana Yarn Supply Agencies, Purana Kotwali, Ludhiana have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1974.

[No. S. 35019(144)/74-PF. II(i)]

क्रा० प्रा० 3310.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स युनिवर्सल फायनेन्स ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड 3A/3, आसफ अली रोड, नई दिल्ली नामक स्थापन, जिसके अन्तर्गत (1) 8/सिक्किण्ड प्लोर, म्यूमोन चेम्बर्स, मेडोज स्ट्रीट, फोर्ट मुम्बई-1, (2) 9, एजरा स्ट्रीट, कलकत्ता-1, (3) 310/311, लिंग्घी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-1, (4) 47, सोलाराम बिल्डिंग, फोर्ट प्लोर, जे० सी० रोड, बंगलोर-2, स्थित उसकी शाखाएं भी आती हैं, से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के अक्टूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(148)/74-पी०एफ०-2]

S.O. 3310.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Universal Finance Traders Private Limited 3A/3, Asaf-Ali Road, New Delhi including its Branches at (1) 8/2nd Floor Beaumon Chambers, Medows Street, Fort Bombay-1, (2) 9, Ezra Street, Calcutta-1, (3) 310/311, Linghi Chetty Street, Madras-1, (4) 47, Scetharam Building, 1st Floor J. C. Road, Bangalore-2 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1973.

[No. S. 35019(148)/74-PF. II]

क्रा० आ० 3311—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् मैसर्स हाइवे साईकल इन्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, इन्डस्ट्रियल एरिया-बी, लुधियाना-3 नामक स्थापन को 1 जुलाई, 1973 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एम० 35019(141)/74-पी०एफ०-2(ii)]

S.O. 3311.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st day of July, 1973 the establishment known as Messrs Highway Cycle Industries (Private) Limited, Industrial Area-B, Ludhiana-3 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(141)/74-PF. II(ii)]

क्रा० आ० 3312.—यत्. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हाइवे साईकल इन्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, इन्डस्ट्रियल एरिया बी०, लुधियाना-3 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 की जुलाई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एम० 35019(141)/74-पी०एफ०-2 (i)]

S.O. 3312.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Highway Cycle Industries (Private) Limited, Industrial Area-B, Ludhiana-3, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1973.

[No. S. 35019(141)/74 PF.II(i)]

क्रा० आ० 3313.—यत्. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रोसेस इन्विपमेंट्स, एफ-11 ब्लॉक, पिम्परी औद्योगिक क्षेत्र, पूना-18 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात

पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के दिसम्बर के एकतीसरे दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एम० 35018(26)/74-पी०एफ०(ii)]

S.O. 3313.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Process Equipments, F-11 Block, Pimpri Industrial Area, Poona-18 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1972.

[No. S. 35018(26)/74-PF-III]

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1974

क्रा० आ० 3314—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् हरियाणा इंजीनियर्स एण्ड फैब्रिकेटर्स, 54-न्यू इण्डस्ट्रियल टाउनशिप, फरीदाबाद नामक स्थापन को 1 जून, 1974 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एम० 35019(146)/74-पी०एफ० 2(ii)]

New Delhi, the 28th October, 1974

S.O. 3314.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st day of June, 1974 the establishment known as Messrs Haryana Engineers and Fabricators 54, N.I.T. Faridabad for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(146)/74-PF. II(ii)]

क्रा० आ० 3215—यत्. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हरियाणा इंजीनियर्स एण्ड फैब्रिकेटर्स, 54-न्यू इण्डस्ट्रियल टाउनशिप, फरीदाबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के जून के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एम० 35019(146)/74-पी०एफ० 2(i)]

S.O. 3315.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Haryana Engineers and Fabricators 54, N.I.T. Faridabad have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1974.

[No. S. 35019 (146)/74 PF. II (ii)]

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1974

क्र० आ० 3316.—यह केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अशोक एस्टेट 'बी' होसाकोट, कुर्ग नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 की जून के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एम० 35019(163)/74-पी० एफ० 2]

New Delhi, the 3rd December, 1974

S.O. 3316.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ashoka Estate "B" Hosakote Coorg have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1973.

[No. S. 35019(163)/74-PF. II.]

क्र० आ० 3317.—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स टम्स, इम्प्लोयर्स एण्ड सर्विसेज, 20, नेताजी सुभाष राड, कलकत्ता-1 जिसमें इसकी निम्नलिखित शाखाएँ भी सम्मिलित हैं:—

(i) 37, उद्यान मार्ग, भुवनेश्वर-1 और

(ii) सह्याद्री सदन, तिलक राड, पूना-30।

नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 की जून के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एम० 35017(34)/74-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 3317.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Tests Inspection and Services, 20, Netaji Subhash Road, Calcutta-1, including its branches at (i) 37, Udyan Marg, Bhubaneswar-1 and (ii) Sahyadri Sadan, Tilak Road, Poona-30, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1973.

[No. S. 35017(34)/74-PF. II.(1)]

क्र० आ० 3318.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात्, 1 जून, 1973 से मैसर्स टेस्ट्स इन्स्पेक्शन एण्ड सर्विसेज, 20, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1 जिसमें (i) 37, उद्यान मार्ग, भुवनेश्वर-1 और (ii) सह्याद्री सदन, तिलक राड, पूना-30 स्थित उसकी शाखाएँ भी सम्मिलित हैं, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एम० 35017(34)/74-पी० एफ० 2 (ii)]

S.O. 3318.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Fund and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of June, 1973 the establishment known as Messrs Tests Inspection and Services, Netaji Subhash Road, Calcutta-1 including its branches at (i) 37, Udyan Marg, Bhubaneswar-1 and (ii) Sahyadri Sadan Tilak Road, Poona-30 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35017(34)/74-PF. II(1)]

क्र० आ० 3319.—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मुयण इन्वैस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, वासुदेवी मैन्शन, विनशा वाण्डा रोड, मुम्बई-20, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के जून के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एम० 35018(33)/74—आ०नि० 2 (i)]

S.O. 3319.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messis Suyash Investments Private Limited, Vaswani Mansion, Dinshaw Vachha Road, Bombay-20 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1973.

[No. S. 35018/33/74-PF. II(ii)]

क्रा० प्रा० 3320—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् 1 मार्च, 1974 से सैमर्स दि महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स, को-ऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड, सं० ए० 1773, डाकघर पसुमलाई, जिला मदुराई नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिरिष्ट करती है।

[सं० एम० 35018(33)/74-सा० नि० 2(ii)]

S.O. 3320.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st day of June, 1973 the establishment known as Messis Suyash Investments Private Limited, Vaswani Mansion, Dinshaw Vachha Road, Bombay-20, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018(33)/74 PF II(ii)]

क्रा० प्रा० 3321—अतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सैमर्स दि महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स, को-ऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड सं० ए० 1773 डाकघर पसुमलाई, जिला मदुराई नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के मार्च के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एम० 35019(73)/74-पी० एफ० 2(i)]

S.O. 3321.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. The Mahalakshmi Textile Mills Co-operative Stores Limited, No. A. 1773, Post Office Pasumalai, Distt. Madurai have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central

Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March 1974.

[No. S. 35019(73)/74-PF. II(i)]

क्रा० प्रा० 3322—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 मार्च, 1974 से सैमर्स दि महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स, को-ऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड, सं० ए० 1773, डाकघर पसुमलाई, जिला मदुराई नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिरिष्ट करती है।

[सं० एम० 35019(73)/74-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 3322.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of March, 1974 the establishment known as Messis The Mahalakshmi Textile Mills Co-operative Stores Limited, No. A. 1773, Post Office Pasumalai, District Madurai for the purposes of the said proviso

[No. S. 35019(73)/74-PF. II(ii)]

क्रा० प्रा० 3323—अतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सैमर्स सूनी कॉर्पोरेशन 52-ब्रिग बाजार स्ट्रीट, थिम्मंगलम, जिला मदुराई जिसमें 132, अलगरकोल रोड मदुराई (2) 1, वल्लल पाचप्पा स्ट्रीट कोचीपुरम दक्षिणी आरकाट जिला, स्थित इसकी शाखाएँ सम्मिलित हैं नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के सितम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एम० 35019(84)/73-पी० नि० II]

S.O. 3323.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Susee Corporation, 52, Big Bazar Street, Thiimangalam, District Modurai including its branches at 132, Alagal Koil Road Madurai (2) 1, Vellal Pachappa Street, Kancheepuram, South Arcot District have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1972.

[No. S. 35019/84/73-PF. II]

का० प्रा० 3324—यत् केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि मिसर्स मोदी ब्रदर्स, 8571, राष्ट्रपति रोड, सिकन्दराबाद-3 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के दिसम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एम० 35019(85)/73-पी० एफ० 2]

S.O. 3324.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Modi Brothers, 8571, Rashtrapati Road, Secunderabad-3 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1972.

[No. S. 35019/85/73-PF. II]

का० प्रा० 3325—यत् केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मिसर्स जूबिली बिस्कुट कम्पनी, प्रो० टी० सेक्शन उल्हासनगर-4 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गयी है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 की दिसम्बर के 31वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एम० 35018(38)/74-पी० एफ० 2]

S.O. 3325.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jubilee Biscuit Company, O.T. Section, Ulhasnagar-4 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1973.

[No. S. 35018(38)/74-PF-II]

का० प्रा० 3326—यत् केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मिसर्स एसोसिएशन आफ सिन्थेटिक फाइबर इन्डस्ट्रीज राजमहल प्रथम तल 84 वीर नरिमान रोड मुम्बई-20 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 की मार्च के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एम० 35018(36)/74-पी० एफ० II]

S.O. 3326.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Association of Synthetic Fibre Industries, Raj Mahal, 1st Floor, 84 Veer Nariman Road, Bombay-20 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of March, 1973.

[No. S-35018(36)/74-PF. II]

का० प्रा० 3327—यत् केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मिसर्स राजवर्धन ट्रेडिंग कम्पनी अमृतसर जिसमें पुरानी कोतवाली चौड़ा बाजार लुधियाना स्थित उनकी शाखा भी सम्मिलित है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एम० 35019(140)/74-पी० एफ० II(i)]

S.O. 3327.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Rajvardhan Trading Company, Amritsar including its branch at Purani Kotwali, Chaura Bazar, Ludhiana have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1974.

[No. S. 35019 (140)/74 PF. II(i)]

का० प्रा० 3328.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार सम्बद्ध विषय में आवश्यक आंच करने के पश्चात् मैसर्स राजवर्धन ट्रेडिंग कम्पनी भूमनसर जिसमें पुरानी कोतवाली चौड़ा बाजार लुधियाना स्थित उसकी शाखा भी सम्मिलित है नामक स्थापन को 1 अप्रैल 1974 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35019(140)/74-पी० एफ० II (ii)]

S.O. 3328.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st day of April, 1974, the establishment known as Messrs. Kajvaidhan Trading Company, Amritsar including its branch at Puarni Kotwali, Chaura Bazar, Ludhiana, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(140)/74-PF. II(ii)]

का० प्रा० 3329.—यत् केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बंगलौर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कॉर्पोरेशन 67-बी० इंडस्ट्रियल एरिया यशवन्तपुर बंगलौर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 की अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस० 35019(160)/74-पी० एफ० II]

S.O. 3329.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Bangalore Industrial Products Corporation, 67-B, Industrial Area, Yeshwantpur, Bangalore have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1974.

[No. S. 35019(160)/74 PF. II]

का० प्रा० 3330.—यत् केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुखर इंडस्ट्रीज गोपाल टाकीज के पीछे यशवन्तपुर बंगलौर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 110 GI/74—8

1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 की मई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस० 35019(164)/73-पी० एफ० 2]

प्रा० पी० नरुला, अवर सचिव

S.O. 3330.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Sunder Industries, Behind Gopal Talkies, Yeshwantpur, Bangalore have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1974.

[No. S. 35019(164)/74-PF. II]

R. P. NARULA, Under Secy.

प्रादेश

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1974

का० प्रा० 3331.—यत् केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाखण्ड अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में ब्रिटिश इण्डिया जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी से संबद्ध नियोजक और उनके कर्मचारियों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यत् केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णय के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1974 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णय के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या ब्रिटिश इण्डिया जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी की, लखनऊ शाखा में अनुभागीय प्रधान का पद सूजित न करने और अनुभागीय प्रधान के रूप में श्री के० कुमार की प्रोत्सति न करने के कार्यवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुलोप का हकदार है?

[फाइल सं० एस० 17012/1/74-एन आर I]

ORDER

New Delhi, the 21st November, 1974

S.O. 3331.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the British India General Insurance Company,

and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the British India General Insurance Company in not creating a post of Sectional Head in Lucknow Branch and not promoting Shri K. Kumar as Sectional Head is justified? If not to what relief is the workman entitled?

[File No. I. 17012/1/74-LR-I]

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1974

का० प्रा० 3332.—जान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना का० प्रा० संख्या 1899 दिनांक 22 अप्रैल 1971 को रद्द करती है।

[संख्या ए० 35017/1/74-एम-I]

एस० एस० सहस्रानामन, अवर सचिव

New Delhi, the 27th November, 1974

S.O. 3332.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) S.O. No. 1899 dated the 22nd April, 1971.

[No. A-35017/1/74-MI]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

का० प्रा० 3333.—यतः गुजरात राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खंड (घ) के अनुसरण श्री जी० एन० डी के०, सचिव, गुजरात सरकार, पंचायत तथा स्वास्थ्य विभाग को श्री आर० बी० शुक्ला के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिये नामनिर्दिष्ट किया है;

अतः, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 2763, तारीख 27 मई, 1971 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में "(राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे अब 10 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्—

"श्री जी० एन० डी के०,

सचिव, गुजरात सरकार,

पंचायत तथा स्वास्थ्य विभाग,

गांधी नगर।

[का० सं० यू० 16012(13)/74-एच० आई०]

S.O. 3333.—Whereas the State Government of Gujarat has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated Shri G. N. Dike, Secretary to the Government of Gujarat, Panchayat and Health Department, to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in the place of Shri R.B. Shukla;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) S.O. No. 2763, dated the 27th May, 1971, namely:—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Governments under clause (d) of section 4) for the entry against item 10, the following entry shall be substituted, namely:—

"Shri G. N. Dike, Secretary to the Government of Gujarat, Panchayat and Health Department, Gandhinagar."

[F. No. U-16012(13)/74-HI]

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1974

का० प्रा० 3334.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 22 दिसम्बर, 1974 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) के उपबन्ध के तहत राज्य के विविध जिलों के कोट्टाराकारा तालुक में कुलक्काडा राजस्व गांव के अन्तर आने वाले क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे।

[एस-38013/10/74-एच० आई०]

टी० एस० कृष्णामूर्ति, अवर सचिव

New Delhi, the 5th December, 1974

S.O. 3334.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 22nd day of December, 1974 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section 1) of section 76 and sections 77, 78, 79, and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the areas within the revenue village of Kulakkada in Kottarakkara Taluk in Quilon District in the State of Kerala.

[F. No. S-38013/10/74-HI]

T. S. KRISHNAMURTHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1974

क्रा० प्रा० 3335.—अन्नक खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1948 के नियम 3 के साथ पठित, अन्नक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 (1946 का 22) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० 3108 तारीख 4 मिनम्बर, 1970 को अधिकांश करने हुये, केन्द्रीय सरकार बिहार राज्य के लिये सहायक समिति का पुनर्गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

1. श्रम मंत्री
बिहार राज्य, पटना अध्यक्ष
2. अन्नक खान कल्याण, आयुक्त बिहार उपाध्यक्ष
3. प्रादेशिक श्रमायुक्त (सी०)
बिहार, धनबाद सदस्य
4. श्री राजेन्द्र नाथ दान,
सदस्य, विधान सभा, बिहार, पटना सदस्य
5. श्री एम० पी० मदानि
इंडियन माइन्स माइनर्स एंड मीलर्स एसोसियेशन, स्वामियों का प्रति-
पी० झुमरी तलैया, हजारीबाग निधित्व करने वाले
सदस्य
6. श्री बी० सामन्ती,
काननगोबीषा, पी० कोदरमा, हजारीबाग
7. श्री एस एन सहाय
महामन्त्रि, मेटलर्जिस्ट्स माइनर्स एसोसियेशन कर्मकारों का प्रति-
पी० कोदरमा, जिला हजारीबाग निधित्व करने वाले
सदस्य
8. श्री आर० पी० शर्मा,
संयुक्त सचिव मेटलर्जिस्ट्स माइनर्स,
बर्म एसोसियेशन, पी० कोदरमा,
जिला हजारीबाग
9. श्रीमती शान्ति सुख चन्द्र,
शान्ति निवास, पी० हजारीबाग, जिला हजारीबाग महिला सदस्य
10. कल्याण उपायुक्त,
अन्नक खान श्रम कल्याण संगठन, कर्मा,
पी० झुमरी तलैया, जिला हजारीबाग, बिहार

[यू० 18012/1/73-एम० III]

बी० के० सकीता, अवर सचिव,

New Delhi, the 26th November, 1974

S. O 3335.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 (22 of 1946) read with rule 3 of the Mica Mines Labour Welfare Fund rules, 1948 and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. 3108 dated the 4th September, 1970

the Central Government hereby reconstitutes the Advisory Committee for the State of Bihar with the following members, namely:—

1. Labour Minister State of Bihar, Patna .. Chairman
2. Mica Mines Welfare Commissioner, Bihar .. Vice Chairman
3. Regional Labour Commissioner (C) Bihar, Dhanbad .. Member
4. Shri Rajender Nath Dawn, Member, Legislative Assembly, Bihar, Patna .. Member
5. Shri S. P. Bhadani Indian Mica Miners and Dealers Association P. O. Jhumeritailaya, Hazaribagh. { Members repre-
.. } senting the Mica
6. Shri B. Samanto, Kan- } Mine Owners of
angobigha, P.O. Koda- } of Bihar
rma, Hazaribagh ..
7. Shri S. N. Sahay, General Secretary, Metalliferous Mine Workers Association, At and P.O. Kodarma, District Hazaribagh ..
8. Shri R. P. Sharma, Joint Secretary, Metalliferous Mine Workers Association, At and P.O. Kodarma, District Hazaribagh. { Members repre-
.. } senting the
9. Srimati Shanti Sukh Chandra, Shanti Niwas P. O. Hazaribagh, Distt. Hazaribagh .. Women Member
10. Deputy Welfare Commissioner, Mica Mines Labour Welfare Organisation, Karma. P. O. Jhumeritailaya District Hazaribagh, Bihar .. Secretary

[U-18012/1/73 M-III]

B.K. Saksena, Under Secy.

प्रावेश

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1974

क्रा० प्रा० 3336.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायय अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैगस भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, डाकघर पाथरहट्टि, जिला धनबाद को भूलनबाराही कोलियरी के प्रबन्धनपत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7—क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (संख्या 1), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैंमें भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, झारखर पाथरडिह, जिला हजारीबाग की भुलनबारारी कोलियरी के प्रबन्धनन्त्र की, श्री साजुद खान, स्टोइंग इचार्ज को रू० 180-273 रू० का वेतन मान, जो कि उसी प्रबन्धनन्त्र के अधीन जीतगोरा में अन्य स्टोइंग इचार्ज के वेतनमान से बहुत कम है, देने की कार्यवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुपाय और किस तारीख से हकदार है ?

[संख्या एल०-2012/62/74-एल० आर० 2]

ORDER

New Delhi, the 26th October, 1974

S.O. 3336.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bhulanbararee Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Patherdih, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management of Bhulanbararee Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Patherdih, District Dhanbad, are justified in giving the pay scale of Rs 180—273 to Shri Sajud Khan, Stowing Incharge which is much less than other Stowing Incharge in Jealgora under the same management ? If not to what relief the concerned workman is entitled and from what date ?

[No. L-2012/62/74-LRII]

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1974

का० आ० 3337 —यह केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाखंड अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सेना कोलियरी, वेस्ट बोकारो टा आफ कोलियरी, झारखर कजू, जिला हजारीबाग के प्रबन्धनन्त्र में संबद्ध निराश्रित और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यह केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्वेशित करना बांछनीय समझती है ,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, (संख्या 2), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या अभिरक्षक, वेस्ट बोकारो टा आफ कोलियरीज झारखर कजू, जिला हजारीबाग का सेना कोलियरी में नियोजित श्री नोनी गोपाल सरकार, रोकड़िया को 7 मार्च, 1973 से सेवा से हटाना न्यायोचित था ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुपाय का हकदार है ?

[सं० एल-2012/134/73-एल० आर०-2]

ORDER

New Delhi, the 7th November, 1974

S.O. 3337.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Semra Colliery, West Bokaro Group of Collieries, Post Office Kaju, District Hazaribagh and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the Custodian, West Bokaro Group of Collieries, Post Office Kaju, District Hazaribagh was justified in removing from service Shri Nani Gopal Sarkar, Cashier, employed at Semra Colliery from the 7th March, 1973? If not, to what relief is the workman entitled?

[No. L-2012/134/73-LRII]

New Delhi, the 5th December, 1974.

S.O. 3338.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jamadoba Coal Washing Plant of Messrs Tata Iron and Steel Company, Limited, Post Office Jealgora, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 27th November, 1974.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
(NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT:

Shri K. K. Sarkar, Judge,
Presiding Officer.

Reference No. 1 of 1973.

In the matter of an industrial dispute under Section 10 (1)(d) of the industrial Disputes Act, 1947.

PARTIES:

Employers in relation to the management of Jamadoba Coal Washing Plant of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post Office, Jealgora, District Dhanbad.

AND

Their workmen.

APPEARANCES:

On behalf of the employers : Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

On behalf of the workmen : Shri Ram Mitra, Secretary, Bihar Koyla Mazdoor Sabha.

State : Bihar.

Industry : Coal.

Dhanbad, 21st November, 1974.

30th KARTIKA, 1896 Saka.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation in the Department of Labour & Employment, being of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Jamadoba Coal Washing Plant of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post office, Jealgora District Dhanbad and their workmen, by order No. L/2012/142/72-Lk.II dated 4th January, 1973 referred the same to this Tribunal u/s 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication upon the issue as mentioned in the schedule below.

SCHEDULE

"Whether the demand of the Bihar Koyla Mazdoor Sabha that Sarvashri Ananda Nandi, Jamaluddin and Biswanath Prasad, Operators are entitled to be placed in the scale of Rs. 205-7-247-10-337 in Grade-D as per the recommendations of the Coal Wage Board is justified? If so, to what relief are the concerned workmen entitled and from what date?"

For the sake of convenience I need not set out the facts of the case in detail in the beginning. I will take up material facts as and when necessary in course of my award.

Management's preliminary legal objection.—The Coal washing Plant at Jamadoba is registered under the Factories Act and it is under the charge of a manager. The washery is not attached to any particular mine and as such the present Reference by the Central Government being incompetent is not maintainable.

Now, admittedly the Coal Washing Plant is not a mine proper according to the definition of a mine in the Mines Act as work in the washing plant is done on the surface as opposed to the work of a mine proper done underground. A mine proper is exempt from registration under the Factories Act. The Coal Washing Plant being not a mine proper cannot claim such exemption. Accordingly, the washing plant may be registered under the Factories Act for various reasons, viz. Safety and welfare of the workmen, etc. So, simply because it is registered under the Factories Act a coal washing plant cannot be totally outclassed from what is known as a mine. According to S.2(j) sub-section (vii) mine includes all workshops situated within the precincts of a mine and under the same management and used solely for purposes connected with that mine or a number of mines under the same management. So, a workshop which is not a mine proper is also included within the definition of mine subject to certain condition being fulfilled. In broad term the coal washing plant can be said to be a workshop. Is it situated within the same precincts of a mine and under the same management and is it solely used for purposes connected with Jamadoba colliery or a number of mines under the same management? There is no definition of precinct in the Mines Act and we may refer to a similar Act viz. Factories Act where precinct has been defined as that which is within one boundary wall with the coal mine. We have it from Shri Anand Nandi, WW.I that the Jamadoba colliery and the Jamadoba coal washing plant are surrounded by one and the same boundary wall. The coal of the Jamadoba colliery comes to the washing plant through the help of conveyors. The coal from underground is raised by tubs and emptied on the conveyors which carry it through to the washing plant. We have it from Shri I. Mahmood, Manager of the washing plant (MW.I) that the distance between the two is about 200 feet. From the above evidence it is apparent that the washing plant, and the colliery are almost side by side so much so that coal from the colliery is carried to the washing plant through conveyors, which could not have been the case if the distance between the two was a sizeable one. It can therefore very well be said that the washing plant and the coal mine are within the same precinct. Admittedly, the Tatas have six collieries and coal raised in these collieries are all sent to the Jamadoba Coal Washing plant for washing. There is no evidence that the washing plant does the work of any other mine and so it can very well be said that the washing plant is used solely for the purposes connected with Jamadoba coal mine and other collieries of the Tatas. It is also admitted that washing plant and all the collieries belong to and are under the management of the Tatas. Thus, it is seen that the Jamadoba coal washing plant fulfills all the conditions laid down in the Mines Act to get itself included within the definition of what is a mine under the Mines Act. I may now

look to other facts and circumstances. The Central Wage Board for Coal Mining Industry dealt with categorisation, wage structure, etc. of workmen in the collieries. According to the Coal Wage Board their recommendations in respect of categorisation, wage structure, etc. would apply to ancillary establishments like washing plant, etc. This is also indicative of the fact that a washing plant though not a mine proper is considered as a mine for all practical purpose. We have it from WW.I that the workmen of the coal washing plant get their treatment and medicine from the dispensary attached to Jamadoba colliery. It is pleaded by the workmen and admitted by the management in their rejoinder that the colliery standing orders are applicable to the employees of the washing plant, the Mazumdar Award, Das Gupta Award and the Wage Board recommendations have been extended to the employees of the Coal Washing Plant. Also the employees of the coal washing plant have been made members of Coal Mines Provident Fund and Coal Mines Bonus Scheme have been extended to them. The Chief Mining Engineer is the overall incharge of the collieries as also the washing plant. I need not multiply instances of similarity as between the two. It appears that the treatment meted out to the coal washing plant is at par with the collieries owned by the Tatas. In short, the coal washing plant is not technically a mine but it comes within the definition of what is included in mine as per S.2 of the Mines Act. Moreover, it is considered as a mine for all practical purposes. Registration of the washing plant under the Factories Act may be because of its main nomenclature as a workshop but then such registration does not prevent it from being included in the definition of mine also as I have already discussed. It has not been shown before me that at any time the coal washing plant has been treated as what may be called a 'State subject'. In view of the evidence on record and other facts and circumstances I am to hold that the Central Government is the competent authority to make the Reference in respect of Jamadoba Coal Washing Plant.

Admittedly, the concerned workmen were originally appointed as mazdoors in the washing plant in category I. Admittedly, they were promoted and placed in category IV of Mazumdar Award w.e.f. 1-5-1964 in the Dust Suppression unit. The workmen claim that the three concerned workmen were promoted and appointed as operators in the Dust Suppression Unit w.e.f. 1-5-64 and accordingly they should be placed in Grade-D of the Wage Board recommendation which is Rs. 205 to Rs. 337 at par with other operators working in the coal washing plant. The management denies that the three concerned workmen were promoted and appointed as operators as such. But they were appointed as pump Khalasies. Ext. W. 1 is a copy of the appointment letter by which the three concerned workmen were appointed as operators (category IV) to look after the maintenance and operation of the dust suppression equipment w.e.f. 1-5-64 and they were paid Rs. 1.25 Np per day as basic wages in the grade Rs. 1.25-0.09-1.79 i.e. category IV. The above appointment letter is ambiguous. It cuts both ways i.e. it may mean that they were operators and it may also mean that they were not operators. Admittedly, the operators in the coal washing plant were in category VII of the Mazumdar Award on a monthly grade of Rs. 46-120. Prima facie when the three concerned workmen were not in category VII of the Mazumdar Award and not on the monthly grade of Rs. 46-120, in which the other operators in the washing plant are, the three concerned workmen can not be said to be operators proper. Prima facie the three concerned workmen can be said to be operators proper being appointed as operator to look after the maintenance and operation of the dust suppression equipment. In view of the above ambiguity in the appointment letter it is not helpful to use for the purpose of determining whether they are operators or not. What we are required to see is what job is performed by the three concerned workmen and it is the nature of job performed by them that will go a long way to determine their status. It is stated in the written statement by the employers that the three concerned workmen have only to start and stop the pumps on which they work viz. (i) 25 H.P (ii) 5 H.P and (iii) 0.125 H.P pump. These pumps are connected to a number of sprays. When they start the pumps nozzles spray the water to suppress the dust. Further it is pleaded by the management that as the workmen are to operate and stop the pumps which are below 35 H.P. they were entitled to be put in category II (new) but they were placed in category III (new) as they are working on more than one pump and they are to stop and start hand operated valves for water spraying. In their

written statement the workmen do not appear to have denied the job description of the three concerned workmen as set out in the employer's written statement. The workmen's written statement is—the dust suppression equipment consist of water pumps and, water tanks-liquid pumps and liquid tanks, solution pumps and solution tanks, about 500 spray nozzles and valves. The job description of operators proper in higher grade have been detailed by the employers in their annexure to their written statement, which is . . . the operators are given charge of sections consisting of a number of machines such as conveyors, crushers, screen coal treatment baths, etc. They are responsible for process control and operation of their respective sections. The operators have to be thoroughly conversant with the working of all equipments under their charge and they are to carry out the maintenance of all the equipments independently. The operators are also responsible for the cleaning and house keeping of their respective sections and for the maintenance of records, inspection sheets, etc. The workmen do not appear to have controverted in their written statement the duties of the operators as given by the management. Both WW. 1 and WW. 2, Shri Biswanath Prasad in their evidence also do not controvert the job description of operators in higher grade as given out by the management. From the evidence on record and other materials it appears that the machines which the three concerned workmen work upon fall far short of the machines the operators work upon. Naturally, therefore, the skill required to be exercised by the three concerned workmen falls far short of the skill required to be exercised by the operators in higher grade by nature of the machines they have to deal with. It is also apparent that the work performed by the three concerned workmen falls far short of the work performed by the operators in degree, in nature and in what not. Then according to the management the three concerned workmen who are said to be pump khalasis are not required to maintain the machines they work upon like the operators. The mention of maintenance of machines in the appointment letter is said to be a mistake and it is in the evidence of the management and in their pleadings that there are greasers who clean and oil the machines worked upon by the three concerned workmen. I do not find any specific denial of this by the workmen either in their written statement or in their evidence. Accordingly it may not be wrong for me to take it for granted that the three concerned workmen are not required to maintain the machines in actuality. So the maintenance of the machines which forms part of the duties of operators does not form part of the job of the three concerned workmen. The workmen compare the three concerned workmen with the operators in higher grade and on this comparison they claim to be categorised and 'wagised' (the term is mine) in the same way as the operators in higher grade. The following facts will speak for themselves as to how far the three concerned workmen compare with the operators. Admitted, before the Coal Wage Board the operators were category VII of the Mazumdar Award whereas the three concerned workmen were in category IV of the same award, definitely the operators being in higher category than the three concerned workmen. Then the operators were monthly rated whereas the three concerned workmen were daily rated, definitely the operators were in a different mode of payment than the three concerned workmen. Then, the operators were on a grade Rs. 45—120 whereas the three concerned workmen were on basic wages at Rs. 1.25 per day in the grade Rs. 1.25—0.09—1.79, definitely the operators were in receipt of higher pay in a higher grade than the three concerned workmen. It therefore follows that on comparison test the case of the three concerned workmen does not compare favourably with the operators in pre-wage board period. By now it is not difficult to understand the intention of the word 'operator' used in the letter of appointment of the three concerned workmen (Ext. W. 1) and it appears that the word 'operator' in the case of the three workmen was used in their appointment letter in the sense that one who operates anything is an operator. This meaning is strengthened by the fact that in their appointment letter the three workmen were placed in category IV which is not the category for the operators and also by the fact that the daily wages of the three workmen were fixed at Rs. 1.25 which is not the pay of the operator. In other words, the term operation of dust suppression unit as used in their appointment letter is just a casual one without meaning what is actually meant by the term 'operators'. For reasons as stated above the three workmen cannot justifiably claim to be equated with operators proper in higher grade just for the sake of it.

The service sheets of the three workmen (Ext. M2, M3 & M4) present an interesting reading. They were employed on 21-10-1963 as mazdoor in the lowest category I. They were promoted on 1-5-1964 as pump khalasi in Category IV. They were placed on 15-8-1967 i.e. after adoption of the wage board recommendation in category III in the scale of Rs. 5.90-0.15-7.40. The year 1967 passed, the year 1968 passed, the year 1969 passed, the year 1970 passed and the year 1971 passed since the three workmen were put as pump khalasi in category III (new). It appears the three concerned workmen watched calmly and silently the passing away of the years 1967, 1968, 1969, 1970 and 1971. It does not appear that in course of these years they ever raised their little finger in protest against the action of the management in placing them in category III (new) and in their not being fixed in grade-D of the wage board recommendation i.e. Rs. 205—337 in which the other operators were fitted on and from 15-8-1967. The reticence thus exercised by the three concerned workmen over the years bring into bold relief the inference that they never protested against the action of the management as they had better known that they were not operators and cannot be categorised and 'wagised' (the term is mine) like the full-fledged operators. Their silence has not been golden to them. Then it appears that the wage board recommended that the categorisation proposed and the wage scales recommended by them should be made applicable to all employees in ancillary undertakings like the coal washing plant and the fitment of such employees into the new scales of pay recommended by them should be effected at unit level in consultation with the workmen or their representative. It is the case of the management that in pursuance of the above a Joint Implementation Committee of the management and the representatives of the Colliery Mazdoor Sangh which is the representative and recognised union of the six collieries and ancillary departments of the Tatas was formed to implement the wage board recommendations. Then a final decision of the Joint Implementation Committee was arrived at regarding the grade and categories of the employees in the coal washing plant and the concerned workmen who had been placed in category No. III were allowed to remain in the same category as per the decision of the Joint Implementation Committee as there was no change in the duties of the concerned workmen to warrant revision in their categorisation or in their wages. It does not appear that this specific allegation of the management has been denied by the workmen either generally or specifically in their written statement. The management's witness in his evidence has also spoken about the Joint Implementation Committee in respect of the above, and it is further in his cross-examination that there were no anomalies in respect of the concerned workmen to be removed by the said committee. Accordingly, the gradation and the categorisation of the three concerned workmen can very well be said to be a closed chapter. Attempts now by some workmen to reopen the issue cannot be better than an exercise in futility. Taking a stock of the evidence on record and other facts and circumstances of the case I am to hold that the case for the three concerned workmen to be placed in the scale of Rs. 205—337 has not been made out.

In the result, the demand of the Bihar Koyala Mazdoor Sabha that S/Shri Anand Nandi, Jamaluddin and Bishwanath

Prasad, operators as mentioned in the order of reference, are entitled to be placed in the scale of Rs. 205—7—247—10—337 in grade—D as per the recommendation of the Coal Wage Board is found not justified. Accordingly they are entitled to no relief.

This is my award.

K. K. SARKAR, Presiding Officer

[No. I-2012/142/72-I RH.]

LALFAK ZUALA, Deputy Secy.

हिमाचल प्रदेश राज्यो के लिए अपर अभिरक्षण, निष्क्रान्त सम्पत्ति, के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या एक० ए० 36016(1)/प्रशासन सेल/73]

डी० एन० असोजा, अवसर सचिव।

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 16th November, 1974

प्रति श्रीर पुनर्वासि मंत्रालय

(पुनर्वासि विभाग)

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1974

का० प्रा० 3339.—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम 1950 (1950 का 31) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पुनर्वासि विभाग से सहायक बन्दीबन्धन आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे श्री एच० जे० लाल गोस्वामी, को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत या इसके द्वारा अपर अभिरक्षण निष्क्रान्त सम्पत्ति को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए दिल्ली के मंच शासित क्षेत्र तथा गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा तथा

S.O. 3339.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoints Shri H. J. Lal Goswami, Asstt. Settlement Commissioner in the Department of Rehabilitation as the Additional Custodian of Evacuee Property for the Union Territory of Delhi and the States of Gujarat, Andhra Pradesh, Maharashtra, Punjab, Haryana and Himachal Pradesh for purpose of discharging the duties imposed on the Custodian by or under the said Act.

[F. No. A-36016(1)/Admn. Cell/73]

D. N. ASIJA. Under Secy.

